ಶುಭ್ ಲಾಭ್
खबरें जो सोच बदल दे
शुभ लाभ
DAILY
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

कर्नाटक कांग्रेस में बॉस बदलने की मांग को लेकर फिर से खींचतान @ नम्मा बेंगलूरु

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 | मंगलवार, 02 जुलाई, 2024 | हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित | epaper.shubhlabhdaily.com | संपादक : गोपाल अग्रवाल | पृष्ठ : 14 |✲| मूल्य-6 रु.| वर्ष-6 | अंक-183

बीच सड़क शरीयत के नाम पर हुआ बर्बर और बेशर्म कारनामा

महिला को घसीट घसीट कर पीटा, बेहोश हो गई तो लात मारी

अशोभनीय और अमानवीय घटना पर चुप बैठी हैं पूरी संसद

पश्चिम बंगाल में अघोषित तौर पर लागू है इस्लामिक कानून !

संविधान-रक्षक ममता चुप, राहुल चुप, खड़गे चुप, अखिलेश चुप

उत्तर दिनाजपुर, 01 जुलाई (एजेंसियां)। ममता बनर्जी के मुस्लिमवाद से पश्चिम बंगाल में इस्लामिक कानून लागू हो गया है। सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के नेता और कुख्यात अपराधी शाहजहां शेख और उसके गुर्गों द्वारा संदेशखाली में बड़ी तादाद में महिलाओं का उत्पीड़न हाल ही सुर्खियों में रहा है। अब उत्तर दिनाजपुर में खुलेआम एक महिला को सड़क पर घसीट घसीट कर पीटे जाने की बर्बर घटना सामने आई है। महिला के साथ एक युवक को भी बीच सड़क पर भीड़ के बीच डंडों और लात घूंसे से मारा जा रहा है। महिला को तब तक मारा गया जब तक वह बेहोश न हो गई। बेहोश होने पर भी उसे सड़क पर घसीटा गया। आप आश्चर्य करेंगे कि यह आपराधिक कृत्य करने वाला व्यक्ति इस्लामिक शरीयत कानून के

तहत महिला और युवक को सजा दे रहा है और पब्लिक तमाशा देख रही है। वहशी की तरह महिला और युवक को पीटने वाले व्यक्ति का नाम ताजेमुल उर्फ जेसीबी है। वह स्थानीय टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का खास चमचा है। एक महिला के साथ हुई इस दर्दनाक घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुप हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं... का डायलॉग मारने वाली प्रियंका गांधी चुप हैं। मोहब्बत की दुकान के बाद अब संविधान की रक्षा की दुकान चलाने लगे राहुल गांधी चुप हैं। राहुल के पिछलग्गू अखिलेश यादव चुप हैं। इंडी के सारे भिंडी चुप हैं।

बंगाल पुलिस का कहना है कि महिला को पीटने वाले ताजेमुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन थाने में घुसते ताजेमुल को देखें तो आपको पुलिस और ताजेमुल की औकात का फर्क साफ-साफ दिखेगा। पुलिस उस महिला पर ज्यादा नाराज है, जिस महिला ने इस घटना का वीडियो वायरल किया। उस महिला का नाम रश्मि सामंत है। वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्ष हैं। रश्मि सामंत के वीडियो को ही भारतीय जनता पार्टी के नेता और आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने उठाया और उसे शासन और प्रशासन के स्तर पर प्रसारित किया।

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में हुई यह घटना एक महिला के साथ महज मारपीट का मसला नहीं है। यह भारतीय संविधान को क्षत-विक्षत करने का मामला है। यह घटना संसद को दी गई सीधी चुनौती है। देश में विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान का शासन चलेगा या अब यहां बर्बर इस्लामिक आचार-विचार चलेंगे? देश के नागरिक यह सवाल पूछ रहे हैं। घटना की वीडियो का लिंक हम यहां दे रहे हैं। अगर पश्चिम बंगाल पुलिस के दबाव में वह लिंक अब तक न हटा हो तो आप राज्य की शर्मनाक स्थिति अपनी आंखों से देख सकते हैं... https://x.com/amitmalviya/status/1807341290520289486

▶10 पर

लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान

जो खुद को हिंदू कहते हैं वही हिंसा करते हैं

नई दिल्ली, 01 जुलाई (एजेंसियां)। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं, वही हिंसा करते हैं। राहुल गांधी के इस बयान पर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल के भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। यह आपत्तिजनक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी होगी।

राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वह 24 घंटे हिंसा हिंसा करते रहते हैं। ये हिंदू हैं ही नहीं। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि अहिंसा फैलाना चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान बीच में ही उठकर राहुल गांधी को रोका और कहा कि यह बात बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहना गंभीर विषय है। इस पर राहुल ने जवाब दिया कि मैंने भाजपा को हिंसक कहा, नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है। भाजपा पूरा हिंदू समाज नहीं है। आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है।

हिंदू समुदाय को हिंसक कहना आपत्तिजनक: मोदी

राहुल गांधी को हिंदुओं से माफी मांगनी होगी: शाह

राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए अमित शाह ने कहा, शोरशराबा कर के इतने ▶10 पर

अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ऐसा बयान देता है : योगी

लखनऊ, 01 जुलाई (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं को लेकर दिये गये आपत्तिजनक बयान की कड़ी निंदा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने निंदनीय बयान से भारत माता की आत्मा को लहुलुहान किया है, इसके लिए उन्हें दुनियाभर में फैले करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए।

सीएम योगी ने कहा, हम यह समझते थे नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी परिपक्व होंगे, मगर खेद है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार का बयान देगा। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक या सम्प्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। ▶10 पर

अयोध्या में मुआवजे को लेकर राहुल ने संसद में झूठ बोला

अयोध्या में बंटा 1733 करोड़ का मुआवजा

योगी आदित्यनाथ ने राहुल को ललकारा, रख दिया ब्यौरा

राहुल का झूठा बयान अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक: योगी

लखनऊ, 01 जुलाई (एजेंसियां)। संसद में अयोध्या में विस्थापितों को दिए गए मुआवजे को लेकर राहुल गांधी द्वारा संसद में की गई गलत बयानी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल का बयान यूपी और अयोध्या को बदनाम करने के लिए दिया गया है। सदन में दिया गया राहुल का झूठा बयान अत्यंत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में विभिन्न विकास कार्यों के दौरान विस्थापित हुए लोगों को 1733 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर प्रदान की गई है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मुआवजे का पूरा ब्यौरा सामने रख कर राहुल गांधी के आदतन झूठ बोलने के ▶10 पर

अयोध्या में कितना और किसे दिया गया मुआवजा

- अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 952.39 करोड़ का मुआवजा
- अयोध्या बाईपास (रिंग रोड) के लिए 295 करोड़ का मुआवजा
- राम जन्मभूमि पथ में 14.12 करोड़ रुपए का मुआवजा
- भक्ति पथ के लिए 23.66 करोड़ का मुआवजा
- रामपथ के लिए 114.69 करोड़ का मुआवजा
- पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 29 करोड़ का मुआवजा
- चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 119.20 करोड़ का मुआवजा
- रेलवे दोहरीकरण के निर्माण के लिए 35.03 लाख का मुआवजा
- एनएच 330ए के निर्माण के लिए 163.90 करोड़ का मुआवजा
- एनएच 227बी के पैकेज 3 के तहत 21.09 करोड़ का मुआवजा
- अबतक कुल 21,548 व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है
- मुआवजे के साथ-साथ दुकानों का सौंदर्यीकरण भी कराया गया
- अयोध्या में 21,548 व्यक्तियों को दिया गया मुआवजा
- राम जन्मभूमि के विस्थापितों को 14.12 करोड़ मुआवजा

झारखंड के सीमाई इलाकों में बढ़े बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट

छानबीन करेगा भारतीय चुनाव आयोग

रांची, 01 जुलाई (एजेंसियां)। झारखंड के पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाकों में बेतहाशा वोट वृद्धि की शिकायत मिली है। यह सामने आया है कि एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या में 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है, जो असामान्य है। इसको लेकर राज्य चुनाव आयोग अब जांच करवाने जा रहा है। इन बूथ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम जुड़ने का शक है। चुनाव आयोग जल्द ही एक टीम साहेबगंज जिले की राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भेजने जा रहा है। यह टीम यहां वोटों की संख्या में वृद्धि की जांच करेगी। राजमहल विधानसभा का बड़ा इलाका पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। यहां एक बूथ पर तो वोट 2019 के मुकाबले दोगुने हो गए हैं। राजमहल प्रखंड बूथ पर 117 प्रतिशत की वृद्धि देखने को मिली है। 2019 में इस बूथ पर मतदाताओं की संख्या 689 थी जो 2024 में बढ़ कर 1400 के पार पहुँच गई है। ▶10 पर

भारत में सजा के बजाय न्याय देने वाला कानून लागू

पुराना कानून विदा, नया कानून आया

नई दिल्ली, 01 जुलाई (एजेंसियां)। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीन नए आपराधिक कानून आज से देश में लागू हो गए। भारतीय न्याय संहिता ने अब आईपीसी (इंडियन पीनल कोड) की जगह ले ली है। सीआरपीसी (क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड) अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जानी जाएगी। आईईसी (इंडियन एविडेंस एक्ट-1872) अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के नाम से

आईपीसी, सीआरपीसी, आईईसी का भारतीयकरण हुआ

व्यवहारिक कठिनाइयों पर पुलिस ने उठाए कई सवाल

जाना जाएगा। भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 रह गई हैं। संशोधन के जरिए इसमें 20 नए अपराध शामिल किए गए हैं, तो 33 अपराधों में सजा अवधि बढ़ाई गई है। 83 अपराधों में जुर्माने की रकम भी बढ़ाई गई है। 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान है। छह अपराधों में सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है।भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 12 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में तीन संशोधित आपराधिक विधियकों के रूप में पेश किया था।

▶10 पर

भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला मामला दर्ज

नई दिल्ली, 01 जुलाई (एजेंसियां)। देशभर में आज से लागू हो चुके नए कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दिल्ली के कमला मार्केट थाना इलाके में दर्ज हुआ है। जिसमें खुद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज मामले के मुताबिक, उप निरीक्षक कार्तिक मीणा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक इलाके में गश्त कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे। यहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बिड़ी और सिगरेट बेच रहा था। ▶10 पर

शेयर मार्केट

बीएसई : 79,476.19
+443.46 +0.56% ↑

एनएसई :24,141.95
131.35 (0.55%) ↑

मौसम बेंगलूरु

अधिकतम : 30°
न्यूनतम : 21°

टाटा समूह ने बंद किया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का फंड

भारत विरोधी एजेंडा चलाने पर सौ से अधिक बर्खास्त

मुंबई, 01 जुलाई (एजेंसियां)। राष्ट्रद्रोही वामपंथियों का अड्डा बनते जा रहे टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस से सौ से अधिक कर्मचारी निकाल दिए गए। बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों को फंड की कमी के कारण नौकरी से बाहर किया गया है। लेकिन यह पर्दे के ऊपर वाला सच है। पर्दे के अंदर वाला सच यह है कि टाटा समूह ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का फंड बंद कर दिया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कई गंभीर विवादों में घिर गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में पढ़ने वाले छात्रों पर राजद्रोह के मुकदमे में बंद शरजील इमाम के समर्थन में नारे लगाने के आरोप लग चुके हैं। इंस्टीट्यूट में कश्मीर की आजादी को लेकर पोस्टर भी लगाए जाते थे।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के कारण 55 शिक्षकों और 60 दूसरे स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया है। यह कार्रवाई शुक्रवार 28 जून 2024) को हुई। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने अपने मुंबई कैम्पस से 20, हैदराबाद कैम्पस से 15, गुवाहाटी कैम्पस से 14 और तुलजापुर कैम्पस से 6 लोगों को निकाला है। इन लोगों को टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरफ से भेजे गए इमेल में निष्कासन का कारण टाटा एजुकेशन ट्रस्ट से पैसा न मिलना बताया गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस प्रशासन ने मीडिया को बताया है कि उसने कई बार टाटा एजुकेशन ट्रस्ट को पैसे भेजने की मांग की, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं मिला।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से निकाले गए यह सभी कर्मचारी संविदा पर थे। इनमें से कुछ 10 साल से अधिक समय से यहां काम कर रहे थे। निकाले गए कर्मचारियों ने कहा है कि उनका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के साथ काम करने का अनुबंध मई महीने में खत्म हो गया लेकिन वह फिर भी इस उम्मीद में काम करते रहे कि उन्हें आगे भी काम पर रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि उनका अनुबंध नवीनीकृत नहीं किया गया है, ▶10 पर

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र बने थे आतंकवादी : एनआईए

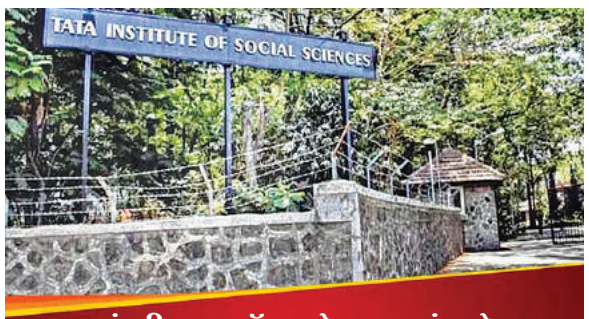

लगाए जाते थे कश्मीर की आजादी और राष्ट्रद्रोहियों के समर्थन वाले नारे

हैदराबाद से 15, मुंबई से 20, गुवाहाटी से 14, तुलजापुर से 6 निष्कासित

कार्टून कॉर्नर

खबरें जो सोच बदल दे शुभ लाभ DAILY हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

नई टीम का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

तेरापंथ युवक परिषद विजयनगर के नव मनोनीत अध्यक्ष कमलेश चोपड़ा एवं उनकी टीम का शपथ ग्रहण का आयोजन साध्वी सिद्धप्रभाजी के सानिध्य में जैन संस्कार विधि द्वारा विजयनगर स्थित अर्हम भवन में सम्पन्न हुआ।

संस्कारक की भूमिका में संस्कारक छत्र मालू, भंवर लाल मांडोत, अभिषेक कावडिया, विकास बाँठिया और धीरज भादानी ने निर्दिष्ट विधि विधान एवं मंगल मन्त्रोचार से कार्यक्रम को सम्पन्न करवाया।

विजयस्वर संगम की टीम द्वारा मंगलाचरण किया गया। अभातेयुप प्रबुद्ध विचारक दिनेश पोखरणा ने श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन किया। परिषद निवर्तमान अध्यक्ष राकेश पोखरणा ने पधारे हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया एवं नव मनोनीत अध्यक्ष कमलेश चोपड़ा को अध्यक्ष पद की गोपनीयता की शपथ दिलायी।

तत्पश्चात कमलेश चोपड़ा ने अपने प्रबंध मंडल परामर्शक एवं कार्यसमिति की घोषणा की एवं सभी को शपथ दिलायी।

तेरापंथ युवक परिषद प्रबंध मंडल में उपाध्यक्ष प्रथम विकास बाँठिया, उपाध्यक्ष द्वितीय अशोक मारू, मंत्री संजय भटेवरा, सहमंत्री प्रथम पवन बैद, सहमंत्री द्वितीय कमलेश दक, कोषाध्यक्ष अमित नाहटा एवं संगठन मंत्री पंकज कोचर को मनोनीत किया। इस अवसर पर साध्वीजी ने मंगल आशीर्वचन देते हुए नव मनोनीत टीम को शुभकामनाएं संप्रेषित की एवं फरमाया की नई टीम को विनय के साथ सबको साथ ले कर चलना है।

हमें पूरी युवा शक्ति को परिषद में जोड़कर नये नये कार्यों को सम्पादित करना है। आध्यात्मिकता की तरफ युवा शक्ति को ले जाना है और चातुर्मास में युवकों को ज्यादा से ज्यादा धर्म लाभ लेने की प्रेरणा दी। अभातेयुप अभूतपूर्व अध्यक्ष विमल कटारिया ने टीम को शुभमंगलकामना सम्प्रेषित करते हुए विजयनगर के गौरवशाली इतिहास को और नयी ऊँचाइयाँ प्रदान करने के साथ नए अध्यक्ष एवं टीम के प्रति मंगलकामना प्रेषित की। अभातेयुप परामर्शक दिनेश पोखरणा, तेरापंथ सभा विजयनगर अध्यक्ष मंगल कोचर, महिला मंडल अध्यक्षा मंजू गादिया ने नई टीम को शुभमंगलकामना सम्प्रेषित की। शपथ समारोह के आयोजन में अभातेयुप परिवार, तेयुप विजयनगर के पूर्व अध्यक्ष, क्षेत्रीय तेयुप परिषद पदाधिकारी, तेरापंथी सभा, महिला मंडल, ज्ञानशाला, अर्हम मित्र मंडल, तेयुप विजयनगर के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। संचालन तेयुप पुर्व अध्यक्ष अमित दक ने किया। आभार तेयुप मंत्री संजय भटेवरा ने व्यक्त किया।

सीरवी समाज वालीबॉल कप का हुआ आयोजन

येलहंका ए. टीम ने जीती प्रतियोगिता

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

यलहंका स्पोर्ट्स क्लब की ओर से शूटिंग वालीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन तावरेकेरे स्थित आईजी वाटिका मैदान में किया गया। जिसमें कुल 16 टीमों ने भाग लिया। इसमें फाइनल में यलहंका ए और के. आर. पेट मैसूरु के बिच खेला गया। जिसमें विजेता यलहंका ए. टीम रही। वही उपविजेता के. आर. पेट मैसूरु रही। बेस्ट नेटर दिलीप, बेस्ट अटैकर रॉकी, बेस्ट सेंटर मुकेश, मैन ऑद द मैच सुरेश को दिया गया। बेस्ट सर्विस राहुल, इमेजिंग प्लेयर भरत। विजेता और उप विजेता टीम को कप प्रदान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर यलहंका स्पोर्ट्स क्लब की ओर से यलहंका बडेर के अध्यक्ष मोहनलाल सैणचा, सचिव अशोक पंवार कोषाध्यक्ष भुण्डाराम राठौड़, सुंकदकट्टे बडेर के अध्यक्ष रूगाराम चोयल, सचिव हनुमान बर्फा, सह –सचिव भंवरलाल गे–हलोत का स्वागत किया गया। इस मौके पर चौथाराम पंवार, प्रतापमल पंवार, चिमनाराम सोलंकी,भेराराम पंवार का सम्मान किया गया। यहलंका स्पोर्ट्स क्लब ए.टीम के कप्तान सुरेश चोयल, बी.टीम के कप्तान अमराराम पंवार मौजुद रहे। वही यलहांका ए. टीम के मुलाराम पंवार ने बताया कि यलहंका स्पोर्ट्स क्लब के सभी खिलाड़ियों ने तन मन धन से सहयोग देकर टूर्नामेंट आयोजन को सफल बनाया। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम बिना वाद विवाद शानदार सम्पन्न हुआ। सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के लिए खाने पिने की बेहतरीन तरीके से व्यवस्था की गई। इस कार्यक्रम में आयोजकों का माला साफा द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन केंगरी वडेर के खेल मंत्री ढगलाराम लचेटा ने किया।

महावीर मुणोत अध्यक्ष व नीरज कटारिया मंत्री बने

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

समस्त जैन समाज की संस्था जैन युवा संगठन बेंगलूरु की आम सभा बिबियुल जैन विद्यालय के प्रांगण में आयोजित की गई। सभा की शुरूआत मंगलाचरण से हुई। अध्यक्ष महेंद्र बागरेचा ने सभी सदस्यो एवं सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टियों का स्वागत करते हुए सम्पूर्ण वर्ष में प्राप्त सहयोग के लिए सभी सदस्यों की बारंबार अनुमोदना की।

मंत्री मदन मुणोत ने मंत्री प्रतिवेदन द्वारा वर्ष भर में संगठन द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रेषित की। कोषाध्यक्ष मुकेश सुराणा ने पूरे वर्ष के आय व्यय का ब्योरा दिया। जैन युवा संगठन सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश धोका ने सेवा ट्रस्ट की विस्तृत रिर्पोट प्रेषित की। सदस्यों के

अनुशासन संबंधित नूतन नियम उपाध्यक्ष महावीर मुणोत ने रखे व भविष्य में उसका पालन करने के लिए सर्वसम्मति बनी। मंत्री मदन मुणोत ने महेंद्र बागरेचा का सेवानिवृत पत्र का वाचन किया। संचालन पूर्व मंत्री दिलीप संचेती, आभार सह मंत्री विशाल गुगलिया ने प्रकट किया। सभा के पश्चात आगामी कार्यकाल 2024–25 के लिए चुनाव प्रक्रिया का आयोजन किया गया। जैन युवा संगठन सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी गौतम मेहता एवं सह चुनाव के रूप में शांतिलाल मेहता द्वारा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर आगामी कार्यकाल के लिए 15 कार्यकारिणी सदस्यों की घोषणा की गई। कार्यकारिणी द्वारा महावीर मुणोत को अध्यक्ष, मुकेश सुराणा को उपाध्यक्ष, नीरज कटारिया को मंत्री, सुश्रुत चेलावत को सहमंत्री, संतोष डूंगरवाल को कोषाध्यक्ष चुना गया। कार्यकारिणी समिति के लिए अभिषेक बोहरा, अनुराग लल–वानी, अनिल बंट, दिनेश तांतेड़, हितेश कांकलिया, मोनीश मुथा, मोती गोटावत, रितेश मेहता, विशाल गुगलिया, विनय गांधी को चुना गया। इस मौके पर दिनेश खिवेंसरा, मुकेश बाबेल, विपुल पोरवाल को पूर्वपदेन पदाधिकारी एवं प्रवीण लालवानी, आतिश धोका को पूर्व कार्यकारिणी सदस्य चुना गया।

सांसद तेजस्वी सूर्या को किया सम्मानित

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

फाउंडेशन इंडिया द्वारा रविवार शाम को होटल संगरीला के सभागार में लोकसभा चुनाव में बेंगलूरु दक्षिण से दूसरी बार बड़े मतों से जितने पर सांसद तेजस्वी सूर्या का सम्मान किया गया।

इस अवसर पर अनेक समाज से बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। फाउंडेशन इंडिया के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंघल व उपाध्यक्ष पारस चोवटिया ने शाल व गु–लदस्ता देकर सम्मानित किया। माहेश्वरी समाज के एनके मालू, अग्रवाल समाज विकास ट्रस्ट के जयप्रकाश गुप्ता, सुरेश कुमार मोदी, हरियाणा सेवा ट्रस्ट, अग्रवाल समाज से सतीश गोयल ने भी सम्मान किया। तत्पश्चात सांसद ने कहा कि आप सभी ने अथक प्रयास व मेहनत

से मुझे दूसरी बार जीता कर सेवा करने का मौका दिया है।

मैं हमेशा विनम्रता के साथ कार्य करने पर तत्पर रहुंगा। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों का आभार धन्यवाद व्यक्त किया। सचिव संजय गुप्ता ने संचालन किया और सभी समाज से पधारे गणमान्य लोगों का आभार प्रकट किया।

श्री गुरु गणेश सेवा समिति की साधारण सभा कल

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। श्री गुरु गणेश सेवा समिति कर्नाटक बेंगलूरु की साधारण सभा बुधवार प्रातः 8 बजे से लालबाग रोड स्थित एम. टी. आर. होटल में रखी गयी है। यह समिति का 75वां (डायमंड जुबली) मासिक अन्नदानम (महाप्रसादी) है। प्रत्येक माह की हर अमावस्या पर इस अन्नदानम में 4500 से 5000 जरूरतमंदरें को भोजन वितरित किया जाता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आगामी 12 सितम्बर को समिति का एक संघ झालाना, पूणा, हैदराबाद और अहमदनगर जा रहा है। उपरोक्त जानकारी समिति के अध्यक्ष किरणचंद बोहरा ने दी। इस अन्नदानम कार्यक्रम पर कर्नाटक तप चन्द्रिका साध्वी पूज्य आगम श्री जी एवं सेवाभावी, मधुर गायिका महासाध्वी धैर्याश्रीजी का पदार्पण महामांगलिक देते हुए होगा।

रक्तदान शिविर का आयोजन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

मारवाड़ी युवा मंच की बेंगलूरु शाखा ने रविवार को नारायणा हृदयालय ब्लड बैंक के सहयोग से शहर के डोड्डानेकुण्डी, आउटर रिंग रोड में स्थित दुर्गा पेटल अपार्टमेंट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। यह रक्तदान शिविर अपार्टमेन्ट के क्लब हाउस में आयोजित हुआ। जिसमें दुर्गा पेटल अपार्टमेन्ट के ओनर्स एसोसिएशन का भरपूर सहयोग मिला। शिविर में कुल 66 यूनिट रक्त का संग्रह हुआ। रक्तदान शिविर समारोह में शाखा के अध्यक्ष स्नेहकुमार जाजू ने सभी रक्तदाताओं का स्वागत किया। शाखा उपाध्यक्ष जयप्रकाश अग्रवाल ने आज की परिस्थिति में रक्तदान की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और रक्तदान की जरुरत के बारे में समझाया।

रक्तदान के संयोजक तनूज टेकरीवाल ने सभी रक्तदाताओं को रक्तदान के बाद आभार पत्र के साथ फलों का जूस और बिस्किट दिया। रक्तदान के दूसरे संयोजक रूपेश अग्रवाल ने रक्तदान शिविर की रुपरेखा बताई। शिविर में अपार्टमेन्ट के निवासियों ने बढ़चढ़ कर भाग किया। साथ ही मंच के युवाओं ने भी उत्साह से अपने पूरे परिवार और मित्रों के साथ रक्तदान किया। इस अवसर पर सोनू शर्मा और जयेश पोद्दार भी उपस्थित थे। इन दोनों ने भविष्य के होने वाले रक्तदान शिविर की जानकारी दी। पूरे अपार्टमेंट के निवासियों को धन्यवाद किया।

80 प्रतिशत निजी और सरकारी नौकरियाँ कन्नडिगाओं को दी जानी चाहिए: नारायण गौड़ा

फ्रीडम पार्क में किया विरोध प्रदर्शन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार और निजी क्षेत्र में कन्नडिगाओं के लिए 80 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की मांग करते हुए राजधानी बेंगलूरु सहित राज्य भर में विरोध की घंटी बजा दी है। कर्नाटक रक्षा मंच के राज्य अध्यक्ष टी.ए. नारायण गौड़ा ने राजधानी बेंगलूरु के फ्रीडम पार्क में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जबकि राज्य भर के कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि सभी स्तरों पर कन्नडिगाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त अधिनियम बनाया और लागू किया जाना चाहिए। सरोजिनी महिषी रिपोर्ट को लागू करने सहित सी और डी ग्रेड पदों पर 100 प्रतिशत नौकरियां कन्नडिगाओं को दी जाएं। मांग थी कि अन्य श्रेणियों में 80 प्रतिशत नौकरियाँ कन्नडिगाओं को दी जानी चाहिए। करावे द्वारा बुलाए गए इस समर्थन के लिए कन्नड़ साहित्य परिषद, कलाकारों, फिल्म अभिनेताओं और अभिनेत्रियों सहित विभिन्न कन्नड़ समर्थक संगठनों ने अपना समर्थन घोषित किया और मांग की कि विरोध प्रदर्शन में भाग लेकर कन्नड़ लोगों को नौकरियां दी जाएं। इस अवसर पर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले करावे के अध्यक्ष टीए नारायण गौड़ा ने कहा कि राज्य में कर्नाटक रक्षा मंच देश की भूमि, जल और संस्कृति के अस्तित्व के लिए लगातार लड़ रहा है। कन्नड़ नेमप्लेट को अनिवार्य बनाने का हालिया संघर्ष सफल रहा है। अब कन्नडिगाओं को नौकरी देने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें अपने राज्य में नौकरियां मांगनी पड़ रही हैं। क्योंकि कन्नडिगा सहिष्णु और शांतिप्रिय हैं, विदेशी हम पर सवार हैं। इसलिए ऐसी स्थिति है जहां सभी क्षेत्रों में कन्नडिगाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है। राजधानी बेंगलूरु समेत देश के तमाम हिस्सों में नौकरियों पर अलग–अलग राज्यों के लोगों का कब्जा है। इस तथ्य के कारण कि कन्नडिगाओं के अधिकारों का आनंद राज्य के बाहर के लोगों द्वारा लिया जा रहा है, ऐसी स्थिति बन गई है कि हमारे राज्य में कन्नडिगा बेरोजगार हो रहे हैं। इसलिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमने अभी जो विस्फोट हुआ है उसे नहीं रोका तो भविष्य में हमें निश्चित तौर पर खतरे का सामना करना पड़ेगा। हमारा प्रस्ताव है कि कर्नाटक में धन और रोजगार पर हमे पहली प्राथमिकता मिलनी चाहिए। हमने इसके लिए संघर्ष किया। नारायण गौड़ा ने गरजते हुए कहा कि हम तब तक संघर्ष जारी रखेंगे जब तक इसे तार्किक स्तर पर नहीं ले जाया जाता, विभिन्न मांगों वाली एक याचिका राज्य सरकार को सौंपी गई।

सोमन्ना ने यशवंतपुर एवं बेंगलूरु छावनी रेलवे स्टेशनों के चल रहे पुनर्विकास की समीक्षा की

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने यशवंतपुर एवं बेंगलूरु छावनी रेलवे स्टेशनों पर चल रहे पुनर्विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर उनके साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, सांसद पी. सी. मोहन और विधायक रिजवान अरशद मौजूद थे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य स्टेशनों को विश्वस्तरीय सुविधाओं में बदलना, यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाना, बुनियादी सुविधाओं का आधुनिकीकरण करना तथा बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए क्षमता में वृद्धि करना है। यशवंतपुर एवं बेंगलूरु छावनी स्टेशन कर्नाटक के रेलवे नेटवर्क में महत्वपूर्ण केंद्र हैं, जो भारतीय रेलवे के महत्वाकांक्षी स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम

के तहत परिवर्तनकारी बदलावों से गुजर रहे हैं। वे यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं एवं सेवाएं प्रदान करने के सपने को पूरा कर रहे हैं। पुनर्विकास योजना में यशवंतपुर स्टेशन के लिए 367 करोड़ रुपये और बेंगलूरु कैंटोनमेंट स्टेशन के लिए 486 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है, जो रेलवे स्टेशन के बुनियादी ढांचे में नए मानक स्थापित करने, यात्रियों के आराम, सुविधा, सुरक्षा को बढ़ाने और यात्रियों के लिए आरामदायक प्रतीक्षा क्षेत्र, बहु–स्तरीय पार्किंग क्षेत्र, बच्चों के लिए खेल का मैदान और स्थानीय उत्प–ादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए तैयार है, क्योंकि दोनों स्टेशनों को समर्पित प्रवेश द्वारों और एक विशाल छत प्लाजा के साथ स्टेशन के दोनों किनारों को जोड़ने वाली एक विश्व स्तरीय सुविधा में बदल दिया गया है। सोमन्ना ने रेलवे अधिकारियों को स्टेशन परिसर में और अधिक हरियाली लाने, यात्रियों के लिए विश्राम स्थलों की सुविधाओं का विस्तार करने और यशवंतपुर में समय पर काम पूरा करने के लिए निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, बेंगलूरु कैंटोनमेंट में, उन्होंने स्टेशन भवन की विरासत को संरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया। पीसी मोहन ने पार्किंग सुविधा में सुधार का अनुरोध किया, जबकि रिजवान अरशद ने प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन को स्टेशन के प्रवेश द्वार से जोड़ने का आग्रह किया।

यशवंतपुर और बेंगलूरु कैंटोनमेंट स्टेशन के रणनीतिक महत्व को स्वीकार करते हुए सोमन्ना ने उपनगरीय रेलवे, मुख्य लाइन मार्गों और मेट्रो लाइनों को जोड़ने वाले एक महत्वपूर्ण जंक्शन के रूप में इसकी भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्र की बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने में स्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया, अगले दो से तीन दशकों में पर्याप्त यातायात की मात्रा का अनुमान लगाया।

जेडीएस प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए निखिल के नाम की चर्चा तेज

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर नए व्यक्ति की नियुक्ति की चर्चा सामने आई है और युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष निखिल कुमारस्वामी का नाम सबसे आगे है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए वह जल्द ही किसी भी समय जद (एस) के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले हैं। कुमारस्वामी के मांड्या लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद पर नये व्यक्ति को चुनने का मुद्दा चर्चा में आ गया है। पूर्व मंत्री बंडप्पा काशमपुर और विधायक सी.बी. सुरेश बाबू का नाम प्रचलन में आया है। निखिल कुमारस्वामी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह चन्नपटना उपचुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि पार्टी संगठन में शामिल रहेंगे। जेडीएस सूत्रों ने कहा कि इस प्रकार, निखिलकुमार स्वामी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किए जाने की संभावना बढ़ गई है। चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र से कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद जेडीएस विधायक दल की सीट खाली हो गई है। जेडीएस कोर कमेटी के अध्यक्ष जी.टी. देवगौड़ा को विधायक दल के नेता का पद मिलने की संभावना है। इसे लेकर अंदरूनी हलके में चर्चा हुई है। पार्टी के सूत्रों ने कहा कि नए जद (एस) विधायक दल के नेता की नियुक्ति मानसून सत्र शुरू होने तक की जाएगी और जीटी देवेगौड़ा यह पद संभालेंगे।

राज्य की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव

भाजपा उतार सकती है चौंकाने वाले उम्मीदवार

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

भाजपा इस बार राज्य की तीन विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में चौंकाने वाले उम्मीदवार उतारने की सोच रही है। यदि सब कुछ उम्मीद के मुताबिक रहा, तो मौजूदा सांसद डॉ. सी.एन. मंजूनाथ की पत्नी अनुसूया को, जेडीएस का गढ़ माने जाने वाले, चन्नपट्टना में भाजपा से लाने की चुपचाप कोशिश की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री सांसद बसवराज बोम्मई के बेटे भरत बोम्मई ने हावेरी जिले के शिग्गांवी और पूर्व मंत्री बी. श्रीरामुलु ने बेल्लारी जिले के संदुर विधानसभा क्षेत्र के लिए टिकट की पैरवी की है। पार्टी में चर्चा अभी प्राथमिक स्तर पर है और भाजपा ने तीन सीटों पर विजयी उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर सत्तारूढ़ कांग्रेस को चुनौती देने की रणनीति तैयार की है। अंत में सभी को केंद्रीय महामहिम द्वारा लिये गये निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया गया है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में,

भाजपा उम्मीदवार डॉ. सी.एन. मंजूनाथ ने बेंगलूरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की, जिसे केपीसीसी अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का गढ़ कहा जाता था। चन्नपटना उपचुनाव के संघर्ष के साथ-साथ ओक्कालिगा नेता एचडी कुमारस्वामी और डी.के. शिवकुमार की जद्दोजहद के बीच ओक्कालिगा उम्मीदवारों को चुनने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रकार चन्नपटना उपचुनाव प्रत्येक पार्टी के दो शक्तिशाली नेताओं के बीच प्रतिष्ठा का मुकाबला है। चूंकि डीके शिवकुमार के चन्नपटना उपचुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ने की संभावना है, इसलिए कहा जा रहा है कि भाजपा-जेडीएस गठबंधन ने डीके बंधुओं को बांधने के लिए एक आश्चर्यजनक उम्मीदवार खड़ा करने की योजना बनाई है। बेंगलूरु ग्रामीण में डीके सुरेश पहले ही लोकसभा चुनाव हार चुके हैं और भाजपा उम्मीदवार डॉ. सीएन मंजूनाथ ने अभूतपूर्व जीत हासिल की है। अगर डीके शिवकुमार चन्नपट्टना से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की महिला वोटरों को आकर्षित करने के लिए सांसद डॉ. सीएन मंजूनाथ की पत्नी अनुसूया को भाजपा-जेडीएस गठबंधन का उम्मीदवार बनाने की सोच रहे हैं। अनुसुया को गठबंधन प्रत्याशी घोषित करने को लेकर गठबंधन दलों के नेताओं ने चर्चा की है। कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियों के नेता जीत-हार के गणित में जुट गए हैं कि अनुसूया को मैदान में उतारने से क्या फायदा मिल सकता है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले एनडीए गठबंधन से एचडी कुमारस्वामी केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। इसके अलावा चन्नपट्टना में विधायक के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी जेडीएस को जीत मिलनी चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र में जेडीएस को बरकरार रखना कुमारस्वामी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है।

बोम्मई खुद विशेष ध्यान देंगे

पूर्व मुख्यमंत्री बोम्मई ने हावेरी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है और उनके बेटे भरत बोम्मई को शिग्गांवी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारने का विचार है जो खाली है। अगर परिवार को टिकट दिया गया तो बोम्मई खुद विशेष ध्यान देंगे और बेटे को जिताने की जिम्मेदारी उठाएंगे। इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाने का दबाव बना हुआ है। इसी तरह, बी श्रीरामुलु, जो पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में हार चुके हैं और राजनीतिक संकट में हैं, फिर से अपनी किस्मत आजमाने की उम्मीद कर रहे हैं। बेल्लारी के सांसद तुकाराम ने मांग की है कि श्रीरामुलु को संदुर विधानसभा क्षेत्र के उप-चुनाव के लिए टिकट दिया जाना चाहिए, जो उनके इस्तीफे के कारण खाली हो गया है।

पुलिस अधीक्षक के कार्यालय के बाहर महिला की हत्या

हासन/शुभ लाभ ब्यूरो।

हासन में पुलिस अधीक्षक के कार्यालय परिसर में एक महिला की उसके पति, जो एक हेड कांस्टेबल है, ने कथित तौर पर हत्या कर दी।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गोरूर पुलिस स्टेशन से जुड़े हेड कांस्टेबल लोकनाथ ने कथित तौर पर अपनी पत्नी ममता की हत्या कर दी। हाल के दिनों में दंपति के बीच मतभेद थे। घर पर तीखी बहस और बार-बार मारपीट के बाद, ममता अपने पति के व्यवहार के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपनी शिकायतें साझा करने के लिए एसपी के कार्यालय गई थी। अपनी पत्नी के इस कदम से परेशान लोकनाथ ने कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला किया। उसके सहकर्मी उसे हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले गए। हालांकि, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।

सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली फर्जी खबरें समाज के लिए खतरनाक: सीएम

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि समाज को फर्जी खबरों से बहुत सावधान रहना चाहिए और प्रेस तथा मीडिया संगठनों से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने का आह्वान किया। वे सोमवार को बेंगलूरु प्रेस क्लब, एसोसिएशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित प्रेस दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली फर्जी खबरें समाज के लिए विनाशकारी हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों पर कड़ी नजर रखने तथा उनका पता लगाने के लिए हर जिले में एक विशेष इकाई स्थापित की गई है।

उन्होंने कहा कि फर्जी खबरों का पता लगाने, उन पर नियंत्रण करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों में फैक्टचेक इकाइयां सक्रिय की गई हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया तेजी से लोगों तक पहुंच रहा है। पहले के समय में खबरों के लिए टीवी, अखबार और रेडियो पर निर्भर रहना पड़ता था। उन्होंने कहा कि अब सोशल मीडिया पर खबरें और भी तेज हो रही हैं। सोशल मीडिया के फायदे के साथ-साथ इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं। इसे अच्छे ढंग से स्वीकार किया जाए तो लाभ होगा। अन्यथा फर्जी खबरें समाज को नुकसान पहुंचाएंगी। उन्होंने कहा कि हमने इनकी जांच और नियंत्रण के लिए हर जिला केंद्र में विशेष इकाइयां शुरू की हैं। फर्जी खबरों से सावधान रहें। जो भी पक्ष में होगा उसके पक्ष में और भी अभियान चलेंगे। जो असहमत होते हैं उनकी आलोचना की जाती है। सोशल मीडिया को ना कहने जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन इन पर नियंत्रण जरूरी है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव नसीर अहमद, मुख्यमंत्री के सचिव के.वी. त्रिलोकचंद्र, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार के.वी. प्रभाकर, सूचना आयुक्त सुरालकर विकास किशोर, श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष शिवानंद तगादुरु, एमएलसी यू.बी. वेंकटेश, प्रेस क्लब के अध्यक्ष आर. श्रीधर, महासचिव मल्लप्पा मौजूद थे। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णप्रसाद ने अपने मुख्य भाषण में पत्रकारिता की वर्तमान स्थिति के बारे में बताया।

अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री की मांग के बाद

कर्नाटक कांग्रेस में बॉस बदलने की मांग को लेकर फिर से खींचतान

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक में अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री रखने की खींचतान के बीच, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार शाम को सत्तारूढ़ कांग्रेस के राज्य नेतृत्व में संभावित बदलाव का संकेत दिया, जिसका नेतृत्व वर्तमान में उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार कर रहे हैं। परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा कि यदि कोई सरकार में मंत्री है और राज्य पार्टी प्रमुख भी है, (आलाकमान को लगता है कि) दोनों पदों को संभालना मुश्किल होगा और वे बदल जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है।

यह घटनाक्रम कांग्रेस के भीतर एक सप्ताह से चल रही खींचतान के बाद हुआ है, जिसकी शुरुआत सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने की थी, जब उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के लिए अतिरिक्त उपमुख्यमंत्री की अपनी लंबे समय से चली आ रही मांग को उठाया था।

यह मांग मुख्य रूप से सिद्धरामैया खेमे की है, जो शिवकुमार को दो प्रमुख विभागों, बेंगलूरु विकास और सिंचाई के साथ राज्य कांग्रेस प्रमुख के रूप में बनाए रखने से नाराज है। राजन्ना ने कांग्रेस की एक व्यक्ति, एक पद नीति को भी उठाया और कहा था कि शिवकुमार को केवल लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष के रूप में बने रहना था। शिवकुमार

खेमे ने सिद्धरामैया की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की वकालत करके मांग को खत्म करने का प्रयास किया। बुधवार को चन्नागिरी के विधायक बसवराजू शिवगंगा ने सिद्धरामैया से कहा कि शिवकुमार को अभी सीएम बनने दें।

एक दिन बाद, बेंगलूरु में केम्पेगौड़ा जयंती समारोह के दौरान, वोक्कालिगा समुदाय के एक प्रमुख संत चंद्रशेखरनाथ स्वामीजी, जिससे शिवकुमार संबंधित हैं, ने सिद्धरामैया से उपमुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कहा। केवल शिवकुमार ही सीएम नहीं बने हैं। यह तभी हो सकता है जब सिद्धरामैया अपना मन बना लें। इसलिए, कृपया शिवकुमार को सीएम बनाएं। हालांकि, शिवकुमार ने शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पार्टी के हित में अपना मुंह बंद रखने को कहा और संतों से पार्टी के मामलों में हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया।

परमेश्वर ने कहा कि पार्टी अध्यक्षों को बदलने की मांग सभी दलों में आम है। उन्होंने कहा जे पी नड्डा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वह अब केंद्रीय मंत्री भी हैं। भाजपा में अब अध्यक्ष बदलने की चर्चा चल रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले भी राज्य कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में बने रहने के लिए गृह मंत्री के रूप में अपने कैबिनेट पद का त्याग करना पड़ा था। परमेश्वर ने कहा शिवकुमार के पास दो प्रमुख विभाग हैं। बेंगलूरु को दूसरे स्तर पर ले जाने के लिए ब्रांड बेंगलूरु की उनकी योजना और सिंचाई विभाग हैं। साथ ही, उन्हें केपीसीसी अध्यक्ष भी होना है और पार्टी के मामलों को भी समय देना है। उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा नेता जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं। हालांकि, इस बारे में फैसला आलाकमान लेगा। विवाद बढ़ने पर शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। हालांकि, उनकी मुलाकात का ब्योरा उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसी अटकलें हैं कि वह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को छोड़ने के लिए अनिच्छुक थे। 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में उनके नेतृत्व में पार्टी के प्रदर्शन को उजागर करते हुए, उन्होंने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों तक पद में विस्तार की मांग की है। ऐसी भी चर्चा है कि कांग्रेस शिवकुमार को राज्य पार्टी प्रमुख के पद से हटने के लिए राजी करके अतिरिक्त उपमुख्यमंत्रियों की बार-बार की मांग को दबाने की कोशिश कर रही है।

पुलिस बल को ऐप से किया गया है लैस

तीन नए कानूनों को लागू करने का दिया जा रहा है प्रशिक्षण: परमेश्वर

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि कर्नाटक के पुलिस बल को देश में सोमवार से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन का प्रशिक्षण दिया गया है। इतना ही नहीं, भारत के आईटी हब के पुलिस बल को अपना काम सही ढंग से करने के लिए तकनीकी सहायता भी मिली है, क्योंकि पुलिस के संदर्भ के लिए एक ऐप बनाया गया है, जब तक कि वे नए कानूनों के तहत मामलों को संभालने में पूरी तरह से निपुण नहीं हो जाते। यहां पत्रकारों से बात करते हुए परमेश्वर ने कहा नए कानूनों के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। हमने कांस्टेबल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक अपने कर्मियों को इसके अनुसार प्रशिक्षित किया है। हमने एक ऐप भी बनाया है, जिसका उपयोग अधिकारी जब चाहें कर सकते हैं। नए कानूनों की सफलता या विफलता का तुरंत पता नहीं चलेगा। मामले दर्ज होने के बाद, यह देखना बाकी है कि अदालतें उन्हें कैसे देखती हैं। यह कानूनी रूप से परीक्षा की घड़ी है। नए कानून पूरे देश में लागू किए जा रहे हैं और सभी क्षेत्रों से परिणाम आएंगे। एक बार जब हमें परिणाम मिल जाएंगे, तो कानूनों के पक्ष या विपक्ष में चर्चा की गुंजाइश होगी। उन्होंने कहा कि अगर कोई विफलता पाई जाती है, तो सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे।

उन्होंने कहा इस पर कई सालों से बहस चल रही थी और आखिरकार इसे लागू किया जा रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कानूनों में कुछ बदलाव किए गए हैं। कर्नाटक में पुलिस को उनके काम में मदद करने के लिए एक ऐप दिया गया है। अंतर-जिला तबादलों से संबंधित मुद्दों को संभालने के लिए भी कानून बनाए गए हैं। पति-पत्नी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले कर्मियों को उनके मूल स्थानों पर काम करने की सुविधा देने के लिए दिशा-निर्देश बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दिशा-निर्देश बनने के बाद, पुलिसकर्मी अपने तबादलों के संबंध में अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। कर्नाटक सरकार के गिरने के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के दावों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा वे दावा करते हैं कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच लड़ाई है। वे अपना खुद का एजेंडा लेकर आएंगे। हमने लोगों को अपना वचन दिया है और हम उसे पूरा कर रहे हैं। आदिवासी कल्याण बोर्ड मामले के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा सरकारी अधिकारियों या राजनेताओं सहित जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई मामले की बैंकिंग एंगल से जांच कर रही है, जबकि विशेष जांच दल यह जांच कर रहा है कि विभाग में क्या गलत हुआ। अंत में जांच रिपोर्ट एक जैसी होनी चाहिए।

स्वाभाविक रूप से कई नाम सामने आएंगे

चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल और आदिवासी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक बसवराज दद्दाल के इस्तीफे की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की भाजपा की योजना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा जांच के दौरान, स्वाभाविक रूप से कई नाम सामने आएंगे। जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अगर अन्य लोगों की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर भाई-भतीजावाद का लगाया आरोप

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

प्रदेश भाजपा ने आबकारी विभाग में बेंगलूरु के आठ उपायुक्तों में से अपनी ही जाति के अधिकारियों की नियुक्ति का विरोध किया है और राज्य सरकार पर भाई-भतीजावाद का गंभीर आरोप लगाया है। उत्पाद विभाग में जातिगत भेदभाव है। एक ही समुदाय के चार लोगों को दर्जा दिया गया है। शिकायत की गई है कि तबादले और नियुक्ति में कुछ मंत्रियों के करीबियों ने जमकर पैसा लगाया है। पिछले दिनों राज्य सरकार पर भाई-भतीजावाद के आरोप सुनने को मिले थे। अब फिर से भाई-भतीजावाद का आरोप सुनने को मिला है। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि इस मामले को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा जाएगा। सिर्फ आबकारी विभाग ही नहीं है, अन्य विभागों में भी भाई-भतीजावाद हो रहा है। कांग्रेस का मतलब भाई-भतीजावाद है। विपक्ष के नेता ने कहा कि गांधी परिवार इसका उदाहरण है। मंत्री ट्रांसफर का धंधा कर रहे हैं। सभी विभागों में ट्रांसफर का गोरखधंधा जोरों पर है। उन्होंने मंत्री पर अपने समुदाय को खुश करने का आरोप लगाया। हाल में विभागों में सिंडिकेट ही तबादले का निर्णय लेते हैं। यही सिंडिकेट मंत्रियों को भी प्रभावित करते हैं। मंत्री ने तबादले को थोक का धंधा बना लिया है।

घरों को पानी से हुए नुकसान का मामला

स्थानीय लोगों ने एयरपोर्ट के खिलाफ किया प्रदर्शन

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट के रनवे से बहकर आए पानी से सात घर क्षतिग्रस्त होने के बाद करमबर के स्थानीय लोगों ने सोमवार को मेंगलूरु अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शन किया।

बार-बार अनुरोध के बावजूद, एयरपोर्ट के अधिकारी और जिला प्रशासन रनवे से पानी के बहाव के कारण घरों में जलभराव की समस्या को लेकर निवासियों की चिंताओं को दूर करने में विफल रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि करमबर में एक निजी संपत्ति के मालिक ने भारी मात्रा में मिट्टी डालकर जल निकासी के प्रवाह को अवरुद्ध कर दिया है। प्रभावित सात घरों के निवासी बहुत ही मुश्किल में हैं, उन्हें जलभराव की स्थिति में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, यहां तक कि उनका राशन भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से निराश स्थानीय लोगों ने विरोध में वाहनों को एयरपोर्ट में प्रवेश करने से रोक दिया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, रास्ता साफ किया और प्रदर्शनकारियों से चर्चा की। मेंगलूरु उत्तर के विधायक डॉ. भरत वाई शेट्टी ने स्थिति का आकलन करने और निवासियों की शिकायतों को सुनने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। स्थानीय लोगों की मांग है कि उपायुक्त और तहसीलदार मौके पर आएं और स्थायी समाधान करें। करमबार में एक घर पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। पीजी चलाने वाली एक निवासी को अपने घर में पानी घुसने के बाद मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बर्तन और फर्नीचर पानी में तैर रहे थे, जिससे बिजली के उपकरण खराब हो गए। पीजी छात्रों के लिए खरीदा गया राशन बर्बाद हो गया और उसे छत पर सुखाना पड़ा, जबकि कुछ को दुर्गंध के कारण फेंक दिया गया।

शुभ लाभ DAILY खबरें जो सोच बदल दे हिंदी दैनिक समाचार पत्र

किसानों ने केआरएस बांध के पास ट्रायल ब्लास्ट का विरोध दोहराया

सरकार पर खनन लॉबी के हितों की चापलूसी करने का संदेह

मैसूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कावेरी बेल्ट के किसानों ने मांड्या में एक गोलमेज बैठक के दौरान मैसूरु के पास केआरएस जलाशय में ट्रायल ब्लास्ट का विरोध दोहराया है। मैसूरु में एक मीडिया सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कर्नाटक राज्य रायता संघ (केआरआरएस) के नेता बदागलपुरा नागेंद्र ने कहा कि 29 जून को मांड्या में गोलमेज बैठक में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं ने मैसूरु के पास श्रीरंगपटना में केआरएस जलाशय की घेराबंदी करने का संकल्प लिया, अगर मांड्या जिला प्रशासन और कावेरी नीरावरी निगम लिमिटेड (सीएनएनएल) फिर से ट्रायल ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं। अधिकारियों द्वारा ट्रायल ब्लास्ट करने के प्रयासों को केआरअ-ारएस सहित किसान संगठनों द्वारा तीन बार रोका गया था। आखिरी प्रयास इस साल मार्च में किया गया था, जब केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीआईएमएफआर) के विशेषज्ञों की एक टीम केआरएस जलाशय के आसपास के क्षेत्र में परीक्षण विस्फोटों के लिए जमीन तैयार करने के लिए मांड्या पहुंची थी। सीएनएनएल और मांड्या जिला प्रशासन द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का हवाला देकर परीक्षण विस्फोट करने की तैयारी करने की खबरों के मद्देनजर मांड्या में किसान संगठनों की गोलमेज बैठक आयोजित की गई थी। मांड्या, मैसूरु, रामनगर, चामराजनगर, तुमकुरु और हासन जिलों के किसानों ने गोलमेज बैठक में भाग लिया और एक स्वर में परीक्षण विस्फोटों का विरोध किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसूरु के निकट केआरएस बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बांध की सुरक्षा को खतरे के मद्देनजर केआरएस जलाशय से 20 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन और संबद्ध गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन सरकार ने जलाशय की सुरक्षा पर खनन के दौरान विस्फोटों के प्रभाव का आकलन करने के लिए परीक्षण विस्फोट करने के लिए न्यायालय को वचन दिया था। खनन लाइसेंस धारकों द्वारा केआरएस जलाशय के 20 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध को लेकर उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने के बाद सीएनएनएल और मांड्या जिला प्रशासन परीक्षण विस्फोट करने के लिए आगे आए थे।

स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग

इस संदेह के साथ कि सरकार खनन लॉबी के आगे झुककर यह साबित करने के लिए परीक्षण विस्फोट करने की योजना बना रही है कि विस्फोटों से जलाशय को कोई खतरा नहीं है, केआरआरएस ने केआरएस जलाशय से 20 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की। इस बात की ओर इशारा करते हुए कि केआरएस न केवल किसानों की जीवन रेखा है, बल्कि कावेरी क्षेत्र में संपूर्ण मानव और पशु आबादी की जीवन रेखा है, नागेंद्र ने कहा कि किसानों ने परीक्षण विस्फोटों के लिए अपना विरोध (परीक्षण विस्फोटों के लिए) मांड्या जिला प्रशासन द्वारा बुलाई गई बैठक के दौरान स्पष्ट कर दिया था, जिसमें परीक्षण विस्फोटों को अंजाम देने के लिए उनका सहयोग मांगा गया था।

केईए समय पर प्रवेश पूरा करने के लिए अगले तीन महीनों तक सरकारी छुट्टियों पर भी करेगा काम

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) ने जुलाई, अगस्त और सितंबर में सरकारी छुट्टियों पर भी काम करने का फैसला किया है, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सीईटी 2024 और एनईईटी 2024 में उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए काउंसलिंग और सीट आवंटन की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू होगी। केईए के कर्मचारी इन तीन महीनों के दौरान रविवार, दूसरे शनिवार और चौथे शनिवार सहित सभी सरकारी छुट्टियों पर काम करेंगे। छुट्टियों में काम करने वाले कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश मिल सकता है।

केईए ने सरकारी छुट्टियों पर काम करने वाले कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान देने का फैसला किया है, अगर उन्हें प्रतिपूरक अवकाश नहीं मिलता है। इस साल भी सीईटी और एनईईटी काउंसलिंग एक साथ होगी, लेकिन केवल जुलाई में। इससे पहले, केईए कर्नाटक में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए केवल सीईटी परीक्षा, काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया आयोजित करता था। हालाँकि, हाल के वर्षों में, राज्य सरकार ने केईए को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों में भर्ती की जिम्मेदारी दी है। ये पहले कर्नाटक लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाते थे। इसके अलावा, केईए को कर्नाटक में मोरारजी देसाई आव-ासीय विद्यालय सहित आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने और उम्मीदवारों का चयन करने की जिम्मेदारी दी गई है।

मुझे भाजपा में फिर से शामिल होने का मिला न्योता: ईश्वरप्पा

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

भाजपा से निकाले गए नेता केएस ईश्वरप्पा ने सोमवार को कहा कि उन्हें पार्टी में फिर से शामिल होने का न्योता मिला है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इस मामले पर अभी तक अपना फैसला साझा नहीं किया है। शिवमोग्गा में पत्रकारों द्वारा भाजपा में उनकी संभावित वापसी के बारे में पूछे जाने पर ईश्वरप्पा ने कहा आपको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या होता है। उन्होंने उन अफवाहों का भी खंडन किया कि उनके बेटे केई कांतेश हावेरी जिले की शिगगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसे पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने हावेरी लोकसभा सीट से सांसद चुने जाने के बाद खाली किया था। शिवमोग्गा शहर में आगामी नगर निगम चुनावों और शिवमोग्गा जिले में स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में ईश्वरप्पा ने कहा कि उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा हम भाजपा के लोगों का एक समूह हैं और हम हमेशा पार्टी के हितों को प्राथमिकता देते हैं। हम ऐसा करना जारी रखेंगे।

उन्होंने कहा जब चुनाव होंगे, हम उस समय कोई फैसला लेंगे। हाल ही में हुए 2024 के आम चुनावों में भाजपा के उम्मीदवार पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई राघवेंद्र के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के बाद भाजपा ने ईश्वरप्पा को छह साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अपने प्रयासों के बावजूद, ईश्वरप्पा को केवल 30,050 वोट मिले, जबकि राघवेंद्र ने 2.43 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता। हालांकि, ईश्वरप्पा को अभी भी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का समर्थन प्राप्त है जो येदियुरप्पा और उनके बेटे विजयेंद्र के विरोधी हैं।

बलात्कार के आरोपी एमएलसी सूरज रेवन्ना को 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

यौन उत्पीड़न के आरोपी जनता दल (सेक्युलर) एमएलसी सूरज रेवन्ना की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई है। बेंगलूरु की एक अदालत ने सोमवार को सूरज की हिरासत बढ़ा दी, जिस पर 16 जून को गन्निकाडा में अपने परिवार के फार्महाउस पर एक पुरुष जेडी(एस) पार्टी कार्यकर्ता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। उसके खिलाफ 22 जून को एफआईआर दर्ज की गई थी और एक दिन बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन द्वारा 26 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 342 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत एक और शिकायत दर्ज की गई। एफआईआर में दो अन्य लोगों का भी नाम है। एफआईआर के अनुसार, सूरज ने कथित तौर पर होलनरसीपुरा के गन्निकाडा फार्महाउस में पहले कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया। सूरज के भाई प्रज्वल पर चार महिलाओं ने बलात्कार का आरोप लगाया है, जिसके बाद वह न्यायिक हिरासत में है। उनके पिता, होलनरसीपुरा के विधायक एचडी रेवन्ना पर भी उनके घर में काम करने वाली एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आर-ोप लगाया है। उन पर उन महिलाओं में से एक का अपहरण करने का भी आरोप है, जिनके साथ प्रज्वल ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और उन आरोपों में कुछ दिन जेल में बिताने पड़े।

पूर्व सीएम वीरप्पा मोइली की बेटी का निधन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की बेटी हम्सा मोइली (50) का बीमारी के कारण निधन हो गया। बीमारी के कारण उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बिना ही उनकी मौत हो गई। वीरप्पा मोइली की तीसरी बेटी हम्सा आम लोगों की दुर्दशा के प्रति संवेदनशील थी। जनुरागी नाम से, वह अपने ढांचे के भीतर समाज सेवा में शामिल थी।

नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान के फैसले का करेंगे पालन: सिद्धरामैया

स्वामीजी के बयान पर मुझे टिप्पणी नहीं करना

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक में सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर सियासी खींचतान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को कहा कि वह नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर कांग्रेस आलाकमान के फैसले का पालन करेंगे। वोक्कालिगा समुदाय के एक संत ने पिछले हफ्ते सार्वजनिक रूप से सिद्धरामैया से पद छोड़ने और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए रास्ता खाली करने का अनुरोध किया था। विश्व वोक्कालिगा महासंस्थान मठ के संत चंद्रशेखर स्वामी की अपील के बारे में पूछे जाने पर सिद्धरामैया ने कहा यह ऐसा मामला नहीं है जिस पर सार्वजनिक रूप से चर्चा की जाए। आलाकमान जो भी फैसला लेगा, हम उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा स्वामीजी क्या कहते हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारी राष्ट्रीय पार्टी है। एक हाईकमान है। सिद्धरामैया के करीबी माने जाने वाले कुछ मंत्रियों ने उप मुख्यमंत्री के और पद सृजित करने और उन्हें लिंगायत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को दिए जाने की मांग की है। इसे शिवकुमार के राजनीतिक पर कतरने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वोक्कालिगा समुदाय से आने वाले शिवकुमार वर्तमान में सिद्धरामैया

सरकार में एकमात्र उप मुख्यमंत्री हैं। पिछले साल मई में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धरामैया और शिवकुमार के बीच कड़ी टक्कर थी। कांग्रेस शिवकुमार को मनाने में सफल रही और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया। उस समय ऐसी खबरें थीं कि रोटेशनल सीएम के फॉर्मूले के आधार पर एक समझौता किया गया है, जिसके अनुसार ढाई साल बाद शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन पार्टी की ओर से आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई। शिवकुमार ने भी मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वकांक्षा को किसी से छिपा कर नहीं रखा है। जबकि सिद्धरामैया ने लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों से कांग्रेस के लिए समर्थन मांगा था, ताकि उनकी स्थिति मजबूत रहे। इस बीच, राज्य में उप मुख्यमंत्री की मांग पर कांग्रेस विधायक प्रियांक खरगे ने कहा, लोग कुछ भी दावा करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो वे चाहते हैं। लेकिन उन्हें सही मंच पर दावा करना चाहिए।

मीडिया में आने और दावा करने का क्या मतलब है? वे आलाकमान के पास जा सकते हैं और इसके बारे में बोल सकते हैं। मुझे भरोसा कि उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान किया जाएगा। लेकिन अगर आप सड़कों पर ऐसा करने जा रहे हैं, तो कोई भी इसकी परवाह नहीं करेगा। आप मुख्यमंत्री पद के लिए भी दावा कर सकते हैं। कोई भी इससे इनकार नहीं कर रहा है। हमारी पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र है। लेकिन दावा सही मंच पर किया जाना चाहिए।

बयान देने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा हूं

वहीं उप मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा मैं उन लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी कर रहा हूं, जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से जुड़े बयान दिए हैं। इंतजार कीजिए और देखिए मैं किसे नोटिस जारी करने जा रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के नेतृत्व वाली सरकार में नीट, नेट और शेयर बाजार भारत में सबसे बड़े घोटाले हैं और हमें संसद में बोलने की अनुमति नहीं थी। माइक बंद थे। हम बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा, जहां तक नीट का सवाल है। एनआरआई सीटें सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों को दी जानी चाहिए। हमारे राज्य में 20 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहे हैं। इससे कर्नाटक के एनआरआई छात्रों को भी फायदा होगा और कॉलेजों को भी फायदा होगा।

सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों पर दिया गया प्रशिक्षण : डीजीपी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। राज्य के डीजीपी आलोक मोहन ने कहा कि कर्नाटक के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नए आपराधिक कानूनों पर प्रशिक्षण दिया गया है, जो सोमवार को देश में लागू हुए। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) में वर्तमान सामाजिक वास्तविकताओं और आधुनिक समय के अपराधों को ध्यान में रखा गया है। नए कानूनों ने क्रमशः ब्रिटिश काल की भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह ली।

मोहन ने एक पोस्ट में कहा हमारे सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को, सभी 7 क्षेत्रों, 6 आयुक्त इकाइयों और 1063 पुलिस स्टेशनों में प्रशिक्षण दिया गया है और इस विषय पर प्रक्रिया जारी है। सोमवार से, सभी नई एफआईआर बीएनएस के तहत दर्ज की जाएंगी। हालांकि, पहले दर्ज किए गए मामलों पर उनके अंतिम निपटारे तक पुराने कानूनों के तहत मुकदमा चलता रहेगा। इसमें कहा गया कि नए कानून आधुनिक न्याय प्रणाली लेकर आए हैं, जिनमें जीरो एफआईआर, पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण, एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन और सभी जघन्य अपराधों के लिए अपराध स्थलों की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल हैं।

कानून व्यवस्था के लिए हुब्बल्ली पुलिस सदैव तत्पर: पुलिस आयुक्त

हुब्बल्ली/शुभ लाभ ब्यूरो।

कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री हुब्बल्ली द्वारा हुब्बल्ली धारवाड़ महानगर पुलिस आयुक्त आईपीएस अधिकारी रेणुका सुकुमार के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसको संबोधित करते हुए आयुक्त सुकुमार ने कहा कि हुब्बल्ली धारवाड़ महानगर में कानून व्यवस्था, यातायात और अपराध को रोकने के लिए महानगर पुलिस सदैव तत्पर रहती है। साथ ही संगठन के सदस्यों और जनता से निवेदन किया कि पुलिस की सहायता के लिए आप आगे आएं। आयुक्त ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास तौर पर बनाए गए चेन्नम्मा वाहिनी के बारे में बताया और साइबर क्राइम के प्रति जागरुक

रहने को कहा। अतिरिक्त सचिव महेंद्र सिंघी ने पुलिस आयुक्त से हुब्बल्ली श्री सिध्दारुढ़ स्वामीजी रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे पर प्रिपेड ऑटो और ओला टैक्सी सेवा चालू करवाने का निवेदन किया। साथ ही ट्रैफिक सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करने का आग्रह किया। इस दौरान पुलिस आयुक्त ने महिलाओं एवं सदस्यों ने पूछे गये प्रश्नों का समुचित उत्तर दिया। इसके अलावा उन्हें अनेक समस्याओं का समाधान और कानून के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर संस्था की ओर से आईपीएस रेणुका सुकुमार को सम्मानित किया गया। बैठक में पुलिस उपायुक्त, (कानून एवं व्यवस्था) कुशल चौकसे, पुलिस निरीक्षक (साइबर अपराध) बीके पाटिल एवं एसीपी यू.बी. चिक्कमठ उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष एसपी समशीमथ ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष प्रवीण अगाड़ी, एडिशनल सचिव महेंद्र सिंघी और पूर्व अध्यक्ष एमसी हिरेमथ सहित बड़ी संख्या में व्यापारी और जनता उपस्थित थे।

अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप बालटाल में उत्सव का माहौल

बालटाल मार्ग पर मधुर संगीत की तरह बहती हैं ठंडी हवाएं

सुरेश एस डुग्गर
जम्मू, 01 जुलाई।

अमरनाथ यात्रा की शुरुआत के साथ ही गंदरबल जिले में यात्रा के आधार शिविर बालटाल में उत्सव का माहौल है। सिंध नाले के किनारे बालटाल में स्थित आधार शिविर चौबीस घंटे चालू रहता है। हर रोज आधी रात के आसपास सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी में विशाल शिविर में चहल-पहल शुरू हो जाती है। देश के विभिन्न हिस्सों से यात्री बसों में सवार होकर 300 किमी लंबे श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग से बालटाल और पहलगाम आधार शिविरों की यात्रा करते हैं। कुछ चेकपॉइंट से गुजरने के बाद बालटाल आधार शिविर पहुंचने पर यात्री उत्सव के उत्साह का अनुभव कर रहे हैं। यात्रियों का स्वागत भजनों से भरपूर रौशनी और सजाए गए लंगरों से हो रहा है।

आधार शिविर में एक पूरा बाजार है जिसमें लंगर (सामुदायिक रसोई) और मुसलमानों द्वारा संचालित अस्थायी दुकानें हैं जो पूजा सामग्री और अन्य सामान बेच रहे हैं। यात्रियों का उत्साह बेस कैंप में पहुंचने और ठहरने के दौरान देखा जा सकता है। यात्री बेस कैंप में स्वतंत्र रूप से घूमते हुए, तस्वीरें खींचने और बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की चीजें खरीदने में व्यस्त दिखाई देते हैं। यात्रियों के लिए लगाए गए लंगरों में भारी भीड़ देखी गई। कई यात्रियों ने कहा कि वे यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उनके मन में बिल्कुल भी डर नहीं है। अहमदाबाद से आए यात्री कमल मिश्रा कहते थे कि हमारे मन में कोई डर नहीं है। यहां सरकार और प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम संतोषजनक हैं।

बालटाल में आम तौर पर कश्मीरी मुस्लिम दिखाई देते हैं, जो अमरनाथ यात्रियों के लिए स्थानीय स्तर पर सेवा

प्रदान करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं। स्थानीय सेवा प्रदाताओं में ज्यादातर वे लोग शामिल हैं, जिन्होंने यात्रियों के लिए अपने कियोस्क और टेंट लगाए हैं और उनका बेसब्री से इंतजार करते देखे जाते हैं। दिल्ली से आए यात्री सुरेश शर्मा कहते हैं, मैं यात्रा को लेकर उत्साहित हूं। मैं दूसरी बार यहां आ रहा हूं, लेकिन मंदिर की हर यात्रा मुझे उत्साहित करती है। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए बालटाल बेस कैंप से निकलने के बाद, यात्री 14 किलोमीटर का छोटा रास्ता अपनाते हैं, जिसमें ढलान बहुत ज्यादा है और चढ़ाई करना मुश्किल है।

यह बालटाल से शुरू होता है और गुफा मंदिर तक पहुंचने से पहले डोमियाल, बरारी और संगम से होकर गुजरता है। यात्री पैदल या हेलिकॉप्टर से गुफा मंदिर तक पहुंचते हैं, ज़्यादातर यात्री टट्टू की सवारी या पालकी पसंद करते हैं। स्थानीय मुसलमान यात्रियों को टट्टू या अपने कंधों पर उठाकर ले जाते हुए देखे जाते हैं। कश्मीरी मुसलमान पैदल यात्रियों को पहाड़ी के छोर पर ही रहने और घाटी के छोर पर न जाने की सलाह देते हुए देखे जाते हैं, नहीं तो वे गिर जाएंगे। रास्ते में, कई चाय की दुकानें हैं, जिनमें लगभग हर दुकान के होर्डिंग्स पर शिव लिंगम की तस्वीरें लगी हुई हैं।

बालटाल मार्ग पर ठंडीएं हवा मधुर गीत की तरह बहती हैं। सीटी की आवाज घोलने वाली ठंडी हवा सफेद ग्लेश्यिर को काट कर रख देती है तो इंसानी चेहरे की क्या हालत होगी। लेकिन इन सबके बावजूद ठंडी हवा के मधुर गीत जब कानों में तरंग छेड़ते हैं तो यूं लगता है किसी फिल्म का दृश्य आंखों के सामने हो। और 15 किमी लम्बा मार्ग 210 मिनटों के भीतर हवाओं के गुनगनाते गीत व संगीत में ऐसे गुजर जाता है जैसे किसी को कोई खबर न होती हो। यह सचमुच किसी फिल्म की कथा नहीं है बल्कि उस मार्ग की कहानी है जिसे कश्मीर में आतंकवाद फैलने के 7 साल के बाद अमरनाथ की पवित्र गुफा तक जाने के लिए खोला गया था। इस दौरान भी यह मार्ग खुला तो रहा था परंतु नागरिकों को इसके प्रयोग की अनुमति सुरक्षा कारणों से नहीं दी जाती रही थी जो गुफा तक पहुंचने का सबसे छोटा मार्ग माना जाता है। और अब परिणाम यह है इसके खोलने का कि यात्रा पर आने वाले इसी मार्ग से गुफा तक जाने और आने को प्राथमिकता देते रहे हैं। अमरनाथ गुफा तक पहुंचने का यह एकमात्र छोटा रास्ता प्रयोग करने वालों के लिए आसानी यह है कि वे एक ही दिन में गुफा तक जाकर वापस श्रीनगर लौट सकते हैं।

श्रद्धा में विकलांगता बाधा नहीं बनती

जम्मू, 01 जुलाई (ब्यूरो)। राजस्थान के जयपुर के आनंद सिंह, जिन्होंने 2002 में एक दुर्घटना में अपने दोनों पैर खो दिए थे, इस साल 13वीं बार भगवान शिव के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की यात्रा कर रहे हैं। भगवान शिव के भक्त आनंद सिंह पवित्र गुफा मंदिर में पूजा करने के लिए 3,880 मीटर की ऊंचाई पर अमरनाथ की अपनी 13वीं यात्रा पर निकले हैं। आनंद बताते हैं, मैंने 2010 में बाबा के दरबार में आना शुरू किया। हालांकि उन्होंने वर्ष 2013 में केदारनाथ में बाढ़ के कारण और दो साल तक जब कोविड महामारी के कारण इसे निलंबित कर दिया गया था, तब वे इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे। बाइस साल पहले एक ट्रेन दुर्घटना में अपने दोनों पैर गंवाने वाले सिंह एक ट्रक के टायर में बैठते हैं और अपने हाथों का घसीट कर चलते हैं। वह 2015 तक ऐसा करते रहे हैं लेकिन कुछ शारीरिक कमजोरी होने के बाद उन्होंने पालकी (एक पालकी) या घोड़े पर यात्रा करना शुरू कर दिया। सिंह कहते हैं कि पहले चार-पांच साल तक मैं अपने हाथों से

खुद को घसीटता रहा, लेकिन अब मेरे लिए यह मुश्किल हो गया है। मैं पालकी में यात्रा करता हूं। भगवान शिव के साथ अपना विशेष रिश्ता बताते हुए आनंद सिंह कहते हैं, यह बंधन हर साल मजबूत होता जा रहा है। इसलिए मैं यहां आता हूं। पवित्र गुफा में पूजा-अर्चना करके मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मुझे यहां वास्तव में सुकून मिलता है और भोले बाबा के दर्शन करने के बाद मुझे जो आंतरिक संतुष्टि महसूस होती है, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अपनी विकलांगता के बावजूद वह खुद को वंचित महसूस नहीं करते। वे कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कुछ लोग मेरे प्रयास को सकारात्मक रूप से देखते हैं, जबकि कुछ अन्य मेरी आलोचना करते हैं। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। सिंह ने पवित्र गुफा मंदिर में तब तक जाने का संकल्प लिया है, जब तक वह खुद ऐसा कर सकते हैं। सिंह ने कहा कि वह चाहते हैं कि पूरी दुनिया में लोग पूरी तरह शांति और सद्भाव के साथ रहें और खुशहाल जीवन जिएं।

जेफरीज की रिपोर्ट : भारत डेस्टिनेशन वेडिंग का सबसे बड़ा केंद्र

भारत में हर साल होती हैं एक करोड़ शादियां

नई दिल्ली, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा विवाह स्थल है। यहां हर साल 80 लाख से एक करोड़ शादियां होती हैं, जबकि चीन में 70-80 लाख और अमेरिका में 20-25 लाख विवाह होते हैं। खास बात है कि आम देशवासी शिक्षा (स्नातक तक) की तुलना में विवाह समारोह पर दोगुना खर्च करते हैं। अमेरिकी जैसे देशों में यह खर्च शिक्षा की तुलना में आधे से भी कम है।

ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय विवाह उद्योग का आकार करीब 10 लाख करोड़ रुपए का है। यह अमेरिका के विवाह उद्योग का लगभग दोगुना है। हालांकि, चीन की तुलना में छोटा है। अमेरिका में विवाह उद्योग का आकार 5.84 लाख करोड़ रुपए (70 अरब डॉलर) का है, जबकि चीन में यह 14.2 लाख करोड़ (170 अरब डॉलर) का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय शादी कई दिनों तक चलती हैं और साधारण से लेकर बेहद भव्य तक होती हैं। इसमें क्षेत्र, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

भारत में एक शादी पर औसतन 12.50 लाख रुपए (15,000 डॉलर) खर्च होते हैं। यह रकम प्रति व्यक्ति या घरेलू आय का कई गुना है। शादियों में होने वाले कुल खर्च में दुल्हन के आभूषणों की हिस्सेदारी आधे से अधिक होती है। लग्जरी सेगमेंट में दुल्हन के लहंगों में भारी जटिल काम शामिल होता है। कुछ मामलों में इन लहंगों का वजह 10 किलोग्राम तक भी हो सकता है।

खर्चीली शादियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों के बावजूद विदेशी स्थानों पर होने वाली आलीशान शादियां भारतीय वैभव को प्रदर्शित करती रहती हैं। जेफरीज ने कहा, भारत में शादियां भव्य होती हैं। इनमें कई तरह के समारोह और खर्च होते हैं। शादियों के सीजन में आभूषण समेत कई उद्योगों में बिक्री बढ़ जाती है। शादियों के सीजन में आभूषण और परिधान जैसी श्रेणियों में खपत बढ़ती है। अप्रत्यक्ष रूप से ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को लाभ मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में खपत श्रेणी में शादियों का दूसरा स्थान है। अगर शादी एक श्रेणी होती, तो खाद्य और किराना के बाद दूसरी सबसे बड़ी खुदरा श्रेणी होती। भारतीय खाद्य और किराना उद्योग का आकार 56.8 लाख करोड़ रुपए (681 अरब डॉलर) है।

फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए दो जुलाई से आवेदन कर सकेंगे किसान

लखनऊ, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

अन्नदाता किसान मोदी-योगी की डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता में हैं। किसानों के लिए चलाई गई अनेक योजनाओं के माध्यम से सरकार इसे साबित भी कर रही है। इस कड़ी में अब प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू, (सी.आर.एम.) योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अन्नदाता किसानों को अनुदान का अवसर उपलब्ध कराया गया है। इसके तहत दो जुलाई से किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह प्रक्रिया 16 जुलाई तक चलेगी।

प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेड्ज्यू (सी.आर.एम.) योजना के तहत कृषि यंत्रों-सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम (सुपर एस.एम.एस), हैप्पी सीडर/स्मार्ट सीडर, सुपर सीडर, पैडी स्ट्रा चोपर/श्रेडर/मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लैशर, सरफेस सीडर, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एम.बी. प्लाऊ, बेलिंग मशीन, स्ट्रा रेक, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, क्रॉप रीपर ट्रैक्टर माउंटेड/सेल्फ प्रोपेल्ड, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर कम बाइंडर एवं कस्टम हायरिंग सेंटर के आवेदन के लिए दो जुलाई को दोपहर 12 बजे से 16 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक बुकिंग कर सकते हैं। विभागीय दर्शन पोर्टल पर यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए बुकिंग किए जाने के लिए विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। आवेदक द्वारा एक मोबाइल नंबर से ही आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए अपना अथवा ब्लड रिलेशन सदस्यों के मोबाइल से ही आवेदन मान्य होगा, जिसकी सत्यापन के समय पुष्टि भी की जाएगी।

कृषक परिवार (पति अथवा पत्नी में कोई एक) द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजना के तहत निर्धारित यंत्रों में से एक या एक से अधिक प्रकार के यंत्र लिए जा सकते हैं। फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों पर अधिकतम 50 फीसदी व कस्टम हायरिंग सेंटर पर अधिकतम 80 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त होगा। योजना के तहत फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों तथा कस्टम हायरिंग सेंटर हेतु ग्रामीण उद्यमी एवं एफपीओ लाभार्थी होंगे।

ई-लॉटरी हेतु स्थल, तिथि एवं समय की जानकारी आवेदकों के मध्य संबंधित जनपदीय उप कृषि निदेशक द्वारा विभिन्न माध्यमों से सूचना दी जाएगी। निर्धारित समय के भीतर लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी समिति के समक्ष विभागीय पोर्टल पर ई-लॉटरी के माध्यम से ब्लॉकवार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा। ई-लॉटरी व्यवस्था में लक्ष्य के अनुरुप चयनित किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या के अतिरिक्त लक्ष्य का 50 प्रतिशत तक क्रम के अनुसार प्रतीक्षा सूची भी तैयार होगी। लक्ष्य की पूर्ति न होने पर ई-लॉटरी द्वारा तैयार प्रतीक्षा सूची के क्रम में लाभार्थी का चयन किया जाएगा।

आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। लक्ष्य अवशेष न रहने पर एवं ई-लॉटरी में चयनित न होने वाले किसानों की जमानत धनराशि वापस कर दी जाएगी। दस हजार एक रुपए से लेकर एक लाख रुपए के कृषि यंत्रों के अनुदान के लिए जमानत धनराशि 2500 रुपए व एक लाख से अधिक अनुदान के कृषि यंत्रों के लिए जमानत धनराशि पांच हजार रुपए होगी। लाभार्थियों का चयन/बुकिंग टोकन कंफर्म होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद यंत्रों की फोटो, सीरियल नंबर एवं संबंधित अभिलेख 30 दिन में अपलोड करना होगा। कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 45 दिन का समय दिया जाएगा। विभाग में सूचीचद्ध कृषि यंत्र निर्माताओं में से किसी से भी क्रय करने की स्वतंत्रता होगी। इन कंपनियों के पोर्टल पर अपलोड यंत्र का क्रय करने पर ही अनुदान अनुमन्य होगा। निर्धारित समय में यंत्र न खरीदने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा। कृषि यंत्रों के खरीदने के लिए फर्मों को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी के स्वयं के खाते से ही किए जाने पर ही अनुदान का भुगतान होगा।

महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी तय

भाजपा प्रत्याशियों में पंकजा मुंडे का भी नाम

मुंबई, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय चुनाव समिति ने सोमवार को महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। जिन नामों की घोषणा की गई है, उनमें पंकजा मुंडे, योगेश तिलेकर, परिणय फुके, अमित गोरखे और

सदाभाऊ खोत शामिल हैं।

खास बात ये है कि भाजपा ने पंकजा मुंडे पर एक बार फिर भरोसा जताया है। पंकजा ने बीड से लोकसभा चुनाव चुनाव लड़ा था। हालांकि, वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार) के बजरंग सोनवाने से 6000 वोटों के मामूली अंतर से हार गई थीं। उनके चार समर्थकों ने उनकी हार के बाद आत्महत्या कर ली थी। राज्य की 11 विधान परिषद सीट पर 12 जुलाई को मतदान होगा। उसी दिन नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। महाराष्ट्र भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व को 11 नामों की सूची भेजी थी। जिनमें से पांच नाम पर पार्टी ने मुहर लगाई है।

मानहानि मामले में मेधा पाटकर को पांच महीने की जेल

नई दिल्ली, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

दिल्ली के साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर को पांच महीने की साधारण कारावास की सजा सुनाई है। यहा सजा उन्हें तत्कालीन केवीआईसी अध्यक्ष वीके सक्सेना (अब दिल्ली के उपराज्यपाल) द्वारा दायर मानहानि मामले में सुनाई गई है। कोर्ट ने मेधा पाटकर को वीके सक्सेना को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। साकेत कोर्ट ने यह भी कहा कि मेधा पाटकर की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को देखते हुए उन्हें अधिक सजा नहीं दी जा रही है। न्यायाधीश ने कहा कि सजा पर 30 दिन तक रोक रहेगी। मेधा पाटकर ने कहा, हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की है। हम सिर्फ अपना काम करते हैं। हम कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे।

रामलला को लगाया जा रहा रत्नजड़ित चंदन का तिलक

अयोध्या, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

राममंदिर में विराजमान बालक राम की सेवा रामानंदीय पद्धति से पूरे वैभव के साथ की जा रही है। रामलला का श्रृंगार रोजाना सोने-चांदी से जड़ित आभूषणों से किया जाता है। इसी क्रम में रामलला के माथे पर रत्नजड़ित चंदन का तिलक लगाया जा रहा है। यह तिलक अलग से बनवाया गया है, रोजाना इसे रामलला के माथे पर लगाया जाता है। हालांकि इस व्यवस्था से पुजारी खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि चंदन घिसकर माथे पर तिलक लगाने की परंपरा ज्यादा उचित है।

राममंदिर के एक पुजारी ने बताया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के माथे पर रोजाना चंदन घिसकर फिर तिलक किया जाता था। इसमें केसर आदि भी मिला होता था। इससे रामलला का मुखमुंडल खिल उठता था, लेकिन अब रामलला के माथे पर रत्नजड़ित चंदन लगाया जाता है। हालांकि उत्सव मूर्ति के रूप में विराजमान रामलला समेत चारों भाईयों को चंदन घिसकर ही तिलक लगाया जाता है। इसके पीछे का कारण पुजारी ने स्पष्ट नहीं किया लेकिन इतना जरूर कहा कि चंदन घिसकर रामलला के माथे पर तिलक लगाने से रोका गया है।

राममंदिर में प्रशिक्षित पुजारियों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए पिछले छह माह से 20 पुजारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। इन सभी पुजारियों को रामलला की सेवा-पूजा में शामिल कर उन्हें पूजन की आचार संहिता समझाने का काम रामलला के मुख्य अर्चक कर रहे थे। अब इनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इन्हें एक-दो दिन में प्रमाण पत्र देकर राममंदिर की पूजा में लगाया जाएगा। राममंदिर परिसर में बनने वाले अन्य मंदिरों की पूजा के लिए इन्हीं में से पुजारी नियुक्त किए जाएंगे।

खबरें जो सोच बदल दे
शुभ लाभ
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

आयुष्मान आरोग्य मंदिर में उपलब्ध होंगी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं

लखनऊ, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि योगी सरकार लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक के बाद एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर रही है।

सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि अब तक प्रदेश के 256 स्वास्थ्य इकाइयों को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड (एन्क्वास) सर्टिफिकेट मिल चुका है। यह प्रमाण पत्र प्रदेश की स्वास्थ्य इकाइयों को गुणवत्तापूर्ण इलाज, स्वास्थ्य के मानकों को पूरा करने एवं उस पर खरा उतरने पर मिला है।

योगी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लोगों को घरों के नजदीक ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज मिलें। साथ ही प्रदेश की जनता अपनी गाढ़ी कमाई निजी अस्पतालों या अप्रशिक्षित चिकित्सकों की क्लिनिक में इलाज पर न खर्च कर अपने परिवार के पालन-पोषण और खुशहाली पर खर्च कर सके। इतना ही नहीं योगी सरकार ने वर्ष 2026 तक प्रदेश की सभी स्वास्थ्य इकाइयों को एन्क्वास सर्टिफिकेशन के दायरे में लाने का लक्ष्य रखा है, जबकि दिसंबर 2025 तक प्रदेश की 50 प्रतिशत स्वास्थ्य इकाइयों को एन्क्वास प्रमाण पत्र से लैस करने का लक्ष्य रखा गया है।

एनएचएम के महाप्रबंधक डॉ. निशांत कुमार जायसवाल ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय केवल उन्हीं स्वास्थ्य इकाइयों को यह प्रमाणपत्र प्रदान करता है जो मरीजों के इलाज और देखभाल के हर मानक को पूरा करते हैं।

अगले तीन महीने में इतनी ही और स्वास्थ्य इकाइयों को एन्क्वास के दायरे में लाने के हरसम्भव प्रयास जारी हैं। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर (आईएसक्यूयूए) द्वारा प्रमाणित होने के कारण एन्क्वास प्रमाणित स्वास्थ्य इकाइयां अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा कर रही हैं। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि 256 एन्क्वास प्रमाणित स्वास्थ्य इकाइयां लोगों को घरों के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहीं हैं, इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ा है।

एन्क्वास के प्रमुख क्लीनिकल सेवाओं के तहत पीएचसी में क्लीनिकल सेवाओं की गुणवत्ता को मापते हैं। इसमें परामर्श, प्रवेश, मूल्यांकन, देखभाल की निरंतरता, नर्सिंग देखभाल, दवा सुरक्षा, मानक उपचार दिशा निर्देशों का उपयोग, आपातकालीन सेवाएं, प्रयोगशाला सेवाएं, चिकित्सा रिकॉर्ड और डिस्चार्ज प्रक्रिया के मानक शामिल हैं।

प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसवोत्तर देखभाल, नवजात देखभाल, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नैदानिक सेवाओं से संबंधित नैदानिक प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। संक्रमण नियंत्रण क्षेत्र के तहत हाथ धोने की सुविधाएं, व्यक्तिगत सुरक्षा, उपकरण प्रसंस्करण, पर्यावरण नियंत्रण और बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन का मूल्यांकन होता है। एन्क्वास के मानक गुणवत्ता प्रबंधन के तहत गुणवत्ता टीम, आंतरिक, वाह्य गुणवत्ता आश्वासन, रोगी संतुष्टि सर्वेक्षण और मानक संचालन प्रक्रियाओं से संबंधित चार मानक शामिल हैं।

एन्क्वास के मानकों पर खरा उतरने वाले बहराइच के कैसरगंज ब्लॉक के परसेंडी आयुष्मान आरोग्य मंदिर के प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश ने बताया कि जब से इसे एन्क्वास सर्टिफिकेट मिला है, तब से यह केंद्र बड़े-बड़े निजी अस्पतालों को भी मात दे रहा है। सभी मानकों को पूरा करने वाला यह जिले का पहला स्वास्थ्य उपकेंद्र है। केंद्र को अगस्त 2023 में न केवल भारत सरकार के एन्क्वास प्रमाणन से सम्मानित किया गया, बल्कि बदलाव में भागीदार बने। साथ ही यहां के स्वास्थ्य कर्मियों को राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया। परसेंडी ग्राम के साकिर अली ने बताया कि पहले गांव के लोग प्रसव व दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जिला मुख्यालय, सीएचसी या प्राइवेट अस्पताल जाते थे। अब परसेंडी में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने से न सिर्फ गांव के गरीब-अमीर बल्कि दूसरे ब्लॉक के लोग भी यहां आते हैं। इस केंद्र की गुणवत्ता ऐसी ही बनी रहे इसके लिए हम सभी लोग भी साफ़-सफाई का पूरा ध्यान रखते हैं।

वाराणसी के पहले एन्क्वास प्रमाणित आयुष्मान आरोग्य मंदिर खरगरामपुर के बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप चौधरी ने बताया कि चार साल पहले सेंटर (जच्चा-बच्चा केंद्र) पर एएनएम द्वारा नियमित टीकाकारण, प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) और परिवार नियोजन परामर्श सेवाएं दी जाती थीं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों से वर्ष 2022 से सेंटर पर ओपीडी, प्रसव संबंधी सुविधाएं, मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, किशोर-किशोरी स्वास्थ्य सेवाएं, संचारी व गैर संचारी रोग संबंधी सेवाएं, नियमित टीकाकारण, परिवार नियोजन सेवाएं व परामर्श के साथ 14 प्रकार की पैथालोजी जांच, टेली मेडिसीन सुविधा लगातार प्रदान की जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) सीमा देवी, एएनएम और आशा कार्यकर्ता इन सेवाओं को घर के नजदीक ही प्रदान करने में बेहतर भूमिका निभा रही हैं।

गोरखपुर की उपलब्धियों में जुड़ा स्वर्णिम अध्याय

गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई शुरू

प्रवेश परीक्षा के बाद कक्षा 6 और 9 में 75-75 सीटों पर हुआ है दाखिला

गोरखपुर, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

पहली जुलाई की तारीख गोरखपुर की उपलब्धियों में स्वर्णिम अध्याय जोड़ने वाली रही। इस तिथि से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट गोरखपुर सैनिक स्कूल में पढ़ाई शुरू हो गई। प्रवेश परीक्षा के जरिये सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में 75-75 सीटों पर दाखिला पहले ही हो गया था। गोरखपुर सैनिक स्कूल का औपचारिक उद्घाटन भी इसी माह होने की उम्मीद है।

सैनिक स्कूल में पहले सत्रारंभ के पहले दिन प्रधानाचार्य ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नारियल फोड़कर विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। गोरखपुर का सैनिक स्कूल खाद कारखाना परिसर में आवंटित 50 एकड़ भूमि पर बना है। डेढ़ सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले इस स्कूल का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 जुलाई 2021 को किया था। 'युवाओं को शिक्षा, देश की रक्षा' के ध्येय से निर्माणाधीन इस शैक्षिक प्रकल्प में कक्षा 6 से 12 तक बालक-बालिकाओं को आवासीय व्यवस्था के तहत शिक्षा प्रदान करने का शुभारंभ सोमवार को हुआ। यहां छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग कैंपस हैं। स्कूल का प्रशासनिक भवन प्राचीन भारतीय संस्कृति व परंपरा का दर्शन कराने वाला बना है। सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों के खेलकूद की गतिविधियों के लिए खेलों के कई कोर्ट व मैदान भी विकसित हुए हैं हैं।

गोरखपुर का सैनिक स्कूल सीएम योगी की उच्च प्राथमिकता वाली परियोजनाओं में सम्मिलित है। इसके शिलान्यास के बाद भी वह कई बार इसके निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण करने आते रहे हैं। फरवरी माह में जब वह सैनिक स्कूल का निरीक्षण करने आए थे, तभी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जुलाई सत्र से यहां पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए। यही नहीं, वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट में इस सैनिक स्कूल के लिए सरकार ने वित्तीय प्रावधान भी इसीलिए किए था कि सत्र संचालन में किसी प्रकार की बाधा न आए। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप गोरखपुर सैनिक स्कूल में एक जुलाई से नियमित कक्षाओं का संचालन प्रारम्भ हो गया है।

पानी की टंकी गिरने पर तीन फर्मों पर एफआईआर, तीन निलंबित

लखनऊ/मथुरा, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

सरकारी कार्य में लापरवाही को लेकर सख्त योगी सरकार ने फिर एक बार बड़ी कार्रवाई की है। मथुरा में रविवार को मथुरा पेयजल पुनर्गठन योजना थ्रू गोकुल बैराज पार्ट-1 के अन्तर्गत कृष्णा विहार कॉलोनी, मथुरा में 2500 किली./20 मीटर क्षमता वाली पानी की टंकी के क्षतिग्रस्त होकर गिरने की घटना को सीएम योगी ने गंभीरता से लिया है। सीएम योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा सोमवार को दोषी अधिकारियों व अनुबन्धित फर्मों के विरूद्ध सख्त एक्शन लिया गया है। साथ ही मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी गठित की गई है।

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा तीन फर्मों (मेसर्स एसएम कान्स्ट्रक्शन, मेसर्स बनवारी और मेसर्स त्रिलोक सिंह रावत) एवं अन्य कर्मियों के विरूद्ध कोतवाली, मथुरा में धारा 304 व 338 के अधीन एफआईआर दर्ज कराई गई है। इसके अतिरिक्त योजना पर तैनात सहायक अभियंता ललित मोहन, जूनियर इंजीनियर बीरेन्द्र पाल एवं रविन्द्र प्रताप सिंह को निलम्बित करते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त तत्कालीन सहायक अभियंता दिव्यांशु कुमार सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक जांच के निर्देश दिए गए हैं।

मामले में अधिशासी अभियंता महराज सिंह, कुमकुम गंगवार, दयानन्द शर्मा एवं तत्कालीन सहायक अभियंता राम प्रकाश यादव पर प्रशासनिक नियंत्रण उप्र जल निगम (ग्रामीण) का होने के कारण इनके विरूद्ध तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रबंध निदेशक, उप्र जल निगम (ग्रामीण) को पत्र लिखा गया है।

इसके अतिरिक्त प्रकरण में तकनीकी कमियों की जांच के लिए मुख्य अभियंता (गाजियाबाद क्षेत्र), उप्र जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन भी किया गया है। जांच समिति घटना की जांच के लिए आईआईटी दिल्ली या आईआईटी कानपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से सहयोग प्राप्त कर आख्या उपलब्ध कराएगी।

अनुप्रिया की चिट्ठी, कुर्मी वोट बैंक खिसकने की घबराहट तो नहीं

लखनऊ, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने ओबीसी व एसटी के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती को लेकर बेअवसर सवाल उठाकर भले ही सियासी सुर्खियां बटोरने का प्रयास किया है, लेकिन इसके पीछे कुर्मी वोट बैंट के खिसकने की घबराहट को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि खुद को अपनी जाति का एकमात्र नेता मान चुकीं अनुप्रिया को इस बार लोकसभा चुनाव में कड़े संघर्ष में बमुश्किल जीत मिली थी, उससे वह काफी दबाव में हैं।

दरअसल, लोकसभा चुनाव में अपनी परंपरागत सीट पर अनुप्रिया को बड़ी मशक्कत और कड़े संघर्ष में जीत मिली थी, वहीं, राबर्टगंज सीट उनके हाथ से निकल गई। इसके अलावा अनुप्रिया द्वारा एक दर्जन से अधिक सीटों पर कुर्मी जाति का प्रभाव होने का दावा किया जा रहा है, उनमें से अधिकांश सीटों पर भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। भाजपा द्वारा परिणामों की समीक्षा में यह बात सामने आने के बाद से ही अनुप्रिया एनडीए में अपनी साख बचाने को लेकर परेशान थीं।

ये अलग बात है कि कुर्मी बहुल सीटों पर हार के बावजूद भी भाजपा नेतृत्व ने उनको न सिर्फ केंद्र में फिर से मंत्री बनाया, बल्कि उन्हें वह अहमियत भी दी है, जो पहले था।इसके बावजूद अनुप्रिया द्वारा ओबीसी-एसटी वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर भर्ती पर सवाल उठाना भाजपा के लिए हैरानी का सबब बन गया है। अनुप्रिया के इस सियासी कदम का उन्हें आगे क्या फायदा होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने इस मुद्दे को उछालकर अपनी बिरादरी पर कमजोर होती पकड़ को फिर से मजबूत करने की कोशिश की है। वहीं, दूसरी ओर से अनुप्रिया के इस कदम को दबाव की राजनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है।

चुनाव परिणाम में कुर्मी वोट बैंक के खिसकने के बाद से ही अनुप्रिया को यह चिंता सताने लगी थी कि अगर एक बार वोट बैंक खिसका तो उसे दुबारा वापस पाना पार्टी के लिए कड़ी चुनौती होगी। इसलिए उन्होंने आरक्षित पदों पर भर्ती को लेकर सवाल उठाकर एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। हालांकि भर्ती आयोग के नियमावली के आधार पर अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने सरकार की ओर से अनुप्रिया के पत्र का जवाब भेजकर स्थिति को साफ कर दिया है। फिर भी उनके इस सियासी पैंतरे को लेकर चर्चा थम नहीं रही है। माना जा रहा है कि बिना सही तथ्यों से अवगत हुए ऐसा मुद्दा उठाना अनुप्रिया की बड़ी सियासी चूक है।

भाजपा खेमा भी अब अनुप्रिया द्वारा पत्र लिखने के पीछे की वजहों की तलाश में जुटा गया है। दरअसल, भाजपा खेमे में इस बात की जोरदार चर्चा है कि अनुप्रिया ने यह कदम अनायास ही नहीं उठाया है। इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। वह हाथ किसका है, इसका पता लगाया जाएगा। यह भी माना जा रहा है लोकसभा चुनाव में चुनाव जीतने वाले दो मंत्रियों के स्थान पर प्रदेश मंत्रिमंडल में होने वाले विस्तार और एमएलसी के रिक्त पदों पर चुनाव को देखते हुए ही अनुप्रिया ने यह कदम उठाया है। जिससे प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया जा सके। वह पहले से ही प्रदेश सरकार में अपने कोटे से एक और मंत्री बनाने का मुद्दा उठाती रही हैं।

दरअसल, हाल में ही सपा सांसद और कुर्मी चेहरा लालजी वर्मा ने हाल में ही एसजीपीजीआई की भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया था। एसजीपीजीआई में जिस डॉ. सर्वेश कुमार चौधरी का मुद्दा उठा है, वह लालजी वर्मा के रिश्तेदार हैं। सोशल मीडिया पर वर्मा द्वारा उठाए गया यह मुद्दा गरम हुआ तो इससे अनुप्रिया पर भी दबाव बढ़ गया। माना जा रहा है कि उनको यह लगा कि कहीं इस मुद्दे के जरिए लालजी वर्मा कुर्मी बिरादरी में उनके लिए मुश्किल न खड़ी कर दें। लालजी वर्मा और अनुप्रिया एक ही बिरादरी की हैं। दोनों इस मुद्दे के जरिए बिरादरी का वोटबैंक अपने पाले में करने की जुगत में लगे हैं।

2500 सोलर मास्ट लाइटिंग सिस्टम से लैस होंगे प्रदेश के कई जिले

लखनऊ, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार प्रदेश में सौर ऊर्जा व स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रसार को बढ़ाने व आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता लाने के भी विभिन्न प्रयास कर रही है। ऐसे में, प्रदेश के विभिन्न जिलों को सौर ऊर्जा चालित सोलर मास्ट लाइटिंग सिस्टम से लैस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

उल्लेखनीय है कि सीएम योगी की मंशा अनुसार उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की गई थी। इस कार्ययोजना को क्रियान्वित करते हुए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा अभिकरण (यूपीनेडा) ने प्रदेश के विभिन्न जिलों को 2500 सोलर मास्ट लाइटिंग से लैस करने के लिए ई-निविदा माध्यम के जरिए एजेंसी निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के पूरा होने पर कार्य प्राप्त करने वाली एजेंसी को 4 माह के भीतर 29.78 करोड़ रुपए की लागत से इन लाइट्स की सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, व कमीशनिंग प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। इन कार्यों को अतिरिक्त, लैंड बैंक मैनेजमेंट पोर्टल व विभिन्न स्कीमों को बढ़ावा देने के लिए आईवीआर तथा डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम के भी विकास कार्य पर यूपीनेडा फोकस कर रही है।

योजना के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों की चयनित साइट्स

पर सोलर पीवी व्हाइट एलइडी लाइट हाई मास्ट लाइट सिस्टम को लगाया जाएगा। ये सौर ऊर्जा चालित मास्ट लाइट्स कई मायनों में विशिष्ट हैं। यह लिथियम फेरो फॉस्फेड बैटरी बेस्ड सिस्टम होगा जो 12.8 वोल्ट कैपेसिटी पर कार्य करेगा और व्हाइट लाइट होने के बावजूद यह अल्ट्रा वॉयलेट रेज का एमीशन नहीं करेगा। यह 135 ल्यूमेंट प्रतिवाट के हिसाब से प्रकाश उत्पन्न करेगा। यानी, आउटडोर्स में ये लाइटें प्रकाश तो अच्छा उत्पन्न करेंगी ही साथ ही जीरो से लेकर 60 डिग्री तक के तापमान में भी यह आसानी से संचालित हो सकेंगीं। इन लाइटों को लगाने वाली एजेंसी द्वारा न केवल इनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगी बल्कि 5 वर्ष के वारंटी पीरियड के अंतर्गत संचालन व रखरखाव की प्रक्रिया को भी सुनिश्चत करेगी।

यूपीनेडा द्वारा लैंड बैंक मैनेजमेंट एप्लिकेशन के विकास के लिए भी कार्य शुरू कर दिया गया है। इस क्रम में, यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को जिम्मा सौंपा गया है जो अपने यहां इंपैनल्ड सॉफ्टवेयर डेवलमेंट एजेंसी के जरिए इस कार्य को पूर्ण कराएगी। कार्य के पूरा होने के उपरांत यूपीनेडा की वेबसाइट पर लैंड बैंक पोर्टल के जरिए आउटलाइन एप्लिकेशन मैनेजमेंट, रेगुलर कॉम्पलायंस, डॉक्यूमेंट्स व कॉन्ट्रैक्ट्स एसेसमेंट, टेनेंट व फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे तमाम कार्यों को बेहतर तरीके से पूरा कर सकेगा। साथ ही, हितधारकों के साथ संवाद कायम करने में भी यह एक अच्छा माध्यम साबित होगा। यह एप्लिकेशन 3 टीयर बेस्ड सिस्टम पर आधारित होगी।

एक ओर, यूपीनेडा द्वारा लैंड बैंक मैनेजमेंट एप्लिकेशन के विकास की प्रक्रिया शुरू की गई है, वहीं दूसरी ओर वह पीएम सूर्य घर योजना तथा पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए जेनरेटिव एआई बेस्ड आईवीआर व डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का विकास भी करवा रही है। यूपीनेडा द्वारा इस कार्य का जिम्मा भी यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) को ही सौंपा गया है। गौरतलब है कि यूपीनेडा द्वारा पराली को बायो फ्यूल में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे पोर्टल का विकास किया जा रहा है जहां किसान पराली बेच सकेंगे और यूपीनेडा इस पराली को बायो फ्यूल में कन्वर्ट कर सकेगा। इस पोर्टल के विकास के साथ ही अब जेनरेटिव एआई की मदद से आईवीआर व डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का भी विकास किया जा रहा है। यह पीएम सूर्य घर योजना तथा पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत लाभान्वितों को ट्रैक व मॉनिटर करने में सक्षम होगा

प्रदेश में तीन नए कानून लागू, बिना दिक्कत दर्ज होने लगी एफआईआर

लखनऊ, 01 जुलाई (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहले से ही 1 जुलाई यानी आज से लागू होने वाले तीन नए कानून को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई थी। ऐसे में सोमवार को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रदेश के विभिन्न थानों में एफआईआर दर्ज की गई। यह जानकारी डीजीपी प्रशांत कुमार ने साझा की।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में 1 जुलाई से लागू तीन नए कानून के तहत सबसे पहले अमरोहा और बरेली में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही वर्तमान में बिना किसी दिक्कत के सभी जगह एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसके अलावा आज प्रदेश के सभी थानों में इसको लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तीनों नए कानून को लागू करने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली गई। इसके तहत ट्रेनिंग और आवश्यक उपकरणों की खरीदारी कर ली गई थी। इतना ही नहीं टेक्निकल विंग द्वारा सभी स्थानों पर आवश्यक नेटवर्किंग को उपलब्ध करा दिया गया था। इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर और भारत सरकार की सामग्री भी शामिल है।

संपादकीय

आपातकाल के जिक्र से कांग्रेस को परेशानी क्यों?

संविधान की प्रति हाथ में लेकर 'संविधान हितैषी' होने का दावा करनेवाले कांग्रेस के नेता संविधान और लोकतंत्र की हत्या के उदाहरण 'आपातकाल' के जिक्र से परेशान क्यों हो रहे हैं? यदि सही अर्थों में उन्हें संविधान और लोकतंत्र की चिंता है, तब उन्हें आपातकाल के जिक्र पर नाराज होने की बजाय कहना चाहिए कि आपातकाल जैसी भयंकर गलती किसी को नहीं दोहरानी चाहिए। एक ओर कांग्रेसी नेता यह भी दावा करते हैं कि आपातकाल थोपने के लिए स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश से माफी माँगी थी और राहुल गांधी भी माफी माँग चुके हैं। यदि कांग्रेस मानती है कि आपातकाल संविधान और लोकतंत्र पर हमला था, तब उसकी 50वीं बरसी पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव रखने का विरोध क्यों किया जा रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर आपातकाल पर प्रस्ताव लाने का विरोध किया है। इसी प्रकार, जब राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया, तो उसके बाद से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर ही विवाद खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि 50 वर्ष पुराने मुद्दे को भाजपा क्यों उखाड़ रही है? यह अतार्किक सवाल है। इतिहास का जिक्र इसलिए भी होता है ताकि वर्तमान पीढ़ी उससे सीख ले सके। जब कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार संविधान को बदलना चाहती है और उन्होंने देश में अघोषित आपातकाल लगा रखा है, तब यह बताया जाना आवश्यक हो जाता है कि आपातकाल क्या होता है? पूर्व प्रधानमंत्री एवं कांग्रेस की प्रेरणा स्रोत इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल में किस प्रकार आम नागरिकों के संवैधानिक एवं मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे? किस तरह छोटी-छोटी बातों के लिए लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था? इंदिरा गांधी की जरा-सी आलोचना करने पर आलोचक को किस प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ती थीं? यह सब जब देश के सामने आएगा, तब ही तो पता चलेगा कि आपातकाल का अर्थ क्या होता है? अन्यथा कांग्रेस सहित विपक्षी दल 'अघोषित आपातकाल' का झूठा विमर्श खड़ा करते रहेंगे। संविधान लहराकर उसकी रक्षा करने का दावा करनेवालों ने किस प्रकार संविधान की आत्मा की हत्या की है, यह तथ्य भी तो जनता के सामने समय-समय पर आते रहने चाहिए। आपातकाल का लाभ लेकर कम्युनिस्टों के सहयोग से कांग्रेस ने संविधान की प्रस्तावना ही बदल दी, जिसे संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'संविधान की आत्मा' कहा था। इसके अतिरिक्त कितने ही संविधान संशोधन करके उसके मौलिक स्वरूप को बदलने का प्रयास कांग्रेस की सरकारों ने किया है। संविधान और लोकतंत्र पर जब भी बात होगी, तब इतिहास से अनेक उदाहरण जनता के सामने रखे जाएंगे, यह स्वाभाविक ही है। राजनीति में ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस दूसरों पर जो चाहे आरोप लगाए और दूसरा पक्ष उसे आईना भी न दिखाए। और फिर आपातकाल के संबंध में तो विशेष प्रसंग बन गया है। आपातकाल थोपे जाने की घटना को 50 वर्ष हो रहे हैं, ऐसे में विशेष प्रयोजन करके जनता को आपातकाल के पीड़ादायक अध्याय से परिचित कराना ही चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने जब संविधान पर बहस शुरू ही कर दी है तब संविधान और लोकतंत्र की हत्या से जुड़े इस दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय का जिक्र होना स्वाभाविक ही है। कांग्रेस को चाहिए कि वह आपातकाल के जिक्र पर परेशान होने की अपेक्षा धैर्य रखकर पश्चाताप करे।

'संविधान हितैषी' होने का दावा करनेवाले कांग्रेस के नेता संविधान और लोकतंत्र की हत्या के उदाहरण 'आपातकाल' के जिक्र से परेशान क्यों हो रहे हैं? यदि सही अर्थों में उन्हें संविधान और लोकतंत्र की चिंता है, तब उन्हें आपातकाल के जिक्र पर नाराज होने की बजाय कहना चाहिए कि आपातकाल जैसी भयंकर गलती किसी को नहीं दोहरानी चाहिए। एक ओर कांग्रेसी नेता यह भी दावा करते हैं कि आपातकाल थोपने के लिए स्वयं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश से माफी माँगी थी और राहुल गांधी भी माफी माँग चुके हैं। यदि कांग्रेस मानती है कि आपातकाल संविधान और लोकतंत्र पर हमला था, तब उसकी 50वीं बरसी पर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव रखने का विरोध क्यों किया जा रहा है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर आपातकाल पर प्रस्ताव लाने का विरोध किया है। इसी प्रकार, जब राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु ने अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया, तो उसके बाद से कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर ही विवाद खड़ा करने की कोशिशें कर रहे हैं। सवाल उठाया जा रहा है कि 50 वर्ष पुराने मुद्दे को भाजपा क्यों उखाड़ रही है? यह अतार्किक सवाल है।

राहुल को देशभर में निकाली गई यात्राओं एवं चुनाव प्रचार में निभाई सशक्त भूमिका ने मजबूती दी है

राहुल गांधी का कद भी बढ़ा एवं राजनीतिक कौशल भी

ललित गर्ग

दस वर्षों बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिला है। वैसे इस बार के चुनाव एवं चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद राहुल गांधी का न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनमें राजनीतिक कौशल एवं परिपक्वता भी देखने को मिल रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि वे प्रतिपक्ष नेता के पद के साथ न्याय करते हुए अपनी राजनीति को चमकायेंगे एवं रसातल में जा चुकी कांग्रेस को सुदृढ़ करेंगे। वैसे देखा गया है कि प्रतिपक्ष के नेता बनने वाले अधिकांश लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इसके लिये अभी लम्बा संघर्ष करना होगा, परिपक्व राजनीति एवं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को साबित करना होगा।

राहुल गांधी लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता बन गये हैं, यह उनका पहला संवैधानिक पद है, इससे पहले वे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इस बड़े पद के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जायेंगी। दस वर्षों बाद लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता का पद मिला है। वैसे इस बार के चुनाव एवं चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद राहुल गांधी का न केवल आत्मविश्वास बढ़ा है, बल्कि उनमें राजनीतिक कौशल एवं परिपक्वता भी देखने को मिल रही है, इससे यह प्रतीत होता है कि वे प्रतिपक्ष नेता के पद के साथ न्याय करते हुए अपनी राजनीति को चमकायेंगे एवं रसातल में जा चुकी कांग्रेस को सुदृढ़ करेंगे। वैसे देखा गया है कि प्रतिपक्ष के नेता बनने वाले अधिकांश लोग प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। लेकिन राहुल गांधी को इसके लिये अभी लम्बा संघर्ष करना होगा, परिपक्व राजनीति एवं देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को साबित करना होगा। निश्चित ही राहुल गांधी का कद बढ़ा है और अब वे स्वल्प समय में ही कद्दावर नेता की तरह राजनीति करने लगे हैं। राहुल को देशभर में निकाली यात्राओं एवं चुनाव प्रचार में निभाई सशक्त भूमिका ने मजबूती दी है। राहुल की राजनीति को चमकाने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की 'भारत जोड़ो यात्रा' के अलावा मणिपुर से मुंबई तक की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब प्रतिनेता के रूप में उनकी एक नई यात्रा शुरु हो रही है जो उन्हें नई राजनीतिक ऊंचाई दे सकती है। देश को 10 साल बाद राहुल गांधी के रूप में विपक्ष का नेता मिला है, जो संसदीय राजनीति के लिए एक अच्छी खबर है। इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी एवं जनता की आवाज को जोरदार तरीके से उठाने एवं सरकार की नीतियों-योजनाओं पर तीखी नजर रखने एवं प्रभावी सवाल उठाने की स्थितियों को बल मिलेगा। लेकिन विपक्ष की नुमाइंदगी का मतलब यह नहीं कि वह हर मामले में सत्ता पक्ष के खिलाफ हो, बल्कि यह है कि वह हमेशा जनता के साथ हो और उसकी ओर से मुद्दे उठाए। नेता प्रतिपक्ष पद से सरकार के साथ ही विपक्ष पर भी जवाबदेही का दबाव बढ़ता है। राहुल की सुविधाएं बढ़ने के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गयी है। 16वीं और 17वीं लोकसभा में कांग्रेस या अन्य विपक्षी दलों के पास इस पद के लिए आवश्यक 10 प्रतिशत सदस्य नहीं थे। कांग्रेस

ने इस बार लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर इस पद को हासिल किया है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े चयन के अलावा लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) निदेशक जैसी प्रमुख नियुक्तियों पर महत्वपूर्ण पैनल के सदस्य भी होंगे। प्रधानमंत्री इन पैनल के प्रमुख होते हैं। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को लोकसभा में पहली पंक्ति में सीट मिलेगी। यह सीट डिप्टी स्पीकर की सीट के बगल वाली होगी। इसके अलावा संसद भवन में सचिवीय तथा अन्य सुविधाओं से युक्त एक कमरा भी मिलेगा। विपक्ष के नेता को औपचारिक अवसरों पर कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। एक केन्द्रीय मंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं राहुल गांधी को मिलेगी। राहुल गांधी इस बार उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले वह लोकसभा में केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश के अमेठी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह पांचवीं बार लोकसभा पहुंचे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवन दिया है। इस बार के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस एवं उसके नेता राहुल को मनोवैज्ञानिक लाभ पहुंचाया है, जो उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि बनी है। इससे कांग्रेस ने अपना आत्मविश्वास फिर से पा लिया है, जो कोई छोटी बात नहीं। और यह राहुल और प्रियंका गांधी की गतिविधियों में साफ झलकता है। साथ ही, अब इस बात को लेकर भी कांग्रेस में कोई दुविधा नहीं रह गई है कि गांधी परिवार ही सर्वोच्च है और पार्टी पर उसका पूरा नियंत्रण होगा। इसका यह भी मतलब है कि टीम-राहुल का सभी मामलों में फैसला अंतिम होगा। पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से राहुल के पास कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सदन के भीतर पहली बार वह कोई पद संभालने जा रहे हैं। ऐसे में राहुल के सामने चुनौती होगी कि वह किस तरह पूरे विपक्ष को साथ लेकर चलते हुए रचनात्मक विरोध की भूमिका को आकार देते हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा काम दलित और पिछड़े मतदाताओं ने यूपी में जो उनकी मदद की है, उनका विश्वास बनाए रखने का है। यह बड़ी सचाई है कि आज भी देश के महत्त्व के राज्यों में भाजपा को क्षेत्रीय दल शिकस्त दे रहे हैं। अगर क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस का गठजोड़ बना रहे, तो ही भाजपा पर दबाव आएगा। बड़ा सच यह भी है कि न भाजपा बदली है ना उसकी विचारधारा। भाजपा एवं नरेन्द्र मोदी को भले ही चुनावों में पूर्ण बहुमत न मिला हो, लेकिन वह ही आज ताकतवर है। यह भी समझना होगा कि भाजपा विपक्ष की ताकत से नहीं, बल्कि सरकार की बड़ी गलतियों एवं पार्टी के अति उत्साह से नुकसान में पहुंची है। यह भी एक तथ्य है कि मुस्लिमों के सक्रिय-समर्थन के बिना कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिल सकती थी। निश्चित ही मुसलमानों के वोट की अहमियत कुछ-कुछ सीटों पर हार-जीत का फैसला कर गई है। भाजपा अपनी आगे की रणनीति इसी आधार पर बनाएगी और वो पिछले चुनावों के जैसी ही होगी। मतलब कि भाजपा कोई नई भाषा नहीं बोलने वाली है। वह आरोप लगाती रहेगी कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण करती है। कांग्रेस के सामने चुनौती होगी कि वो इस आरोप को अपने पर आने न दे, ताकि भाजपा हिंदुओं के हितों की एकमात्र रक्षक है, ऐसा दावा ना कर सके। कांग्रेस को इस हिंदू-मुस्लिम राजनीतिक बवंडर से बचने के लिये अपनी रणनीति को बनाना होगा। बिना हिन्दू वोट के कांग्रेस सफल राजनीतिक पारी नहीं खेल सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सफलता और निष्फलता का सही आकलन कर लेना जरूरी है। जनता के समक्ष अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखना अच्छी बात है, लेकिन मोदी आज जिस जमीन पर खड़े हैं, जनता के बीच उनकी जो स्वीकार्यता है उसका सही आकलन करना कांग्रेस की आगे की रणनीति के लिए बेहद जरूरी होगा।

दृष्टि कोण

पंजाब में आसन्न संकट की आहट

इस बार लोकसभा में भाजपा का सफाया हो गया और शिअद एक सीट, कांग्रोस 7 और आप को तीन सीटों पर कामयाबी मिली है। पंजाब के इस आसन्न संकट को देखते हुए केन्द्र सरकार को सुनियोजित तरीके से खालिस्तानियों पर नकेल कसने की रणनीति पर काम करना होगा, ताकि खालिस्तान के उनके ख्वाब को सदैव के लिए खत्म किया जा सके। पंजाब में आसन्न संकट की आहट गत 6 जून को 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' की चालीसवीं बरसी पर कईं खालिस्तान समर्थकों द्वारा अमृतसर स्थित 'हर मन्दिर साहिब/'स्वर्ण मन्दिर' में हर साल की तरह इस बार भी कट्टरपंथी अलगाववादी नेता जनरैल सिह भिण्डरावाले, हरदीप सिह निज्जर, क्षतिग्रस्त अकाल तख्त के चित्र लगी तथा खालिस्तान जिन्दाबाद लिखी तख्तियाँ उठाये, खालिस्तानी झण्डे लिए, 'खालिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाये, इससे पहले 18वीं लोकसभा चुनाव में इस राज्य से खालिस्तान समर्थक दो निर्दलीय उम्मीदवारों की बडे अन्तर से जीत, यह पंजाब के भावी आसन्न संकट की आहट है। यह सब देखसुनकर पंजाब लोगों में से शायद ही किसी को वुछ आर्यं हुआ होगा। इसका कारण यह है कि पंजाब के लोग यहाँ की इस जमीनी सच्चाईं से भली-भाँति परिचित हैं। वे चाहकर भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। वैसे भी खालिस्तानी कईं तरह की हरकतों के जरिए इस राज्य में ये अपनी उपस्थिति दिखाते आए हैं, इसमें खालिस्तान समर्थकों द्वारा चुनाव लड़ना, ऑपरेशन ब्लू स्टार के दिन मातम मानना, दीवारों पर खालिस्तानी नारे लिखना या फिर अपना झण्डा फहराना रहा है। कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन समेत कईं देश उनके बड़े अड्डे बने हुए हैं। इनमें से कनाडा तो बेशमा से खुलकर उनकी हिमायत करता आ रहा है। इसी 12 जून को खालिस्तानियों ने इटली के पुगालिया में आयोजित जी-7 सम्मेलन से पहले महात्मा गाँधी की प्रतिमा खण्डित कर उसके नीचे अपने नेता हरदीप सिह निज्जर का नाम लिख दिया। इससे पहले ये कनाडा,अमेरिका में महात्मा गाँधी की प्रतिमाएँ तोड़ने के साथ-साथ हिन्दुओं के मन्दिरों पर खालिस्तानी नारे लिखने और लन्दन स्थित भारतीय उच्चायुत्त कार्यालय पर तोड़फोड़ कर चुके हैं,किन्तु वहाँ की पुलिस ने इनके खिलाफ अपेक्षित कार्रवाईं नहीं की है। इस बार के लोकसभा के चुनाव में खालिस्तान समर्थक प्रत्याशियों को चुनाव लड़न के लिए अमेरिका समेत दूसरे देशों से धन भी मिला है। 6 जून, 1984 को हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद खालिस्तानियों के खत्मे के लिए चली मुहिम ने उनकी कमर जरूर तोड़ दी थी, पर वुछ लोगों की मन से अभी तक खालिस्तान का विचार/चाहत का अन्त नहीं हुआ है, क्योंकि लोभ या फिर भय के कारण देश की सभी सियासी परटियाँ इनके खिलाफ खुलकर बोलने से बचती आयी हैं। यहाँ तक कि वुछ परटियों का उन्हें मौन समर्थन भी मिलता रहा है और अब भी प्राप्त हो रहा है। इस साल के बरसी के कार्यंव्राम में खालिस्तान समर्थकों में अकाली दल (अमृतसर) के पूर्व सांसद सिमरनजीत सिह मान भी शामिल थे, जो संगरूर लोकसभा सीट से 26 जून, 2022 उपचुनाव में जीते थे, पर इस बार इन्हें आप के प्रत्याशी गुरमीत सिह हेयर ने हरा दिया है। ये न केवल चुनाव हार गए हैं, बल्कि तीसरे स्थान पर रहे हैं। इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में 'भारतीय पुलिस सेवा' (आइ.पी.एस.) से त्यागपत्र दिया था। पूर्व सांसद ध्यान सिह मण्ड के गुट समेत विभिन्न संगठनों के कार्यंकर्ताओं ने सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त पर नारे लगाये। अलगाववादी नेता जनरैल सिह भिण्डरावाले कट्टरपंथी सिख संगठन दमदमी टकसाल का प्रमुख था। 6 जून, 1984 को पंजाब में जनरैल सिह भिण्डरावाले के नेतृत्व में सिख उग्रवाद को रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के आदेश पर भारतीय सेना द्वारा स्वर्ण मन्दिर पर धावा बोला गया। भिण्डरावाले ने स्वर्ण मन्दिर परिसर में भारी मात्रा में घातक हथियार जमा किये हुए थे। स्वर्ण मन्दिर परिसर में उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान वह अपने हथियारबद्ध अनुयायियों के साथ मारा गया था। अब जनरैल सिह भिण्डरावाला सरीखा दिखने वाला अमृतपाल सिंह देशद्रोह के आरोप में 'राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम' (एनएसए) में गिरतार और इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बन्द है। उसने जेल में रहकर पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से काँग्रेस के प्रत्याशी वुलबीर सिह जीरा को 1.97 मतों से जीत हासिल की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के अंगरक्षक रहे और उनके हत्यारे बेअन्त सिह का बेटा सरबजीत सिह खालसा फरीदकोट साहिब लोकसभा (सुरक्षित सीट) से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीता है।

कुछ अलग

चीन द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन

हांगकांग में लोकतंत्र की हत्या, ऊइगर मुसलमानों पर अत्याचार एवं हांगकांग के मीडिया मुगल जैक मा को हिरासत में लिए जाने को लेकर चीन की भत्र्सना की जा रही है। कहा जा रहा है कि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में अपनी जनता के मानव अधिकारों का हनन कर रहा है। इस संदर्भ में 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार घोषणा पत्र की धाराओं पर पुनर्विचार करना चाहिए। घोषणा पत्र की धारा 29 में व्यक्ति के अधिकारों को प्राथमिक बताया गया है यद्यपि यह भी कहा गया है कि व्यक्ति के अधिकारों को समाज के हित में सीमित किया जा सकता है। लेकिन प्राथमिकता व्यक्ति के अधिकारों की ही बनी रहती है। इसका अर्थ यह हुआ कि व्यक्ति विशेष समाज के हितों के विपरीत तब तक काम कर सकता है जब तक सरकार उसके अधिकारों को सीमित न करें। जैसे छात्रों को सिखाया जाए कि चोरी तब तक की जा सकती है जब तक पुलिस न पकड़े। यह न सिखाया जाए कि चोरी करना गलत है। इसी प्रकार घोषणा पत्र कहता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हितों को तब तक बढ़ा सकता है जब तक समाज उसे न रोके। चाणक्य ने कहा था कि व्यक्ति को परिवार के लिए, परिवार को गांव के लिए और गांव को देश के लिए त्याग देना चाहिए। मानव अधिकार घोषणा पत्र इसके ठीक विपरीत है। व्यक्ति को प्राथमिक रखा गया है जबकि चाणक्य के अनुसार गांव और देश को प्राथमिक रखा जाना चाहिए। इसलिए इस धारा पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। घोषणा पत्र की धारा 29.1 में कहां गया है कि व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व है लेकिन इस दायित्व का निर्वाह करना व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए व्यक्ति द्वारा समाज के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह न भी किया जाए तो भी वह अपने व्यक्तिगत अधिकारों की मांग कर सकता है जैसा कि आतंकवादी करते हैं। इसका परिणाम यह है कि जो व्यक्ति समाज के विपरीत काम करते हैं उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है और उनके समाज के विपरीत कार्यो को पर्दे के पीछे छिपा दिया जाता है। घोषणा पत्र की धारा 29.3 में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्रीय के सिद्धांतों के विरुद्ध कोईं व्यक्ति कार्यं नहीं करेगा। अब विचार कीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों में एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि सुरक्षा परिषद में पांच स्थायी सदस्य होंगे जिनके पास वीटो पॉवर होगा। शेष 200 देशों को नीचा दर्जा दिया गया है। इसलिए इस असमानता के विरुद्ध आवाज उठाना मानव अधिकार घोषणा पत्र के विपरीत है। एक तरफ घोषणा पत्र संपूर्ण विश्व के नागरिकों के समान अधिकार की बात करता है और वही घोषणा पत्र दूसरी तरफ वुछ विशेष देशों के विशेष अधिकारों को सुरक्षित करता है और संपूर्ण विश्व को इस असमानता के प्रति आवाज उठाने से भी मना करता है। घोषणा पत्र की एक प्रमुख विसंगति आर्थिक असमानता को पुष्ट करने की है। धारा 13 में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को अपने देश की सीमा में यात्रा का अधिकार होगा। धारा 21.2 में कहा गया कि देश की सीमाओं में व्यक्ति को सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग का अधिकार होगा। धारा 22 में कहा क्या कि हर व्यक्ति को देश की सीमा में सामाजिक सुरक्षा जैसे रोटी, कपड़ा और मकान का अधिकार होगा। प्रश्न यह है यदि संपूर्ण विश्व एक ही है तो इन आर्थिक अधिकारों को देश की सीमा में क्यों बांध दिया गया? यानि राजनीतिक अधिकारों में संपूर्ण विश्व एक है। विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनीतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय बनाने से अमीर देशों को गरीब देशों में दखल करने का अवसर मिल जाता है जबकि आर्थिक अधिकारों को सीमा के अंदर बांध देने से अमीर देश अपनी अमीरी को सुरक्षित रख सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में हमें चीन द्वारा मानव अधिकारों के हनन को समझना चाहिए।

देश दुनिया से

नीट सहित अहम प्रतियोगिताओं में पेपर लीक मामले दुर्भाग्यपूर्ण

पेपर लीक की समस्या सिर्प उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे पिछडा समझे जाने वाले राज्यो तक ही सीमित ही नही है। पेपर लीक की समस्या एक महामारी की तरह एक संगठित रूप से संचालित मशीनरी की तरह काम कर रही है, जिसमे छात्र माफिया, कोचिंग सेंटर, प्रिंसिपल और अधिकारी तक शामिल है। जम्मू से लेकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक से लेकर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश तक पिछले 5 वषरे मे पेपर लीक के 41 मामलो की आधिकारिक मामलो मे पुष्टि हुईं है। महामारी की तरह पैली हुईं इस बीमारी को रोकने मे शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य भता एजेंसिया पूरी तरह से असफल हुईं है। पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश की जरिये इन मामलो को रोकने के लिए आजीवन कारावास समेत एक करोड़ रुपए तक के फाइन का प्रावधान कर दिया है, अब देखना है कि इतनी सख्त सजा के प्रावधान के बावजूद परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलो मे कमी आयेगी या नही।

अभी आम चुनावों से वुछ माह पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित पुलिस भता परीक्षा के पेपर लीक का मामला थमा ही नही था कि पूरे देश मे मेडिकल की पढाईं के लिए प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा नीट मे भारी गड़बड़ी और पेपर लीक के मामले ने पूरे देश मे मेडिकल मे प्रवेश के इच्छुक छात्रों के मन मे निराशा और अशांति पैला दी है। पेपर लीक की समस्या सिर्प उत्तर प्रदेश या बिहार जैसे पिछडा समझे जाने वाले राज्यो तक ही सीमित ही नही है। पेपर लीक की समस्या एक महामारी की तरह एक संगठित रूप से संचालित मशीनरी की तरह काम कर रही है, जिसमे छात्र माफिया, कोचिग सेंटर, प्रिसिपल और अधिकारी तक शामिल है। जम्मू से लेकर उत्तर प्रदेश, कर्नाटक से लेकर गुजरात और अरुणाचल प्रदेश तक पिछले 5 वषरे मे पेपर लीक के 41 मामलो की आधिकारिक मामलो मे पुष्टि हुईं है। महामारी की तरह पैली हुईं इस बीमारी को रोकने मे शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग और अन्य भता एजेंसिया पूरी तरह से असफल हुईं है। पता चला है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अध्यादेश की जरिये इन मामलो को रोकने के लिए आजीवन कारावास समेत एक करोड़ रुपए तक के फाइन का प्रावधान कर दिया है, अब देखना है कि इतनी सख्त सजा के प्रावधान के बावजूद परीक्षाओं के पेपर लीक के मामलो मे कमी आयेगी या नही। अब यह समस्या एक सामाजिक समस्या बन गयी है, चुनाव के समय हर राजनीतिक दल अपने अपने समर्थको को मुफ्त की रेविड़यां बांटने की घोषडा करता है जिससे उन्हे वोट मिल सके। पर कोईं भी दल युवाओ को इस तरह का आश्वासन देने की हिम्मत नही करता कि हम देश मे युवाओ को प्रतियोगी परीक्षाओं में निष्पक्ष पारर्दशिता पूर्ण परीक्षा दे पायेंगे। इस मामले मे संघ लोक सेवा आयोग को छोड़कर सारे भता बोर्ड या भता एजेंसिया असफल रहे हैं। वर्ष 2022 मे राजस्थान मे धोखाधड़ी विरोधी कानून भी पारित किया गया और इसमे सजा के तौर पर आजीवन कारावास के प्रावधान को शामिल किया गया। भारतीय संसद द्वारा फरवरी 2024 मे इसी तरह का कानून पारित करने के बावजूद आज भी इस अपराध मे सैकड़ो लोग गिरफ्तार किये गए है। युवाओ के लिए पेपर लीक की घटनाएं पीड़ादायक और विनाशकारी है, यह जिदगी मे रुकावट, तनाव पूर्ण परिवार और तार तार हो जाने वाले को जन्म देती है और राज्य की निष्पक्ष रूप मे भता परीक्षा आयोजित करने मे असमर्थता प्रर्दषित करती हैं और ये राज्य की सेवा मे आयी अक्षमता भी दर्शाती है। जब वेंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान सांसद के रूप मे शपथ लेने जा रहे थे तो पूरे विपक्ष मे नीट नीट के नारे लगाकर उन्हे हूट किया, जो उचित नही है। यह सच है कि सिविल स्रविस और आईं आईं टी के पात नीट देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है और इसके पेपर लीक होना और वुछ सेलेक्टेड लोगो को ग्रेस मार्व देना बहुत ही दुर्भाग्य पूर्ण है। इस समस्या के प्रति सभी दलों को पाटा लाइन से हटकर संजीदगी से रोकने की आवश्यकता है क्योकि एक दूसरे पर दोषारोपण से इस समस्या से छुटकारा नही मिलने वाला। विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे बड़ी पाटा कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि पिछले पांच वषरे मे राजस्थान मे अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस के कार्यं काल मे सबसे अधिक पेपर लीक हुए और उसी कांग्रेस के सांसद शिक्षा मंत्री धर्मेद्र प्रधान को नीट नीट करके हूट कर रहे थे, वही इंडिया गठबंधन के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के तीन वरिष्ठ नेता लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर लैंड फॉर जाब स्वैम्प मे चार्ज शीट दाखिल हो चुकी है। ऐसी घटनाओ से व शिक्षित युवा जिनके पास न पैसा है न जुगाड़ है, निराश और हताश होकर आत्म हत्त्या जैसे कदम उठाते है। एक समय लोक सभा मे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियो के लिए पदोन्नति मे आरक्षण के लिए बहस चल रही थी और इस बिल के विरोध मे बोलते हुए समाजवादी पाटा के नेता मुलायम सिह यादव ने कहा कि यदि प्रमोशन मे भी आरक्षण दिया गया तो हमे वुशल और दक्ष सचिव और वैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारी नही मिलेंगे और मेरे विचार मे श्री मुलायम सिह यादव के विचारों पर बहस या चर्चा की जा सकती है और आरक्षण का विरोध करने वाले यह भी तर्व देते है कि यदि 30™ अंक प्राप्त करने वाले डॉक्टर बनेंगे तो मरीजो का इलाज वैसे होगा। यदि हमे पुलिस और प्रशासन को दक्ष बनाना है तो प्रतियोगी परीक्षाओं मे पेपर लीक और सोल्व गैंग को जड़ से उखाड़ देना होगा, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों को अपने मतभेद भुलाकर इस समस्या का हल निकालना होगा। जहां आज हमने पूरे विश्व के समक्ष एक मजबूत आर्थिक शत्ति के रूप मे स्थापित करने मे सफलता पायी है पर वही हम सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा मे प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षाओं मे पूरी निष्पक्षता और पारर्दषिता स्थापित करने मे पूरी तरह से असफल रहे है और यही हमारा दुर्भाग्य है।

आप का नजरिया

जनप्रातिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता की जरूरत

आज के युग में जहां एक छोटे से पद की नौकरी के लिए लाखों बेरोजगार शिक्षितों की कतार खड़ी होती हो, बहुत सारी टेस्ट तथा प्रातियोगितामूलक परीक्षाओं में सफल होने के बाद ही उन्हें नौकरी मिलती हो, हमारे देश की प्राजातांत्रिक व्यवस्था का एक भद्दा मजाक देखिए, देश के शासन की डोर तथा भाग्यविधाता बनने के लिए कोईं विशेष शिक्षा या योग्यता की आवश्यकता ही नहीं, इसका सीधा प्राभाव, आप माने या नहीं, देश की सारी व्यवस्थाओं पर पड़ता है और शायद आज भारत की गरीबी, बेरोजगारी तथा अव्यवस्था का मूल कारण इसी शिक्षा व्यवस्था का जरूरी न होना, गुणात्मक प्राभाव इसके पिछड़ेपन में नजर आता है। आप बहस कर जीत सकते हैं, पर एक बात मानकर चलिए कि देश सिर्प बाबुओं की मनमानी तथा जनता के प्रातिनिधियों के इसी कारण की वजह से जनता या देश की प्रागति प्राभावित हो रही है और आगे होती रहेगी। दुख है आज की तारीख में इस बात की बहस न प्रिंट मीडिया न ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो रही। जब एक छोटे से व्यापार या कार्यालय के कार्यंकलाप को संपादित करने के लिए शिक्षात्मक मापदंड अनिवार्यं है तो देश, खासकर भारत जैसे विशाल देश को चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में क्यों नहीं की गईं, शायद इसका कारण उस समय के शासनलोभी नेताओं ने अपने लाभ को देखकर न करने की योजना बनाईं होगी। मुझे तो ऐसा प्रातीत होता है कि भारत की राजनीति तीन एमएस (मनी, मुश्किल एवं मैज्योरिटी) के खेल में सिमट गईं है जहां अच्छे प्राशासक, जनप्रातिनिधि जिनमें प्राशासनिक, प्रागतिशील विचारधारा तथा सच्चे नेतृत्व करने की क्षमता हो, ऐसी व्यवस्था ही नहीं की गईं। हो सकता है मेरे इस लेख की आलोचना भी हो पर एक बड़ा देश जो आजादी के 70 वर्षो के बाद भी पिछड़ा बना रहे, जहां की 60 प्रातिशत जनता आज गरीबी रेखा के नीचे, किसी भी आधुनिक सुख-सुविधा से वंचित रहे, अपने आपमें लज्जाजनक बात है। इस बात को थोड़ा और अच्छी तरह समझने के लिए हमें स्वाधीनता से वुछेक दशक पहले जाना पड़ेगा, जब भारतवर्ष बर्मा से अफगानिस्तान तक पैला था। हजारों छोटेछोटे शासकों के बीच एक बड़ा भारतवर्ष, अपनी बहुत सारी अच्छाइयों के लिए विश्व के समृद्ध देशों में इसकी गणना होती थी, जिसे पाने के लिए अरब साम्राज्य यूरोपीय देशों के अलावा कितने शासकों की होड़ लगी रही थी। एक ओर विशाल भारतवर्ष में मौर्यं, गुप्त, मुगल साम्राज्यों ने देश को एक बनाकर रखा तो दूसरी ओर छोटे-छोटे शासकों के बीच वर्चस्व की लड़ाईं, विद्रोह, मतभेद भी रहे। इसका फायदा विदेशों से आए छोटे पर मजबूत यूरोपियन देशों के राजाओं या कहें तो व्यापारियों को मिला और एक बड़ा देश छोटे से देश के राजा/रानी के हाथ चला गया और हमारे विभाजित, कमजोर, मतलबी शासक मूकदर्शक बन बैठे। मैं यहां इस बात की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि देश जिसे हम महान कहते हैं, सैकड़ों वर्षो तक अंग्रेजों के अधीन बना रहा, क्योंकि यहां की जनता या फिर विभाजित शासकों को इस बात का पता ही नहीं चला कि भारत देश हजारों छोटे-छोटे राज्यों या राजघरानों से बना है, उनका शत्रु बगल वाला राजघराना या राजा नहीं और कोईं है।

भारतीय मूल के डॉ. संपत फिर चुने गए रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति चुनाव में होगी अहम भूमिका

वॉशिंगटन, 01 जुलई (एजेंसियां) ।

अमेरिका में भारतीय मूल के डॉ. संपत शिवांगी को एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया है। उन्हें जुलाई में मिल्वौकी में होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेन्शन के लिए के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। बता दें कि इस सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक रूप से नामित किया जाएगा।

जुलाई में इस दिन होगा आरएनसी - 78 वर्षीय ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से मैदान में हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय के प्रभावशाली नेता डॉ. शिवांगी को छठी बार सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुना गया है। उन्होंने कहा, खबर साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे 13 जुलाई से 19 जुलाई तक मिल्वौकी में होने वाले आगामी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में एक आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। विस्कोन्सिन के मिल्वौकी में चार दिवसीय रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन (आरएनसी) पांच नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करेगा। नामांकन प्रक्रिया देश भर से रिपब्लिकन प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाएगी। बता दें, रिपब्लिकन पार्टी की आजीवन सदस्य और रिपब्लिकन इंडियन काउंसिल व रिपब्लिकन इंडियन नेशनल काउंसिल की संस्थापक सदस्य डॉ. शिवांगी को लगातार छह बार आरएनसी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा, यह छठी बार होगा जब मैं रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा, ताकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को नामित कर सकूं।

इससे पहले भी चुने गए रिपब्लिकन के प्रतिनिधि - भारतीय-अमेरिकी डॉ. संपत को पहली बार 2004 में न्यूयॉर्क शहर में रिपब्लिकन सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को नामित करने के लिए चुना गया था। 2008 में, उन्हें जॉन मैककेन और 2012 में टाम्पा में मिट रोमनी को नामित करने के लिए मिनियापोलिस में एक रिपब्लिकन प्रतिनिधि के रूप में चुना गया था। अब फिर से मिल्वौकी में 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को नामित करने के लिए उन्हें चुना गया है। उन्होंने कहा, ट्रंप को दोबारा नामित करने और अगले चार वर्ष के लिए दोबारा निर्वाचित करने के लिहाज से इस ऐतिहासिक सम्मेलन का हिस्सा बनना बेहद सम्मान की बात है।

न्यूज ब्रीफ

विदेश में पढ़ाई के सपनों को झटका ऑस्ट्रेलिया में वीजा के लिए करना होगा दोगुना खर्च

सिडनी । ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो जरा ठहरिए। क्योंकि अब ये उतना आसान नहीं रहा जितना हुआ करता था। यहां छात्र वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। छात्रों को पढ़ाई के लिए अब खर्च ज्यादा करना होगा। दरअसल, यहां अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा शुल्क को दोगुने से भी अधिक कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह कदम रिकॉर्ड प्रवासन पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। यह किया बदलाव अंतरराष्ट्रीय छात्र वीजा शुल्क एक जुलाई से बढ़ गया है। अब यह शुल्क 710 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 39,493.11 रुपये से बढ़कर 1600 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 88,998.56 रुपये हो गया है। वहीं विजिटर वीजा वाले और अस्थायी स्नातक वीजा वाले छात्र अब छात्र वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। आवेदन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लागू होगा गृह मंत्री क्लेयर ओ नील ने कहा, लागू होने वाले बदलावों से हमारी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अखंडता को बहाल करने में मदद मिलेगी। साथ ही एक प्रवासन प्रणाली तैयार होगी जो निष्पक्ष, छोटी और ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर है। मार्च में जारी आधिकारिक आंकड़ों से पता चला है कि 30 सितंबर, 2023 तक आव्रजन 60 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 548,800 हो गया है। वीजा शुल्क में वृद्धि किए जाने की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया में छात्र वीजा के लिए आवेदन करना अमेरिका और कनाडा की तुलना में कहीं अधिक मंहगा हो गया है। अमेरिका से भी महंगा शुल्क में वृद्धि के कारण ऑस्ट्रेलिया के लिए छात्र वीज़ा के लिए आवेदन करना, अमेरिका और कनाडा जैसे प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कहीं अधिक महंगा हो गया है। अमेरिका में जहां इसके लिए 185 अमेरिकी डॉलर यानी 15,440.14 रुपये देने होते हैं। वहीं कनाडा में 150 कनाडाई डॉलर यानी 9,156.36 रुपये का शुल्क देना पड़ता है। सरकार ने कहा कि वह वीजा नियमों में खामियों को भी दूर कर रही है, जो विदेशी छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में अपने प्रवास को लगातार बढ़ाने की अनुमति देते हैं, क्योंकि 2022-23 में दूसरे या बाद के छात्र वीजा पर छात्रों की संख्या 30 फीसदी से अधिक बढ़कर 150,000 से अधिक हो गई है।

नस्लीय टिप्पणी पर पीएम सुनक ने रिफॉर्म यूके पार्टी को घेरा, बोले- ये उनकी विचारधारा को बताता है

लंदन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने निगेल फरेज की दक्षिणपंथी रिफॉर्म यूके पार्टी के एक समर्थक की तरफ से उन पर किए गए नस्लीय टिप्पणी के बाद गुस्सा जाहिर किया है। दरअसल एक समाचार चैनल ने रिफॉर्म यूके पार्टी एक समर्थक की रिकॉर्डिंग को प्रसारित किया था, जिसमें वो दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए अपमानजनक शब्द पाकी का इस्तेमाल कर रहा था। ये रिफॉर्म यूके पार्टी की संस्कृति को दर्शाता है वहीं अपने चुनाव अभियान के दौरान इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री सुनक ने मीडिया से कहा, कि इससे दुख होता है और मुझे गुस्सा आता है। ऐसी टिप्पणी मेरी दोनों बेटियों कृष्णा और अनुष्का के सामने की गई है, मैं उस टिप्पणी को दोहरा भी नहीं सकता। पीएम सुनक ने आगे कहा, कि जब आप रिफॉर्म उम्मीदवारों और प्रचारकों को नस्लवादी और स्त्री-द्वेषी भाषा और बिना किसी चुनौती के विचारों का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह आपको रिफॉर्म पार्टी के भीतर की संस्कृति के बारे में बताता है।

दोहा में विदेश मंत्री जयशंकर और पीएम अल थानी की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर बातचीत

दोहा । व्यापार, निवेध और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने को लेकर भारत कतर के साथ बातचीत करेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर एक दिवसीय यात्रा पर कतर की राजधानी दोहा पहुंच चुके हैं। जयशंकर कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी के साथ द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बातचीत करेंगे। बता दें कि कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। दोहा पहुंचने के बाद कतर के चीफ ऑफ प्रोटोकॉल महामहिम श्री इब्राहिम फखरू ने हवाई अड्डे पर डॉ जयशंकर का स्वागत किया। व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी समेत कई अन्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी समेत कई अन्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।

दक्षिण चीन सागर पर कम नहीं हो रहा तनाव, चीन ने फिलीपींस तट पर तैनात किया विमानवाहक पोत

बीजिंग, 01 जुलई (एजेंसियां) ।

दक्षिण चीन सागर पर तनाव का माहौल है, इसी बीच चीन ने अपना दूसरा विमानवाहक पोत शांडोंग भी तैनात कर दिया। यह शांडोंग फिलीपीन तट के पास पानी में गश्त करते हुए देखा गया है। वहीं फिलीपींस की ओर से भी दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन का विरोध करना शुरू कर दिया है।

पिछले कुछ महीनों में चीन और फिलीपींस की नौसेनाओं और तट रक्षकों के बीच टकराव चल रहा था। क्योंकि अमेरिका द्वारा समर्थित फिलीपींस ने चीन द्वारा दावा किए गए दक्षिण चीन सागर में द्वितीय थॉमस शोल पर अपने दावों को साबित करने का अथक प्रयास किया था। चीन दक्षिण चीन सागर के अधिकांश हिस्से पर अपना दावा करता है। इस पर फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई और ताइवान के बीच तीखी बहस है। चीन का आरोप है कि फिलीपींस ने 1999 में जानबूझकर दूसरे थॉमस शोल में एक नौसैनिक जहाज को फंसा दिया था। चीन का दावा था कि क्षतिग्रस्त जहाज को नौसैनिक कर्मियों द्वारा संचालित एक स्थायी प्रतिष्ठान में बदल दिया। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के एक न्यायाधिकरण द्वारा 2016 के फैसला लिया गया। इसके आधार पर दक्षिण चीन सागर पर अपने दावों को पुख्ता करने की कोशिश में लगा है। हालांकि, चीन ने न्यायाधिकरण का बहिष्कार किया। लेकिन न्यायाधिकरण के निष्कर्षों को खारिज कर दिया और अपने दावों पर जोरदार तरीके से जोर दिया।

वहीं दूसरी ओर चीन ने पिछले महीने एक नया कानून लागू किया। इस नए कानून के तहत उसके तट रक्षक को चीन के जलक्षेत्र में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी जहाजों को जब्त करने और 60 दिनों तक विदेशी चालक दल को हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया। यह कानून के तहत चीन के तट रक्षक को यह अधिकार भी है कि वह जरूरत पड़ने पर विदेशी जहाजों पर गोली चला सकता है। अमेरिका ने मनीला के दावों के समर्थन में अपनी ताकत दिखाने के लिए फिलीपींस में मध्यम दूरी की टाइफॉन मिसाइल प्रणाली तैनात की है।

अब हाल में चीन ने अपना दूसरा विमानवाहक पोत शांडोंग तैनात किया है। जो फिलीपीन तट के पास पानी में गश्त करते नजर आया। लगभग 70,000 टन विस्थापन वाला विमानवाहक पोत शांडोंग, फिलीपींस के पानी में गश्त करते नजर आया। चीनी विशेषज्ञों के अनुसार विमानवाहक पोत संभवत: एक निर्धारित अभ्यास पर है, जो इसे पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में संभावित दूर की समुद्री यात्रा के लिए भी तैयार कर सकता है।

बता दें कि शांडोंग की तैनाती पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा बड़े और मध्यम विध्वंसक सहित प्रमुख सतही लड़ाकू जहाजों के साथ-साथ मुख्य उभयचर लैंडिंग जहाज को दक्षिण चीन सागर में तैनात करने के बाद की गई है। इसका कारण यह है कि फिलीपींस के साथ समुद्री क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ गया था।

वहीं शंघाई यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ में राजनीति विज्ञान विभाग में रक्षा प्रोफेसर नी लेक्सियोंग को हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में कहा कि शांडोंग का रास्ता मनीला और वाशिंगटन के लिए एक निवारक के रूप में था। मनीला स्थित थिंक टैंक इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक चेस्टर कैबल्ज़ा ने कहा कि वाहक की गश्त बीजिंग द्वारा प्रदर्शनकारी राजनीति का एक उदाहरण है। यदि ऐसा फिर से होता है तो इसका अर्थ होगा कि उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर लाल झंडा है। उन्होंने कहा, जब हम भारी सैन्य बल देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि बीजिंग युद्ध की तैयारी कर रहा है।

विवादित दक्षिण चीन सागर में अपने दावों को पुष्ट करने के लिए चीन-फिलीपींस टकराव ने पिछले महीने हिंसक रूप ले लिया। यह तब हुआ जब बीजिंग द्वारा विदेशी जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करने और चीनी जल में उल्लंघन करने के संदिग्ध विदेशियों को हिरासत में लेने के लिए नए नियम जारी करने के बाद पहली बार उनके नौसैनिक जहाजों में टक्कर हुई। वहीं कुछ सप्ताह पहले फिलीपींस द्वारा दावा किए गए दक्षिण चीन सागर के द्वितीय थॉमस शोल के पास फिलीपींस के नौसैनिक जहाज और एक चीनी जहाज में टक्कर हो गई थी। बता दें कि फिलीपींस ने भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों का भी आयात किया है। चीन के पास वर्तमान में दो विमानवाहक पोत हैं, पहला लियाओनिंग, जो सोवियत युग के जहाज का एक रिफिट था। दूसरा शांडोंग, जो 2019 में कमीशन किया गया, एक स्वदेशी रूप से निर्मित दूसरा विमानवाहक पोत है। चीन का तीसरा विमानवाहक पोत फुज़ियान, जो 80,000 के विस्थापन के साथ दो वाहकों से बड़ा है, वर्तमान में परीक्षण के दौर से गुजर रहा है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का आरोप सीमा पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा अफगान तालिबान

इस्लामाबाद, 01 जुलई (एजेंसियां) ।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान में तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि बार-बार अनुरोध के बावजूद तालिबान सरकार पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। आसिफ ने कहा, पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पश्चिमी सीमा की ओर भेजने के लिए 10 अरब रुपये देने की पेशकश की थी और अफगान सरकार से सहयोग की उम्मीद की थी। लेकिन अफगान सरकार आतंकवादियो के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। पाकिस्तान ने बार-बार अफगानिस्तान की सरकार से कहा है कि वह तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और अन्य आतंकवादी समूहों को अपनी धरती का इस्तेमाल न करने दे।

हालांकि, काबुल भी बार-बार इस दावे को खारिज करता रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ उसकी जमीन का इस्तेमाल हो रहा है। आसिफ ने कहा कि सरकार ने पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में आतंकवादियों को स्थानांतरित करने के लिए 10 अरब रुपये की पेशकश की थी। लेकिन उसे डर था कि आतंकवादी वहां से भी पाकिस्तानी की सीमा में लौट सकते हैं। पिछले हफ्ते वॉयस ऑफ अमेरिका को दिए इंटरव्य में आसिफ ने कहा था कि सैन्य अभियान अज्म-ए-इस्तेकाम के तहत पाकिस्तान सीमा पार अफगानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना सकता है।

उन्होंने टीटीपी के साथ बातचीत की संभावना को भी खारिज कर दिया था। इस साल मार्च में पाकिस्तानी वायु सेना के लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के अंदर खोस्त और पक्तिका के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादियों के खिलाफ हवाई हमले किए थे। इन हवाई हमलों के तुरंत बाद आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को बताना चाहता है कि हम पाकिस्तान में इस तरह के आतंकवादी हमलों जारी नहीं रहने दे सकते। इस्लामाबाद ने यह कार्रवाई तब की थी जब पाकिस्तानी बलों पर एक घातक आतंकी हमला हुआ।

संपत्ति विवाद में महिला और बेटी को कमरे में बंद किया फिर दीवार बनाकर कर बाहर आने का रास्ता किया सील

इस्लामाबाद, 01 जुलई (एजेंसियां) ।

महिला ने सुहैल पर लगातार उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उसने बताया कि आरोपी के उसके घर से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है।

पाकिस्तान में सिंध प्रांत के हैदराबाद में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। संपत्ति विवाद मामले में एक महिला और उसकी बेटी को उसके परिजनों ने पहले एक कमरे में कैद कर लिया और फिर उस कमरे के बाहर दीवार बनाकर उसे पूरी तरह से सील कर दिया। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को बचा लिया।

कमरे के बाद दीवार बनाकर महिला को किया कैद

यह घटना लतीफाबाद नंबर-5 इलाके की है, जहां पुलिस और कुछ पड़ोसियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दीवार को तोड़कर पीड़ितों को बचाया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके जीजा अपने बेटों के साथ मिलकर उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। बाद में उन लोगों ने कमरे को बाहर से एक दीवार बनाकर हमेशा के लिए बंद कर दिया। आरोपी की पहचान सुहैल के तौर पर की गई है। महिला ने सुहैल पर लगातार उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। इसके अलावा उसने बताया कि आरोपी के उसके घर से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज भी है। कानून प्रवर्तन ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया। उन्होंने जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए अपनी प्रतिबद्धता का आश्वासन भी दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) डॉ. फारुख लिंजर ने जनता को आश्वासन दिया कि ऐसे जघन्य कृत्य को अंजाम देने वालों कोजवाबदेह ठहराने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है।

पूर्व राष्ट्रपति पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है फैसला, 34 संगीन आरोपों में दोषी हैं ट्रंप

वॉशिंगटन,01 जुलाई (एजेंसियां) ।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट बहुप्रतीक्षित फैसले पर फैसला सुनाएगी। जिसे सदियों के लिए फैसले का नाम दिया गया है। जिसमें ये तय होगा कि क्या पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभियोजन से मुक्त हैं बता दें कि 30 मई को ट्रंप को 34 मामलों में दोषी पाया था। भले ही फैसले में ट्रंप के इस दावे को खारिज करने की संभावना हो कि उन्हें अभियोजन से पूर्ण प्रतिरक्षा है। लेकिन यह निर्णय इस बात में महत्वपूर्ण होगा कि क्या 2020 के चुनाव में उनकी हार को पलटने की साजिश रचने के लिए उनका मुकदमा इस साल के चुनाव से पहले आगे बढ़ सकता है, जिसमें वे रिपब्लिकन उम्मीदवार हैं।

ट्रंप के नियुक्त जजों का बयान

वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नियुक्त किए गए रूढ़िवादी न्यायाधीश नील गोरसच ने अप्रैल में दलीलें सुनने के दौरान कहा था कि, हम सदियों के लिए एक नियम लिख रहे हैं। वहीं एक अन्य न्यायाधीश ब्रेट कैवनघ ने कहा, इस मामले का राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति पद के भविष्य और देश के

भविष्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

सुनवाई में पहले ही हो चुकी है देरी

बता दें कि मामले में ट्रंप की मूल सुनवाई की तारीख 4 मार्च थी, जो राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ नवंबर में होने वाले उनके चुनावी मुकाबले से काफी पहले थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने कार्यकाल के दौरान नियुक्त किए गए तीन लोगों समेत रूढ़िवादियों का वर्चस्व है, ने फरवरी में राष्ट्रपति पद की प्रतिरक्षा के लिए उनकी दलील सुनने पर सहमति जताई और मामले को अप्रैल में विचार किए जाने तक के लिए रोक दिया। जिसका साफ मतलब है कि मामले में सुनवाई पहले ही काफी देर हो चुकी है।

चार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे ट्रंप

हालांकि अदालत की तरफ से यह फैसला सुनाए जाने की संभावना नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को पूरी तरह से अभियोजन से प्रतिरक्षा प्राप्त है। अप्रैल में हुई बहस के दौरान, न्यायाधीश उनके दावों पर काफी हद तक संशय में दिखे, कुछ ने सवाल उठाया कि क्या इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति बिना किसी रोक-टोक के अपराध कर सकते हैं। चार आपराधिक मामलों का सामना कर रहे ट्रंप कम से कम चुनाव के बाद तक मुकदमों को टालने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है अगर ट्रंप फिर से चुने जाते हैं, तो जनवरी 2025 में राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद, उनके खिलाफ संघीय मुकदमों को बंद करने का आदेश दे सकते हैं।

हिंदुओं के खिलाफ हो रहे हमले के खिलाफ एकजुट हुए अमेरिकी सांसद, बोले- किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे

वॉशिंगटन, 01 जुलई (एजेंसियां) ।

अमेरिका में आजकल हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। इसी मसले को लेकर अब यहां के सांसद बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने यहां बढ़ते हिंदूफोबिया और अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे भेदभाव का विरोध जताने के लिए भारतीय अमेरिकियों को अपना समर्थन देने का संकल्प लिया है।

तीसरी बार मनाया गया राष्ट्रीय हिंदू वकालत दिवस

उत्तरी अमेरिका के हिंदुओं के गठबंधन (सीओएचएनए) ने 28 जून को तीसरी बार राष्ट्रीय हिंदू वकालत दिवस मनाया। इस दौरान कई हिंदू छात्रों, शोधकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं ने भाग लिया और अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं के सामने आने वाली चिंताओं पर चर्चा की।

हिंदूफोबिया और मंदिरों पर हमलों की निंदा

सांसद थानेदार ने यहां दिनभर चली वकालत में कहा, हम यहां हैं और हम लड़ाई

लड़ रहे हैं। हाउस रेजोल्यूशन 1131 पेश करने वाले डेमोक्रेट थानेदार ने कहा कि आप सभी की जो आवाज है, वही संसद में हिंदू समुदाय की आवाज है। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान का जश्न मनाते हुए हिंदूफोबिया और मंदिरों पर हमलों की निंदा की है।

उन्होंने कहा कि वह हिंदूफोबिया, भेदभाव या नफरत को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे

सांसद रिच मैककॉर्मिक ने नीति निर्माण में हिंदू अमेरिकी और भारतीय-अमेरिकी समुदाय की लगातार बढ़ती हुई भागीदारी और अमेरिका के भविष्य को बदलने की उनकी क्षमता का स्वागत किया। रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने हिंदू अमेरिकियों के योगदान का सम्मान करते हुए सदन के प्रस्ताव 1131 के लिए अपने समर्थन की ओर ध्यान दिलाया। साथ ही समुदाय से अमेरिकी सपने को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, जो नवाचार, कड़ी मेहनत, सफलता और इसकी परंपराओं का जश्न मनाता है।

रिपब्लिकन सांसद ग्लेन ग्रोथमैन ने समुदाय के साथ एकजुटता व्यक्त की और सांसद रो खन्ना ने पिछले दशक में समुदाय की वकालत के विकास का जश्न मनाया। लोगों को गर्व करने के लिए प्रेरित करते हुए खन्ना ने दर्शकों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बधाई दी।

देश में नफरत के खिलाफ खड़े रहेंगे

कांग्रेसी मैक्स मिलर ने धर्म की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में बात की और सदन के प्रस्ताव 1131 का समर्थन करने पर गर्व व्यक्त किया। उन्होंने हिंदू समुदाय के सामने आने वाली समस्याओं के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और आश्वासन दिया कि वे पूरे देश में नफरत और कट्टरता के सभी रूपों के खिलाफ खड़े रहेंगे।

रिपब्लिकन नेता मिलर ने स्वीकार किया कि यह देश के लिए एक कठिन समय है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वे हिंदू समुदाय के लिए मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर आपके समुदाय के साथ कुछ भी होता है, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। उन्होंने दर्शकों से मजबूती से खड़े रहने और अपने मूल्यों से कभी पीछे न हटने का भी आग्रह किया।

115 से अधिक सांसदों के कार्यालयों का दौरा किया

सीओएचएनए ने कहा कि इस साल हिंदुओं ने कई तरीके के हमलों का सामना किया है। 40 से अधिक कोर स्वयंसेवकों ने हाउस रेजोल्यूशन 1131 के लिए समर्थन की वकालत करने के लिए 115 से अधिक सांसदों के कार्यालयों का दौरा किया, जो हिंदू-अमेरिकी समुदाय के योगदान का जश्न मनाते हुए हिंदूफोबिया और मंदिरों पर हमलों की निंदा करता है।

15 अमेरिकी राज्यों से बड़ी संख्या में हिंदू युवाओं सहित 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

रोहित और विराट के एक साथ संन्यास लेने से स्तब्ध था: शमी

नई दिल्ली, 01 जुलाई (एजेंसियां) ।

टी20 विश्व कप 2024 चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इन दिग्गजों के एक साथ संन्यास लेने के फैसले से न सिर्फ क्रिकेट फैंस बल्कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी स्तब्ध हैं।

ब्रिजटाउन के केंसिंग्टन ओवल में दक्षिण अफ्रीका पर सात रन की जीत के साथ भारत ने अपना दूसरा टी20 विश्व कप जीता। इसके बाद विराट कोहली को उनकी 59 गेंदों में 76 रन की पारी के लिए प्लेयर-ऑफ-द-मैच पुरस्कार दिया गया। फैंस का शुक्रिया अदा करते हुए विराट ने कहा कि यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का आखिरी टी20 था।

दाएं हाथ के इस खिलाड़ी ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का अंत भारत के लिए इस प्रारूप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में किया, उन्होंने 125 मैचों में 48.69 की औसत और 137.04 की स्ट्राइक रेट से 4188 रन बनाए।

इसके बाद, रोहित ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि वह भी अपना टी20 इंटरनेशनल करियर यहीं खत्म कर रहे हैं, उन्होंने 159 मैचों में 4231 रन बनाकर अपना टी20 करियर सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी के रूप में समाप्त किया। उनके नाम पुरुषों के टी20 में सबसे ज्यादा शतकों का रिकॉर्ड भी है।

शमी ने कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली का टी20 से संन्यास लेना एक झटका था। वो भारत के लिए दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं, 15-16 सालों तक देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते रहे और व्हाइट-बॉल क्रिकेट के बादशाह के रूप में खुद को स्थापित किया।

दोनों का एक साथ संन्यास लेना चौंकाने वाला है, लेकिन यह स्वाभाविक भी है। जब एक खिलाड़ी जाता है, तो दूसरा आता है। हालांकि, टीम में ऐसे सितारों की जगह लेना एक बड़ी चुनौती होगी। मैं रोहित और विराट दोनों को टीम के लिए मैच जीतने, भारत के लिए अद्भुत पारियां खेलने और इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

भारत की खिताबी जीत पर शमी ने टीम इंडिया और सहयोगी स्टाफ को जीत के लिए बधाई दी और पूरे अभियान के दौरान टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रशंसकों का आभार जताया।

शमी ने कहा, विश्व कप का हिस्सा बनने वाले खिलाड़ी भाग्यशाली होते हैं कि उन्हें यह अवसर मिलता है। केवल 10 प्रतिशत खिलाड़ियों को अपने जीवन काल में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने का मौका मिलता है।

भारत की जीत के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फोन कॉल पर टीम इंडिया को बधाई देने पर शमी ने कहा, मैं वास्तव में सराहना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री में खेल के लिए जुनून है और वे व्यक्तिगत रूप से टीम को उनकी जीत के बाद बधाई देते हैं। इससे वास्तव में टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है।

न्यूज ब्रीफ

खिलाड़ियों की रवानगी से पहले विदाई समारोह में मांडविया बोले- भारत की पदक तालिका में होगा सुधार

नई दिल्ली । पेरिस ओलंपिक की शुरुआत 26 जुलाई से होगी। इससे पहले पेरिस जाने वाले एथलीटों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आगामी टूर्नामेंट में भारतीय दल द्वारा नया मानदंड स्थापित करने की उम्मीद जताई गई। इस बात पर जोर दिया गया कि हाल के वर्षों में सरकार के लिए खेल प्राथमिकता रहे हैं। इस विदाई समारोह में एथलीटों, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में खेलों से पहले एथलीटों के समर्थन में सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स) के बारे में बताया गया। मांडविया ने पेरिस जाने वाले एथलीटों की औपचारिक विदाई और किट के अनावरण के दौरान कहा, मुझे विश्वास है कि यह दल खेलों में भारत के विकास को बनाए रखेगा। हमने 2016 रियो में दो पदकों से बढ़कर तोक्यो में सात पदक हासिल किए। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक से भारत तालिका में 67वें से 48वें (स्थान) पर पहुंच गया। मुझे उम्मीद है कि हमारे एथलीट हमें इस बार पदक तालिका में और भी ऊपर ले जाएंगे। पेरिस जाने वाले भारतीय दल की तीन किट (औपचारिक पोशाक, खेल पोशाक, और यात्रा पोशाक) का अनावरण किया गया। मांडविया ने आगे कहा, यह कार्यक्रम सिर्फ किट और औपचारिक पोशाक के अनावरण के बारे में नहीं है, बल्कि उन अरबों भारतीयों के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतीक है जो एथलीटों के पीछे एकजुट हैं। आईओए प्रमुख उषा ने कहा कि पेरिस में एथलीटों को सर्वश्रेष्ठ सहायता प्रणाली प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा, हमने डॉ. दिनशॉ पारदीवाला के नेतृत्व में एक मजबूत टीम इकट्ठी की है। इसमें खेल चिकित्सा विशेषज्ञ, कल्याण विशेषज्ञ, पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट और एक नींद वैज्ञानिक शामिल हैं। भारतीय दल में करीब 120 एथलीट शामिल हैं, जिनमें भाला फेंक में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा, 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम और रिकॉर्ड 21 निशानेबाज शामिल हैं।

दक्षिण अफ्रीकी टीम अब भी बदल नहीं पाई दबाव में बिखरने की आदत क्लूजनर से क्लासेन तक वही कहानी टीम ने फिर दोहराई

मुम्बई । दक्षिण अफ्रीकी टीम एक बार फिर दबाव में बिखरने के मिथक को गलत साबित नहीं कर पायी है। टीम को लेकर बड़े मुकाबले में दबाव के बीच बिखरने की जो बातें कहीं जाती रही हैं। वे एक बार फिर टी20 विश्वकप में सही साबित हुई हैं। दक्षिण अफ्रीकी टीम इस टूर्नामेंट में सभी मैच जीतकर फाइनल में पहुंची थी पर इसे बाद भी उसे करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस हार से दक्षिण अफ्रीकी प्रशंसकों के मस्तिष्क में लांस क्लूजनर की यादें फिर ताज हो गयी हैं। ये भी साफ हो गया है कि क्लूजनर से हेनरिक क्लासेन तक हालात नहीं बदले हैं। इसी कारण उसने हाथ में आया हुआ मैच खो दिया। दक्षिण अफ्रीकी टीम को अंतिम 30 गेंदों पर 30 रन की जरूरत थी और 6 विकेट हाथ में थे। उस समय हेनरिक क्लासेन आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे।

आईएल टी20 क्रिकेट लीग में खेलेंगे नरेन , रसेल ओर बोल्ट जैसे दिग्गज

दुबई । संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में टी20 अंतरराष्ट्रीय टी20 लीग अगले साल की शुरुआत में होगी। इस लीग के 13 जनवरी से शुरू होने की संभावना है। इसमें अंतराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले खिलाड़ी ही खेल सकते हैं। ऐसे में इसमें दिग्गज क्रिकेटर सुनील नरेन, आंद्रे रसेल , ट्रेंट बोल्ट, एलेक्स हेल्स, मोईन अली, वनिंदु हसरंगा आदि खेलते हुए नजर आयेंगे। इसमें 6 टीमें भाग लेंगीं और 34 मैच खेले जाएंगे। इसमें सभी टीमें एक-दूसरे के खिलाफ दो-दो मैच खेलेंगी। इसके बाद प्लेऑफ मुकाबले होंगे। इस लीग के दौरान ही दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में टी20 लीग खेली जाएंगी। दक्षिण अफ्रीका की एसए 20लीग 10 जनवरी से 11 फरवरी तक खेली जानी है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग दिसंबर में शुरू होकर 4 फरवरी तक चलेगी जबकि पाक की पीएसएल लीग 9 फरवरी से शुरू हो रहा है।

भयंकर तूफान, एयरपोर्ट बंद, लैंड स्लाइड की चेतावनी... हेरिकेन ने बारबाडोस में मचाई तबाही, कब और कैसे आएगी टीम इंडिया

ब्रिजटाउन, 01 जुलाई (एजेंसियां) ।

बारबाडोस के केंसिंग्टन ओवल स्टेडियम में टीम इंडिया ने इतिहास रचा। उसने साउथ अफ्रीका को रोमांचक फाइनल में 7 रन से हराने के बाद दूसरी बार टी20 विश्व कप की ट्रॉफी उठाते हुए 140 करोड़ भारतीय क्रिकेट फैंस का सपना पूरा किया। टीम इंडिया लगभग 3 महीने से क्रिकेट खेल रही है। खिलाड़ी टी20 विश्व कप खेलने से लगभग 2 महीने तक आईपीएल 2024 खेले और देखा जाए तो इस दौरान वे कभी कभार ही घर गए। अब जब विश्व विजेता होने की जंग जीत ली है तो खिलाड़ी स्वदेश आने को बेसब्र होंगे, लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ा रुकावट तूफान हेरिकेन रोड़ा बनी।

हेरिकेन बेरिल ने मचाई तबाही, बारबाडोस में होटल में बंद टीम इंडिया

हेरिकेन बेरिल के तेज होने के कारण बारबाडोस हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण भारतीय क्रिकेट टीम को अपने होटल के अंदर ही रहना पड़ रहा है। खबर आई थी कि 29 जून को टी20 विश्व कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम के द्वीप राष्ट्र में फंसने की संभावना है। बेरिल के पहुंचने की उम्मीद थी। बेरिल के बारबाडोस में पहुंचने के बाद इसके गंभीर परिणाम होने की आशंका है। रिपोर्ट की मानें तो दूसरा सबसे गंभीर तूफान है।

कर्फ्यू जैसा माहौल, 6 से 9 फीट ऊंची तूफानी लहर का अनुमान

बारबाडोस हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है और कर्फ्यू जैसी स्थिति है, क्योंकि किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। टीम इंडिया के खिलाड़ी होटल में फंसे हैं और लाइन में लगकर खाना खाते नजर आए। वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, बेरिल के 130 मील प्रति घंटे से अधिक की हवाओं के साथ विंडवर्ड द्वीप समूह से टकराने की उम्मीद है।

तूफान केंद्र ने 6 से 9 फीट ऊंची तूफानी लहर और 3 से 6 इंच तक बारिश का अनुमान लगाया है। बारबाडोस में 2004 के बाद सबसे खतरनाक तूफान मौसम विभाग के अनुसार, तूफान के कारण बारबाडोस और विंडवर्ड द्वीप समूह में 3 से 6 इंच

बारिश होने की उम्मीद है। बेरिल का ग्रेनेडा और सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंस के विंडवर्ड द्वीप समूह के पास से गुजरना एक शक्तिशाली कैटिगरी 4 तूफान के रूप में इसे 2004 में आए तूफान इवान के बाद से सबसे शक्तिशाली तूफान बना देगा।

एजेंसी ने कहा कि टोबैगो को रेड लेवल की चेतावनी के तहत रखा गया था। सबसे अधिक खतरा त्रिनिदाद और टोबैगो को है।

बारबाडोस की प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटली ने द्वीप पर सभी गैर-जरूरी व्यवसायों को बंद करने का आग्रह किया था। बारबाडोस मौसम विज्ञान सेवाओं ने कहा कि बेरिल का केंद्र किसी समय द्वीप के लगभग 75 मील दक्षिण में से गुजरने की उम्मीद है। तूफानी हवाएं, भारी बारिश, बाढ़ और लैंड स्लाइड जैसी गंभीर स्थिति आ सकती है।

बारबाडोस में ऐसा रहा है तूफानों का इतिहास उल्लेखनीय है कि यह अब अटलांटिक महासागर का तीसरा सबसे जल्दी आने वाला प्रमुख तूफान है। सबसे पहले 8 जून, 1996 को तूफान अल्मा आया था, उसके बाद तूफान ऑड्रे आया, जो 27 जून, 1957 को प्रमुख तूफान की स्थिति में पहुंच गया था। इस तूफान ने जून में उष्णकटिबंधीय अटलांटिक में बनने वाले सबसे पूर्वी तूफान का रिकॉर्ड पहले ही बना लिया है, जिसने 1933 में बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। मध्य और पूर्वी अटलांटिक पारंपरिक रूप से अगस्त में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं, आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि महासागर के तापमान को गर्म होने और विकासशील प्रणालियों को बढ़ावा देने का समय मिल जाता है।

आईसीसी की विश्वकप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में रोहित सहित छह भारतीय खिलाड़ी शामिल

दुबई, 01 जुलाई (एजेंसियां) ।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने विश्वकप की टीम ऑफ द टूर्नामेंट की घोषणा कर दी है। इसमें रोहित शर्मा, हार्दिक पंड्या सहित छह भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है। हैरानी की बात ये है कि इसमें भारतीय टीम के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को जगह नहीं मिली है जबकि विराट ने टी20 विश्वकप के फाइनल में शानदार पारी खेलते हुए 76 रन बनाये थे। आईसीसी की इस टीम में भारत की ओर से कप्तान रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, के अलावा ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या और अर्शदीप सिंह व जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को भी शामिल किया गया है। अफगानिस्तान के 3 खिलाड़ी, वेस्टइंडीज, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के 1-1 खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया गया है।

वहीं दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज एनरिक नॉर्किया को 12वें खिलाड़ी के तौर पर रखा गया है। दक्षिण अफ्रीक के विश्वकप में 15 विकेट लिए थे।

रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने पहली बार विश्वकप जीता। रोहित ने इस टूर्नामेंट में 3 अर्धशतकों की सहायता से कुल 257 रन बनाए। वहीं विश्वकप फाइनल में शानदार बल्लेबाजी करने के अलावा डेडिड मिलर का कैच पकड़ कर मुकाबला भारतीय टीम की ओर करने वाले सूर्यकुमार यादव को भी टीम में जगह मिली है। जसप्रीत बुमराह ने विश्व कप में कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4.17 की इकोनोमी से रन दिए और 15 विकेट लिए। इसके अलावा युवा अर्शदीप सिंह ने 17 विकेट लेकर इस विश्व कप में रिकॉर्ड बनाया।

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस ने 169 रन बनाने के साथ साथ 10 विकेट भी चटकाए। इस कारण उन्हें भी टीम में जगह मिली है। पंड्या के प्रदर्शन भी गेंद और बल्ले से अच्छा रहा। इस कारण उन्हें भी टीम में जगह मिली है। वहीं अफगानिस्तान की ओर से विश्वकप में शानदार शुरुआत करने वाले रहमनुल्लाह गुरबाज को भी इस टीम में रखा गया है। गुरबाज ने तीन अर्धशतकों की सहायता से 281 रन बनाए थे। गुरबाज ने 124.33 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये। इसके अलावा वेस्टइंडीज के विकेटकीपर निकोलस पूरन को भी इस टीम में शामिल किया गया है। निकोलस ने 228 रन बनाये और उनका स्ट्राइक रेट 146.15 रहा। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने 14 विकेट इस कारण उन्हें भी टीम में जगह मिली है। इसके अलावा अफगान तेज गेंदबाज फजहलक फारूकी ने इस विश्व कप में 17 विकेट लिए।

पंजाब के लिए गर्व का पल, तीन खिलाड़ियों को मिली देश की कमान, क्रिकेट-फुटबॉल और हॉकी की करेंगे कप्तानी

चंडीगढ़, 01 जुलाई (एजेंसियां) ।

भारत ने टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा कर लिया है। 13 साल बाद देश को विश्व कप मिला है। इस जीत से पूरे देश में खुशियां हैं। क्रिकेट टीम को हर कोई बधाई दे रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह के प्रदर्शन पर न सिर्फ पंजाब में पूरे देश में भी चर्चा हो रही है। इस बीच पंजाब के लिए एक और गर्व का पल सामने आया है।

पंजाब के तीन खिलाड़ियों को देश की कमान मिली है। तीनों खिलाड़ी अपनी-अपनी टीम की कप्तानी करेंगे। पंजाब के लिए यह ऐतिहासिक क्षण है। इससे पूरा पंजाब गर्व महसूस कर रहा है। इन खिलाड़ियों को मिली कमान बता दें कि कुछ महीने बाद भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर जाएगी। इसके लिए टीम का ऐलान हो गया है। पंजाब के लाल शुभमन गिल को इसकी कमान मिली है। शुभगमन गिल भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। वहीं, आगामी पेरिस ओलंपिक में हरमनप्रीत सिंह हॉकी टीम की कप्तानी करेंगे।

फुटबॉल टीम की कमान गुरबीर संधू संभालेंगे। पंजाब के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। 6 जुलाई से मैच शुरू पेरिस ओलंपिक 2024 और पैरालंपिक खेल फ्रांस में आयोजित अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। ओलंपिक खेल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होंगे। वहीं, भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा 6 जुलाई से शुरू होगा। इस दिन दोनों टीमें हरारे में पहले टी20 में आमने सामने होंगी। दूसरा टी20 सात जुलाई को हरारे में ही खेला जाएगा। तीसरा मैच 10 को, चौथा 13 को जबकि पांचवां और आखिरी टी20 मैच 14 जुलाई को खेला जाएगा।

अभिषेक शर्मा भी चमके खास बात है कि पंजाब के अभिषेक शर्मा को भी भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली है। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए ओपनिंग करने वाले अभिषेक शर्मा ने आईपीएल 2024 में अपनी ताबतोड़ बल्लेबाजी से सभी को दीवाना बनाया था। मूल रूप से अमृतसर के रहने वाले अभिषेक शर्मा ने आईपीएल के 16 मैचों में 32.27 की औसत और 204.22 के बेहद ही शानदार स्ट्राइक रेट से 484 रन बनाए थे।

गाजीपुर के राजकुमार पाल का भारतीय हॉकी ओलंपिक टीम में सिलेक्शन, पेरिस में दिखाएंगे दमखम

गाजीपुर, 01 जुलाई (एजेंसियां) ।

पेरिस में होने वाले हॉकी ओलंपिक में गाजीपुर के राजकुमार पाल को भारतीय हाकी टीम से खेलने का मौका मिला है. गाजीपुर की सैदपुर के करमपुर गांव के रहने वाले राजकुमार पाल पहले हाकी खिलाड़ी हैं, जिनका चयन ओलंपिक टीम में हुआ है. राजकुमार को अब 2024 में पेरिस में हो रहे ओलंपिक खेलों में प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा. राजकुमार 16 सदस्यीय टीम में मिडफील्डर के तौर पर खेलेंगे. मेघबरन सिंह स्टेडियम के प्रबंधक अनिकेत सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस कर यह जानकारी साझा की।

अनिकेत सिंह ने बताया कि मेघबरन सिंह स्टेडियम के दो खिलाड़ियों राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय का चयन ओलंपिक के लिए हुआ है. ललित उपाध्याय मूलरूप से वाराणसी के रहने वाले हैं. ललित पिछले ओलपिंक में कांस्य पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे. हालांकि ललित ने अपने कॅरियर की शुरुआत इसी स्टेडियम से की थी. वहीं गाजीपुर को राजकुमार पाल के रूप में पहला ओलंपियन मिला है. इसका श्रेय स्टेडियम के संस्थापक स्वर्गीय तेज बहादुर सिंह को जाता है। राजकुमार पाल के दो बड़े भाई जोखन पाल और राजू पाल इसी स्टेडियम के खिलाड़ी रहे हैं. फिलहाल वे स्पोर्ट्स कोटे से सरकारी नौकरी में हैं. राजकुमार पाल के कोच इन्द्रदेव ने बताया कि राजकुमार पाल ने 8 साल की उम्र से खेलना शुरू कर दिया था. बचपन से ही वह बहुत अनुशासित खिलाड़ी रहा है. राजकुमार के अंदर सीखने की ललक शुरू से ही थी. जिसकी वजह से वह लगातार आगे बढ़ता रहा और आज ओलंपिक में जाने वाले गाजीपुर का पहला खिलाड़ी बन गया है।

राजकुमार पाल पिछले चार साल से नेशनल टीम का हिस्सा हैं और इनके बेहतरीन खेल की वजह से ओलंपिक टीम में चयन किया गया है. इससे पहले कई अंतरराष्ट्रीय मैच भी खेले हैं. 2020 में बेल्जियम के खिलाफ अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था. फिलहाल राजकुमार बेंगलुरु में ट्रेनिंग कैम्प अटेंड कर रहे हैं और ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं. 8 जुलाई को राजकुमार हॉलैंड जाएंगे और वहां कुछ प्रैक्टिस मैच खेलेंगे और वहीं से पेरिस के लिए रवाना हो जाएंगे।

जो हो गया उसे छोड़ो, गलतियों से सीखो, मजबूत होकर वापसी करो: सिंधु का ओलंपिक मंत्र

नई दिल्ली, 01 जुलाई (एजेंसियां) ।

पेरिस ओलंपिक में अब एक महीने से भी कम समय रह गया है, इसलिए उम्मीदें अपने चरम पर हैं और प्रशंसकों को उम्मीद है कि दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु इस चतुष्कोणीय ओलंपिक में पदकों की हैट्रिक पूरी करेंगी।

लेकिन, सिंधु की पेरिस यात्रा कठिन रही है क्योंकि चोट के कारण लंबी छुट्टी से वापस आने के बाद वह पिछले साल कोई भी खिताब जीतने में असफल रहीं। इस बीच, उन्होंने अपने दक्षिण कोरियाई कोच पार्क ताए-सांग से नाता तोड़ लिया और मलेशिया के हाफ़िज़ हाशिम को नियुक्त किया, लेकिन वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहने के कारण छह महीने बाद ही वह अलग हो गईं।

निराशाजनक नतीजों की श्रृंखला के कारण सिंधु विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 से भी बाहर हो गईं। उन्होंने धीरे-धीरे गति पकड़ी और रेस टू पेरिस रैंकिंग सूची में 12वें स्थान पर रहने के बाद लगातार तीसरे ओलंपिक के लिए स्थान पक्का कर लिया।

पेरिस गेम्स के लिए टिकट हासिल करने के

बाद, सिंधु ने लगभग एक साल में अपना पहला फाइनल खेला जब वह पिछले महीने मलेशिया मास्टर्स के शिखर मुकाबले में पहुंची जहां वह चीन की वांग झी यी से खिताब हार गईं।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एक मीडिया बातचीत में, जब सिंधु से पूछा गया कि जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर नहीं थीं, तब उन्होंने उस चुनौतीपूर्ण चरण का सामना कैसे किया, तो उन्होंने कहा कि गलतियों से सीखना, जो हुआ उसे छोड़ना और मजबूत होकर वापस आना महत्वपूर्ण है। देखिए, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ऐसे मैच होते हैं जहां कभी-कभी आप आगे रह सकते हैं और कभी-कभी आप हार भी सकते हैं। मलेशियाई मास्टर्स में मेरे साथ ऐसा हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छी स्थिति में नहीं थी, लेकिन मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ खेला और कभी-कभी आप नेतृत्व कर रहे होते हैं और ऐसा होता है और यह ठीक है, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है। एक सवाल के जवाब में कहा, मेरे लिए जब मैं कोई मैच हार जाती हूं या जब आपके सामने कोई और प्रतियोगिता आने वाली होती है, तो मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और मजबूत होकर वापस आएं और जो हो गया उसे छोड़ दें और सिर्फ अगले टूर्नामेंट पर ध्यान केंद्रित करें। मेरा मतलब है, हर कोई एक-दूसरे के खेल को जानता है। बात सिर्फ इतनी है कि उस दिन, जो अच्छा खेलता है और सर्वश्रेष्ठ देता है वह विजेता होता है। इसलिए, मलेशिया मास्टर्स में जो हुआ है, मुझे पता है कि यह थोड़ा दुखद है कि मैं वह जीत हासिल कर सकती थी। मैं 11-3 से आगे थी, यह सिर्फ उन 11 अंकों की बात है और मैं चैंपियनशिप जीत सकती थी लेकिन मुझे लगा कि यह मेरा दिन नहीं था क्योंकि मैंने सब कुछ किया और यह काम नहीं आया, लेकिन, यह ठीक है, मैंने जीत हासिल की, कुछ गलतियों से बहुत कुछ सीखा। इस जनवरी में सिंधु ने पेरिस 2024 से पहले अपने नए गुरु प्रकाश पादुकोण के करीब रहने के लिए अपना आधार हैदराबाद से बेंगलुरु स्थानांतरित कर लिया और अपने नए इंडोनेशियाई कोच एगस सांतोसो के साथ प्रशिक्षण शुरू किया। सांतोसो को भारत में कोचिंग का पूर्व अनुभव है। उन्होंने 2020 और 2021 में किदांबी श्रीकांत और बी साई प्रणीत सहित भारतीय एकल खिलाड़ियों के कोच के रूप में कार्य किया और टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए भारतीय बैडमिंटन दल के साथ थे। सिंधु ने कहा, मैं जनवरी से एगस के साथ खेल रही हूं, जाहिर है, कुछ महीने पहले और अब तक यह अच्छा रहा है। एक कोच और एथलीट को एक-दूसरे को समझने में निश्चित रूप से समय लगता है। इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं और एगस पहले से ही पुरुष (एकल) के लिए भारत में थे इसलिए वह जानते हैं कि यह कैसे काम करता है, यह पहली बार है जब मैं और एगस एक साथ काम कर रहे हैं और यह बहुत मजेदार रहा है।

विवादों से जूझ रहे बोइंग ने स्पिरिट एयरोसिस्टम्स के अधिग्रहण का ऐलान किया, 4.7 अरब डॉलर में सौदा

नई दिल्ली,01 जुलाई (एजेंसियां) । **विवादों से जूझ रही हवाई जहाज निर्माता कंपनी बोइंग ने 4.7 अरब डॉलर में विनिर्माण फर्म स्पिरिट एयरोसिस्टम्स के अधिग्रहण की घोषणा की है। स्पिरिट एयरोसिस्टम्स पहले से ही बोइंग की विनिर्माण श्रृंखला का हिस्सा है।**

वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित बोइंग ने देर रात एक बयान में इस खरीदारी की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि इस अधिग्रहण का इक्विटी मूल्य 4.7 बिलियन डॉलर यानी प्रति शेयर 37.25 डॉलर है।

सौदे का कुल मूल्य लगभग 8.3 बिलियन डॉलर है, जिसमें स्पिरिट की ओर से रिपोर्ट किया गया शुद्ध ऋण शामिल है।

स्पिरिट ने अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर भी इस सौदे की घोषणा की है। बोइंग के अध्यक्ष और सीईओ डेव कैलहोन ने बयान में कहा, हमारा मानना है कि यह सौदा उड़ान भरने वाले लोगों, हमारे एयरलाइन ग्राहकों, स्पिरिट और बोइंग के कर्मचारियों, हमारे शेयरधारकों और देश के सर्वोत्तम हित में है।

स्पिरिट एयरोसिस्टम्स पहले भी बोइंग के स्वामित्व में था और अब अधिग्रहण के बाद एक बार फिर बोइंग के तहत कंपनी के आने से विमान निर्माता के विमानों की गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार होगा। बोइंग फिलहाल नियामकों और कांग्रेस की जांच के दायरे में है। कैलहौन ने कहा, स्पिरिट को फिर से एकीकृत करके, हम अपनी सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों सहित अपने वाणिज्यिक उत्पादन प्रणालियों और हमारे कार्यबल को समान प्राथमिकताओं, प्रोत्साहनों और परिणामों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। यह फैसला सुरक्षा और गुणवत्ता पर केंद्रित हैं।

न्यूज़ ब्रीफ

100 रुपए पर आया आईपीओ, 311 पर हुई लिस्टिंग, एक ही दिन में निवेशकों को 211 फीसदी का मुनाफा

नई दिल्ली। शिवालिक पावर कंट्रोल के आईपीओ ने बंपर रिटर्न देकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है। इसका आईपीओ 100 रुपये के इश्यू प्राइस पर आया था और लिस्टिंग 311 रुपये पर हुई। इसका मतलब कि आईपीओ निवेशकों को 211 फीसदी का बंपर रिटर्न मिला है। शिवालिक पावर का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 24 जून से 26 जून तक के लिए खुला था। इश्यू 250 गुना से अधिक सब्सक्राइब हुआ। कंपनी ने आईपीओ में 64.32 लाख फ्रेश शेयर बेचे। वह आईपीओ से मिली रकम का इस्तेमाल अन्य कंपनियों को खरीदने के लिए करेगी। साथ ही, पूंजीगत व्यय समेत दूसरे कामकाजी खर्च भी देखे जाएंगे। क्या करती है शिवालिक पावर शिवालिक पावर कंट्रोल इलेक्ट्रिक पैनल बनाती है। इनका इस्तेमाल टांसफार्मर और जनरेटर जैसे विद्युत उपकरणों में किया जाता है। शिवालिक ट्रेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, जो पिछले दो दशक से बिजनेस कर रही है। इसका क्वालिटी, डिजाइन और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर दमदार पकड़ है। शिवालिक के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में पीसीसी पैनल्स, आईएमसीसी पैनल्स, स्मार्ट पैनल्स, एमसीसी पैनल्स, डीजी सिंक्रनाइजेशन पैनल्स और आउटडोर पैनल्स जैसी चीजें भी शामिल हैं। इसके प्रोडक्ट नेपाल, बांग्लादेश, युंगाडा, केन्या, नाइजीरिया और अल्जीरिया समेत 15 से अधिक देशों में निर्यात होते हैं। कैसे है कंपनी की वित्तीय सेहत शिवालिक की वित्तीय सेहत लगातार बेहतर हो रही है। पिछले तीन साल से इसके मुनाफे में जोरदार ग्रोथ देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का शुद्ध मुनाफा 67.28 लाख रुपये रहा। वित्त वर्ष 2022 में यह 1.75 करोड़ रुपये और फिर वित्त वर्ष 2023 में 7.16 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना 25 फीसदी से अधिक की चक्रवृद्धि दर से बढ़कर 82.69 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। अगर सिर्फ पिछले वित्त वर्ष यानी 2023-24 की बात करें, इसकी अप्रैल-दिसंबर तिमाही में शिवालिक को 7.60 करोड़ रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ। वहीं रेवेन्यू 63.79 करोड़ रुपये रहा।

भारत सबसे बड़ा विवाह स्थल, हर साल होती हैं एक करोड़ तक शादियां:जेफरीज की रिपोर्ट में दावा

नई दिल्ली । भारत दुनिया का सबसे बड़ा विवाह स्थल है। यहां हर साल 80 लाख से एक करोड़ शादियां होती हैं, जबकि चीन में 70-80 लाख और अमेरिका में 20-25 लाख विवाह होते हैं। खास बात है कि आम देशवासी शिक्षा (स्नातक तक) की तुलना में विवाह समारोह पर दोगुना खर्च करते हैं। अमेरिकी जैसे देशों में यह खर्च शिक्षा की तुलना में आधे से भी कम है। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय विवाह उद्योग का आकार करीब 10 लाख करोड़ रुपये का है। यह अमेरिका के विवाह उद्योग का लगभग दोगुना है। हालांकि, चीन की तुलना में छोटा है। अमेरिका में विवाह उद्योग का आकार 5.84 लाख करोड़ रुपये (70 अरब डॉलर) का है, जबकि चीन में यह 14.2 लाख करोड़ (170 अरब डॉलर) का है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय शादी कई दिनों तक चलती हैं और साधारण से लेकर बेहद भव्य तक होती हैं। इसमें क्षेत्र, धर्म और आर्थिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाख करोड़ है भारतीय विवाह उद्योग का आकार, अमेरिका की तुलना में करीब दोगुना भारत में एक शादी पर औसतन 12.50 लाख रुपये (15,000 डॉलर) खर्च होते हैं। यह रकम प्रति व्यक्ति या घरेलू आय का कई गुना है। शादियों में होने वाले कुल खर्च में दुल्हन के आभूषणों की हिस्सेदारी आधे से अधिक होती है।

सस्ता हुआ कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर तेल कंपनियों ने 30 रुपए घटाए दाम

नई दिल्ली । कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। तेल विपणन कंपनियों की ओर से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करने का फैसला किया गया है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की कटौती की गई है। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की खुदरा बिक्री कीमत 1646 रुपये हो गई है। हाल के महीनों में लगातार वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। 1 जून को 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 69.50 रुपये की कटौती की गई थी, जिससे कीमत घटकर 1,676 रुपये हो गई थी। इससे पहले 1 मई, 2024 को प्रति सिलेंडर 19 रुपये की एक और कटौती हुई थी।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

महिला को घसीट...

अमित मालवीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं। दूसरी तरफ टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने उम्मीद के मुताबिक ही बयान दिया है। हमीदुल ने पीड़ित महिला को दुष्ट जानवर बताया और अपने चमचे ताजेमुल को इस्लाम का हवाला देकर इंसाफ करने वाला बताया। इस बयान पर आम नागरिकों को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन हमीदुल जैसे लोगों को शर्म नहीं आती। बंगाल पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स से रश्मि सामंत का वह वीडियो हटाने को कहा है, जिसमें ताजेमुल द्वारा की जाने वाली बर्बर मारपीट की घटना कैद है। हालांकि घटना का वीडियो भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय और सीपीआई के मोहम्मद सलीम ने भी पोस्ट किया। यह वीडियो देख कर आपको लगेगा कि यह भारत की नहीं, बल्कि किसी खाड़ी देश या अफगानिस्तान की घटना है। एक महिला को और एक पुरुष को घेरा बनाकर अमानुषिक तरीके से सड़क पर घसीट घसीट कर पीटा जाना भारत में तो असंभव माना जाता है। लेकिन असलियत यही है कि यह दर्दनाक दृश्य भारत का है।

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में खुलेआम भीड़ के सामने एक महिला की बर्बर पिटाई का दृश्य पूरे देश में निंदा का विषय बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में शरीयत कानून लागू हो गया है? ऐसा इसीलिए, क्योंकि जिस ताजेमुल ने इस घटना को अंजाम दिया है वह इलाके में शरीयत कानून के तहत त्वरित सजा और न्याय देने के लिए मुकर्रर किया गया है। पुलिस और अदालत की उसके सामने कोई कीमत नहीं। वह चोपरा के टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान का चमचा है।

भाजपा और सीपीआई (एम) - दोनों ही विपक्षी दलों ने कहा कि ताजेमुल तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। वीडियो में एक महिला के अलावा एक पुरुष को भी जमीन पर पटक कर पीटे जाते हुए देखा गया। संवेदनहीनता की पराकाष्ठा देखिए कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक हमीदुल रहमान ने अपने करीबी का बचाव करते हुए जिस महिला की पिटाई हुई उसे ही दुष्ट जानवर कह दिया। साथ ही उसने कहा कि उक्त महिला की गतिविधियां असामाजिक थीं। चोपरा के विधायक ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र के हिसाब से कुछ संहिता और न्याय होते हैं।

उधर, इस्लामपुर के एसपी जॉबी थॉमस के ने कहा कि पुलिस ने सोशल मीडिया पर वीडियो देखने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन्होंने घटना की जांच कराने की बात कही। टीएमसी विधायक हमीदुल रहमान ने कहा कि पीड़िता की तरफ कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई गई है। दहशतगर्द समुदाय के बीच फंसी कोई महिला वहां से निकल कर थाने में एफआईआर कैसे दर्ज कराए, यह आसानी से समझा जा सकता है। यह बात पुलिस ने भी मानी है कि उस क्षेत्र में सालिशी सभा नाम से समानांतर इस्लामी अदालत (कंगारू कोर्ट) चलती है, जहां न्याय और सजा दी जाती है।

अमित मालवीय ने घटना का वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासन का यह एक भयावह चेहरा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि भीड़ के बीच एक महिला और एक पुरुष को जमीन पर पटक कर पीटा जा रहा है। हमलावर की पहचान ताजेमुल के रूप में हुई है, जिसे स्थानीय लोग जेसीबी नाम से बुलाते हैं। वह त्वरित न्याय देने के लिए जाना जाता है। उसकी नजर में पुलिस-कोर्ट की कोई हैसियत नहीं। अमित मालवीय ने बताया कि चोपरा के विधायक हमीदुल रहमान का वो करीबी (चमचा) है। मालवीय ने कहा, भारत को टीएमसी द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में शरीयत अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेशखाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था का कोई नामोनिशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगी या उसका बचाव करेंगी जैसे उन्होंने शेख शाहजहां के लिए खड़ी हुई थीं? संदेशखाली में जनजातीय समाज की महिलाओं का यौन शोषण करने वाले शेख शाहजहां और उसके गुर्गों को बचाने के लिए बंगाल सरकार ने दिन-रात एक कर दिया था।

महिला और युवक को बर्बरता से पीटे जाने की घटना उत्तर दिनाजपुर स्थित चोपरा विधानसभा क्षेत्र के लक्ष्मीकांतपुर की है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्लू) को भी इससे अवगत करा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में इस तरह से एक इस्लामी कट्टरपंथी द्वारा कंगारू कोर्ट चलाए जाने का वीडियो आने के बाद एक बार फिर से राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा के कई कार्यकर्ता अब तक पार्टी दफ्तर में परिवार के साथ रहने को मजबूर हैं। गांव के गांव खाली हो गए हैं। वीडियो में दिख रहा है कि ताजेमुल महिला को डंडे से मार रहा था। महिला बार-बार उसे छोड़ने की गुहार लगा रही थी लेकिन ताजेमुल रुकने का नाम नहीं ले रहा। उसने महिला को तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गई। इसके बाद उसने महिला के अचेत होते ही उसे लात मारी। वीडियो में महिला के अलावा एक अन्य व्यक्ति को भी पीटते हुए देखा जा रहा है।

महिला से मारपीट मामले की वीडियो सामने आने के बाद भाजपा और सीपीआई (एम) - दोनों ही विपक्षी दलों ने दावा किया था कि ताजेमुल के संबंध तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है। हालांकि, तृणमूल कांग्रेस ने भी इस घटना के बाद ताजेमुल से अपना पल्ला झाड़ लिया है। टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद शांतनु सेन ने कहा, पार्टी ने कभी ऐसे हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया है। भाजपा को इस मामले में कुछ बोलने से पहले अपने राज्यों में हालात देखने चाहिए। वायरल वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर बड़ी तादाद में इसकी आलोचना हो रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूर्व अध्यक्ष रश्मि सामंत ने ऐसी हरकत को तालिबानी हरकतों से जोड़ा और कहा कि ये अफगानिस्तान नहीं बल्कि बंगाल है। एक्स से रश्मि का ट्वीट और वीडियो हटाने के लिए बंगाल पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रश्मि ने कहा, बंगाल में एक महिला की आवाज उठाने पर अकाउंट बंद करवाने की कोशिश हो रही है। तानाशाही जिंदा है और फल-फूल भी रही है।

बंगाल से आए दिन महिलाओं को लेकर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो भद्र लोक को लज्जा में डालने के लिए पर्याप्त हो सकती हैं। मगर भद्र लोक का प्रदेश कहे जाने वाले बंगाल में इन घटनाओं को लेकर बंगाली भद्रलोक और लुटियन जोन के पत्रकारों के साथ ही, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जैसी बातें करने वाली प्रियंका गांधी भी एकदम चुप हैं। सबसे बढ़कर बंगाल के सत्ताधारी राजनेताओं का जो रवैया सामने है, वह अत्यंत दुखद और शर्मनाक है। जो लोग संविधान बचाओ की बातें करते हैं, उनके प्रदेश में बर्बर मुस्लिम कानून कब और कैसे लागू हो गया कि वहां कोई भी कट्टरपंथी अधर्मी महिलाओं को सड़क पर बर्बतापूर्वक पीटे और पूरा प्रदेश तमाशा देखता रहे?अभी बहुत दिन नहीं हुए जब ममता बनर्जी समेत तमाम विपक्षी नेता अपने अपने हाथ में संविधान की कॉपी लेकर यह कहते हुए चुनाव प्रचार करते पाए जाते थे कि वे संविधान की रक्षा करने के लिए यह चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं तो मोदी जी संविधान बदल देंगे। मगर उनके ही प्रदेश में संविधान बदला ही नहीं गया है, बल्कि संविधान को अस्वीकार कर दिया गया, यह उन्हें दिख नहीं रहा? पश्चिम बंगाल में 88 फास्ट ट्रैक अदालतों में से 55 अदालतें केवल महिलाओं के लिए हैं, यह कहने वाली ममता बनर्जी आज चुप क्यों है? हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो जारी हुआ था जिसमें भाजपा की एक मुस्लिम कार्यकर्ता रोसोनारा खातून को कूचबिहार में उनके घर से बाहर निकालकर निर्वस्त्र कर दिया गया था। इस विषय में भी बेशर्म संविधान-रक्षकों ने चुप्पी साधे रखी। संदेशखाली में भी पीड़ित महिलाओं को तत्काल इंसाफ की चर्चा रही थी। उस कांड में पूरे देश ने देखा था कि कैसे आरोपी को बचाने के लिए महिला मुख्यमंत्री ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था।

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में हुई यह घटना एक महिला के साथ महज मारपीट का मसला नहीं है। यह भारतीय संविधान को क्षत-विक्षत करने का मामला है। यह घटना संसद को दी गई सीधी चुनौती है। देश में विधि द्वारा स्थापित भारतीय संविधान का शासन चलेगा या अब यहां बर्बर इस्लामिक आचार-विचार चलेंगे? देश के नागरिक यह सवाल पूछ रहे हैं।

जो खुद...

बड़े कृत्य को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेता ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वह हिंसा करते हैं, हिंसा की बात करते हैं। इनको शायद मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग खुद को गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वे सभी लोग हिंसा करते हैं। हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना अनुचित और असंसदीय है। इसके लिए राहुल को माफी मांगनी चाहिए। शाह ने कहा, मैं उनसे एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभयमुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले लें। गुरुनानक साहब की अभयमुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले लें। अभय की बात इनको करने का कोई हक नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत किया है। लाखों लोगों को जेल में डाला गया। वैचारिक आतंक कभी था तो आपका आपतकाल था।

अपरिपक्व बुद्धि...

राहुल गांधी ने हिंदुओं पर जो टिप्पणियां की हैं वह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहुलुहान करने जैसा है। भारत माता को लहुलुहान करने के लिए उन्हें माफी मांगना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी को लेकर जिन लोगों ने कुछ भ्रम पाला होगा, उनका भ्रम टूट गया होगा। कांग्रेस को राहुल गांधी को भारत की जनता से माफी मांगने के लिए कहना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हिंदू भारत की मूल आत्मा है, हिंदू सहिष्णुता, उदारता और कृतज्ञता का पर्याय है। यह बात स्वयं को एक्सीडेंटल हिंदू कहने वाली जमात के शहजादे को कैसे समझ में आएगी। उन्होंने कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में डूबी हुई बताया।

अयोध्या में ...

चरित्र को एक बार फिर से बेनकाब कर दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में झूठे और गुमराह करने वाले वक्तव्य देते हुए देखा है। संविधान का गला घोंटने वाले लोगों ने संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे से के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। 1 लाख का फर्जी बॉन्ड भरवा कर भारत की माताओं और बहनों को गुमराह करने का कार्य किया। आज फिर इन्होंने झूठा बयान दिया है जो कि अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है।

सीएम योगी ने कहा कि हर कोई जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से किसने वंचित किया है। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था, बल्कि सरयू को भी रक्तरंजित किया था। आज जब अयोध्या अपने वैभव को पुन:प्रतिष्ठापित करते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो कांग्रेस इसे कैसे अच्छा मान सकती है। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। सच यह है कि 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के लिए अयोध्या वासियों को उपलब्ध कराए हैं। चाहे रामपथ हो, भक्तिपथ हो, जन्मभूमि पथ हो या एयरपोर्ट हो, जिसकी जमीन, दुकान, मकान इसमें शामिल थी, उन्हें मुआवजा दिया गया है। जिनके पास पीछे दुकान बनाने की जगह थी, उनके दुकान बने हैं, जिनके पास स्पेस नहीं था उन्हें मल्टी लेवल कॉम्प्लेक्स बनाकर दुकान देने के कार्य को आगे बढ़ाया गया। राहुल का बयान सत्य से परे झूठ का पुलिंदा हैं। यह यूपी और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है। यह भारत और अयोध्या की छवि को खराब करने की उस मानसिकता का हिस्सा है जो ये एक्सीडेंटल हिंदू आजादी के बाद से लगातार करते आ रहे हैं।

पुराना कानून...

इन विधेयकों को लोकसभा ने 20 दिसंबर 2023 को और राज्यसभा ने 21 दिसंबर 2023 को मंजूरी दे दी। राज्यसभा में विधेयकों को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किए जाने के बाद ध्वनि मत से पारित किया गया था। इसके बाद 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति से मंजूरी के बाद विधेयक कानून बन गए। लेकिन इनके प्रभावी होने की तारीख 1 जुलाई 2024 रखी गई थी। संसद में तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इनमें सजा देने के बजाय न्याय देने पर फोकस किया गया है।

तीन नए आपराधिक कानून लागू होने पर पुडुचेरी की पूर्व एलजी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि इससे मुझे जो सबसे बड़ा लाभ दिखाई देता है, वह यह है कि इससे पुलिस को जवाबदेही, पारदर्शिता, तकनीक, पीड़ितों के अधिकार, अदालतों में त्वरित सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुनः प्रशिक्षण मिल रहा है।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत हर केस की जांच वैज्ञानिक व निष्पक्ष तरीके से होगी। इसके लिए हर पुलिसकर्मी को अपने मोबाइल पर ई-प्रमाण ऐप डाउनलोड करना जरूरी होगा। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक, ऐप के जरिए मौके से जब्त सामान, निरीक्षण आदि की ऑडियो-वीडियो बनानी होगी। इन साक्ष्यों को 48 घंटे में अदालत में पहुंचाना होगा। दिल्ली पुलिसकर्मियों को कानून की धाराएं और ऐप की जानकारी हर जिला कार्यालय में दी जा रही है।

नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना अनिवार्य है, ताकि गवाहों की सुरक्षा व सहयोग सुनिश्चित की जाए और कानूनी प्रक्रियाओं की विश्वसनीयता व प्रभाव बढ़ाया जाए। वहीं, बीएनएस में महिलाओं व बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच को प्राथमिकता मिलेगी। इसके तहत मामले दर्ज किए जाने के दो माह के भीतर जांच पूरी की जाएगी। पीड़ितों को 90 दिन के भीतर मामले की प्रगति पर नियमित रूप से जानकारी पाने का अधिकार होगा। पीड़ित महिलाओं व बच्चों को सभी अस्पतालों में निशुल्क प्राथमिक उपचार या इलाज मुहैया कराया जाएगा।

नए कानूनों के तहत किसी मामले के जांच अधिकारी को वीडियो तुरंत ऐप पर अपलोड करनी होगी। वीडियो को लोड करने पर ऐप में यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर यानी वेब एड्रेस (यूआरएल) और हैश वैल्यू दिखाई देगी। इनका उल्लेख केस डायरी में करना अनिवार्य होगा। आम आदमी हो या पुलिसकर्मी बीएनएस की धारा 36 (4) के तहत यह लिखकर देगा कि वीडियो के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है।

धारा 105 - ऐप वाले मोबाइल से ऑडियो-वीडियो के जरिए तलाशी और जब्ती की रिकॉर्डिंग की जाएगी। 173 (1) (2) (बी)- संज्ञेय मामलों में सूचना रिकार्ड करने के अलावा असाधारण परिस्थितियों में पीड़िता और शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम पीड़ितों से जुड़े मामले में तुरंत वीडियोग्राफी की जाएगी। 185 (2)- जांच के दौरान तलाशी कार्रवाई की वीडियोग्राफी ऐप से होगी। 176 (3)- सात वर्ष या अधिक सजा वाले अपराधों में वीडियोग्राफी की जाएगी। 180 (3)- पुलिस द्वारा गवाह की जांच, ऑडियो-वीडियो की गई रिकॉर्डिंग। ऐप में एफआईआर नंबर, वर्ष, डीडी नंबर, दिनांक, जिला, यूनिट, पुलिस स्टेशन का नाम और ऑडियो-वीडियो की जानकारी दर्ज होगी।

वीडियो बनाने के बाद संबंधित विवरण यानी बोले गए शब्दों को भी लिखा जाएगा। इसके अतिरिक्त वीडियो नोट भी जोड़े जा सकते हैं और सेव बटन दबाकर उन्हें ऐप में सुरक्षित रखा जा सकेगा। अपलोड किए गए साक्ष्य टैब में देखे जा सकते हैं। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का अधिकार मिलेगा। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहयोग मिल सकेगा। इसके अलावा गिरफ्तारी विवरण पुलिस थानों और जिला मुख्यालयों में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाएगा, ताकि गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार और मित्र महत्वपूर्ण सूचना आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

पीड़िता को अधिक सुरक्षा देने व दुष्कर्म के किसी अपराध के संबंध में जांच में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए पीड़िता का बयान पुलिस की ओर से ऑडियो-वीडियो के जरिए दर्ज किया जाएगा। महिलाएं, पंद्रह वर्ष की आयु से कम उम्र के बच्चे, 60 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों, दिव्यांग या गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को पुलिस थाने आने से छूट मिलेगी और वे अपने निवास स्थान पर ही पुलिस सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

नए कानूनों का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले दिल्ली पुलिस के जवानों का कहना है कि घटनास्थल पर साक्ष्यों की प्रक्रिया को पूरा करने में दिक्कत आ सकती है। जवानों ने नाम उजागर नहीं करने के शर्त पर बताया कि नए कानून में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत घटनास्थल, तलाशी लेने और जब्ती करने के दौरान की वीडियोग्राफी अनिवार्य है, लेकिन कई जगहों पर हालात ऐसे होते हैं, जहां पुलिसकर्मी को अपनी पहचान उजागर किए बिना ही कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है।

अपराधियों के पकड़ने के साथ-साथ हथियार भी बरामद किए जाते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी हथियार लेकर आए बदमाश को पकड़ने के दौरान वीडियोग्राफी करेगा तो उसे पकड़ पाना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे में घटनास्थल पर वीडियोग्राफी करना पुलिसकर्मियों के लिए भी घातक होगा।द्वारका जिले में तैनात एक हवलदार ने बताया कि किसी थाना इलाके में कुछ देर के अंतराल पर झपटमारी की कई वारदातें होती हैं। साथ ही, अन्य घटनाएं भी होती हैं। इन मामलों में एक ही जांच अधिकारी को कई मामले सौंपे जाते हैं।

ऐसे में जांच अधिकारी के लिए सभी घटनास्थलों पर पहुंचना, वीडियोग्राफी करना और मामले की जांच करना एक साथ संभव नहीं हो पाएगा। घटना होने के बाद जांच अधिकारी से आला अधिकारी घटनास्थल के हालात के बारे में भी जानकारी लेते हैं, ऐसे में मोबाइल से वीडियो बना रहे जांच अधिकारी के लिए यह सब करना संभव नहीं हो पाएगा। एक सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि दिल्ली के कुछ ऐसे इलाके हैं, जहां छोटे झगड़ों के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पथराव हो जाता है। ऐसे में जांच अधिकारी साक्ष्य के लिए वीडियोग्राफी करेगा या फिर हालात पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा।

भारतीय न्याय...

इससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही थी। उप-निरीक्षक ने उसे रेहड़ी हटाने के लिए कहा। लेकिन रेहड़ी मालिक ने अपनी मजबूरी बताई। वहां से नहीं जाने पर पुलिस कर्मी ने रेहड़ी वाले के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और आमजन के आने जाने में दिक्कत करने का मामला दर्ज किया है।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने बताया कि पुराने मामलों को आईपीसी के तहत निपटाया जाएगा। एक जुलाई से जब नए मामले दर्ज किए जाएंगे, तो उन पर बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धाराएं लागू होंगी। सभी को इन धाराओं का पालन करना होगा। अब नए मामलों को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धाराओं के तहत निपटाया जाएगा।

झारखंड के ...

जिन बूथ पर बढ़ोतरी हुई है, उनमें से अधिकांश गंगा के पार दियारा क्षेत्र में स्थित हैं और इनकी सीमा पश्चिम बंगाल से सटी हुई है।

राजमहल विधानसभा में वोटरों की संख्या में एकाएक बढ़ोतरी को लेकर स्थानीय भाजपा विधायक अनंत ओझा ने राज्य के चुनाव आयोग से शिकायत की है। विधायक अनंत ओझा ने इस मामले में जानकारी भी साझा की है। विधायक ओझा ने बताया कि 2014 से 2019 के बीच जिन इलाकों में 9000 वोट बढ़ा था वहां 2019 से 2024 के बीच 24000 वोट बढ़ गया, जो कि आशंकित करता है। ओझा ने बताया कि उनकी विधानसभा में जहां पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाकों में वोट बेतहाशा बढ़े हैं, वहीं हिंदू बहुल बूथ पर यह वोट कम हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 17 ऐसे बूथ हैं, जहां हिंदुओं के वोट पिछले पांच वर्ष में घट गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव में कई ऐसे हिंदू वोटर थे, जिनके पास वैध मतदाता पहचान पत्र होने के बाद भी उन्हें वोट नहीं डालने का मौका मिला। उनका नाम लिस्ट से गायब था।

विधायक ओझा ने बताया कि ऐसे वोट न डाल पाने वाले मामले बड़ी संख्या में हैं और इनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो खुद उपमुखिया हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर हमने राज्य चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव आयोग से 73 ऐसे बूथ की शिकायत की गई है।

अब चुनाव आयोग इस विषय में जांच करने जा रहा है। मतदाताओं के भौतिक सत्यापन के कयास भी इस मामले में लगाए जा रहे हैं। यह शक जताया जा रहा है कि बांग्लादेशी अवैध घुसपैठिए इस इलाके में बंगाल के रास्ते आकर कब्जा कर रहे हैं। इसी को लेकर चिंताएं और बढ़ गई हैं। इस मामले में राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी प्रश्न उठे हैं। विधायक अनंत ओझा ने कहा है कि स्थानीय कर्मचारियों ने इस मामले में लापरवाही बरती है, अगर वह ऐसा न करते तो न ही वोट बेतहाशा बढ़ते और न ही हिंदू वोटर वो न डाल पाने की शिकायतें करते।

भारत विरोधी एजेंडा...

जिसके कारण अब वह नौकरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस प्रशासन ने कहा है कि अगर उसे टाटा एजुकेशन ट्रस्ट से पैसा मिल गया तो इन लोगों को नौकरी पर वापस बुला लिया जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो इनकी नौकरी चली जाएगी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इससे पहले भी कई बार विवादों में रहा है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में जांच करते हुए बताया था कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के कुछ छात्रों को आतंकी संगठन भाकपा (माओवादी) ने भर्ती किया था। यह संगठन इनसे आगे आतंकी गतिविधियां करवाना चाहता था। इनके पकड़े जाने पर छात्र होने के आधार पर सहानुभूति बटोरने की भी योजना बनाई गई थी। इन छात्रों को भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपियों ने भर्ती किया था। यह चाहते थे कि भारत में एक समानांतर सरकार खड़ी की जाए। एनआईए ने यह सारी जानकारी कोर्ट में दी थी।

गौरतलब है कि भाकपा (माओवादी) भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। यह भारत में नक्सलवाद के सहारे दशकों से आंतरिक सुरक्षा का खतरा बना हुआ है। इस संगठन के कारण हजारों अर्धसैनिक और पुलिस बलों समेत आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के भीतर वामपंथी जहर लंबे समय से पसरा हुआ है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के कुछ छात्रों ने बताया था कि पुलवामा हमले में 40 जवानों के मारे जाने के बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के एक व्हाट्सऐप ग्रुप में भारतीय सेना के जवानों पर निर्दोषों की हत्या और रेप करने का आरोप लगा कर उनकी वीरगति का मजाक उड़ाया गया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का एक छात्र इन जवानों के मारे जाने पर हंस रहा था।

टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के भीतर लगातार देश विरोधी कृत्य भी होते रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री मोदी को गाली दिए जाने वाले पोस्टर छात्र अपने कमरों पर लगाते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्रों ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। यह लोग बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में प्रताड़ित होने वाले हिंदुओं को भारत में नागरिकता दिए जाने पर गुस्सा थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के छात्र संगठन ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने को लेकर भी प्रलाप किया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के भीतर पूर्वोत्तर को भारत से काटने की बात करने वाले शरजील इमाम के समर्थन में भी नारे लगे थे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में भारत को तोड़ने की बातें खुले तौर पर चलती आई हैं। फरवरी 2020 में एक समीक्षा कार्यक्रम के दौरान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में कश्मीर को आजाद करो, कश्मीर पर से कब्जा हटाओ जैसे पोस्टर दिखाई दिए थे। इन्हें कलाकारी के नाम पर लगाया गया था। इनमें सीएए-एनआरसी हटाने की बात कही गई थी। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में छपने वाले रिसर्च पेपरों में भी लगातार कश्मीर पर जहर उगला जाता रहा है। प्रगतिशील होने का दावा करने वाले वामपंथी यह जहर फैलाते रहे हैं।

ऐसे ही एक रिसर्च पेपर में अनन्या कुंडू नाम की एक रिसर्चर ने लिखा था, भारत ने कश्मीर पर कब्जा करने के लिए यहां की आवाजों को दबाया और नैरेटिव को नियंत्रित किया। कश्मीर की कहानी कश्मीर नहीं, भारत ने लिखी। आज जिस कश्मीर को हम जानते हैं, वो भारतीय सोच के हिसाब से ही। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा हुई। पितृसत्तात्मक भारतीय सेना कश्मीरी समाज को तोड़ने के लिए महिलाओं के शरीर को निशाना बनाती है।

4 शुभ योग में आज मनाई जाएगी योगिनी एकादशी

सनातन धर्म में एकादशी तिथि को बेहद शुभ माना गया है। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। एक कृष्ण और दूसरा शुक्ल पक्ष में। धार्मिक मान्यता है कि एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करने से जातक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। साथ ही सभी मुरादें पूरी होती हैं। जुलाई के महीने में योगिनी एकादशी और देवशयनी एकादशी पड़ेगी। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जगत के नाथ भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन योगिनी एकादशी मनाई जाती है। वर्ष 2024 में 02 जुलाई को योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी पर वैष्णव समाज के लोग व्रत रख विधि-विधान से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं। साथ ही शुभ कार्यों में सिद्धि पाने के लिए विशेष उपाय भी करते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। योगिनी एकादशी पर 4 शुभ योग का निर्माण हो रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सच्चे मन से एकादशी व्रत करने से जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को यह व्रत जरूर रखना चाहिए।

ज्योतिषाचार्य ने बताया कि साल में 24 एकादशी के व्रत रखे जाते हैं। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन उनकी पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती हैं। ऐसे में कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं, जो बेहद कठिन होता है। इस दिन को लेकर मान्यता है कि जो भी एकादशी का व्रत रखता है, उसपर भगवान विष्णु के साथ-साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में आषाढ़ माह में आने वाली योगिनी एकादशी का महत्व अधिक बढ़ जाता है। आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार 2 जुलाई 2024 के दिन ये व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा-अर्चना करने पर पापों से मुक्ति मिलती हैं। ये भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से 88 हजार ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है।

डॉ. अनीष व्यास
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक
पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान,जयपुर-जोधपुर
मो.9460872809

योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 01 जुलाई को सुबह 10:26 मिनट पर शुरू होगी। वहीं, इसका समापन 02 जुलाई को सुबह 08:42 मिनट पर पर होगा। ऐसे में 02 जुलाई को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा।

धृति योग

योगिनी एकादशी पर धृति योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन धृति योग सुबह 11:17 मिनट तक है। इसके बाद शूल योग का निर्माण होगा। धृति योग में भगवान विष्णु की पूजा करना परम फलदायी होगा।

त्रिपुष्कर योग

योगिनी एकादशी तिथि पर त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 08:37 मिनट से हो रहा है और समापन 03 जुलाई को सुबह 04:40 मिनट पर होगा।

सर्वार्थ सिद्धि योग

योगिनी एकादशी तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। इस योग का निर्माण सुबह 05:27 मिनट से हो रहा है और समापन 03 जुलाई को सुबह 04:40 मिनट पर होगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी।

शिववास योग

योगिनी एकादशी पर शिववास योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन भगवान शिव सुबह 08:42 मिनट तक कैलाश पर विराजमान रहेंगे। इसके बाद नंदी पर सवार रहेंगे। भगवान शिव के कैलाश और नंदी पर विराजमान रहने के दौरान अभिषेक करने से साधक को सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है।

योगिनी एकादशी पूजा विधि

योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का विधान है। साथ ही पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करना अधिक शुभ होता है। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद उनकी विधि अनुसार पूजा करे और योगिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। बाद में विष्णु जी की आरती करें। इस दिन आप जरूरतमंद लोगों को भोजन व दान दक्षिणा भी दे सकती हैं, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।

पूजा के दौरान इन मंत्रों का करें जप

विष्णु गायत्री मंत्र

ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्।।

विष्णु मंगल मंत्र

मङ्गलम् भगवान विष्णुः, मङ्गलम् गरुणध्वजः। मङ्गलम् पुण्डरी काक्षः, मङ्गलाय तनो हरिः।।

योगिनी एकादशी व्रत के नियम

योगिनी एकादशी व्रत के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत नहीं रखने वालों को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन बाल, नाखून, और दाढ़ी कटवाने की भूल न करें। योगिनी एकादशी के दिन ब्राह्मणों को कुछ दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण करने के बाद अन्न का दान करना शुभ माना गया है।

आषाढ़ अमावस्या के दिन इस विधि से करें पितरों का तर्पण, जानें शुभ मुहूर्त

23 जून से आषाढ़ मास शुरू हो गया है। यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। आषाढ़ माह में कई व्रत और त्योहार आते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आषाढ़ चौथा महीना है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी आषाढ़ का महीना बहुत खास माना जाता है।

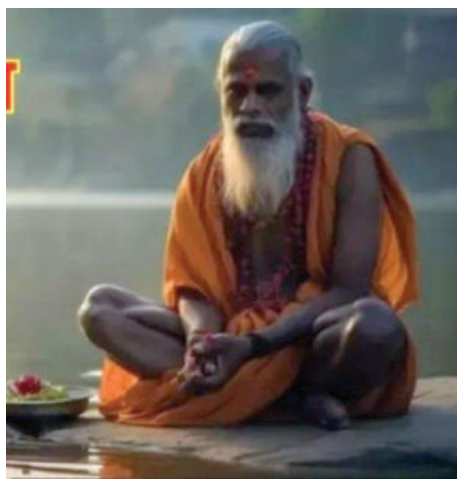

आषाढ़ महीने में आने वाली तिथि भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के कार्य किए जा सकते हैं। इन कार्यों को करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। साथ ही खुशहाली आती है। आइए, जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी।

आषाढ़ अमावस्या तिथि 2024

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 5 जुलाई को सुबह 4:57 बजे शुरू होगी। यह तिथि 6 जुलाई को सुबह 4 बजकर 26 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में आषाढ़ अमावस्या 5 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी।

पितरों की आत्मा की शांति के लिए हर महीने की अमावस्या तिथि पर दान और तर्पण करना शुभ होता है। ऐसे में इस दिन यह कार्य जरूर करने चाहिए।

पितरों के तर्पण की विधि

* पितरों को तर्पण देने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय का होता है।
* सूर्योदय के समय स्नान-ध्यान करने के बाद पितरों को तर्पण करना चाहिए।
* पितरों को तर्पण देने के लिए सफेद फूल, काले तिल और कुशा का उपयोग करें।
* पितरों का तर्पण दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके करना चाहिए।
* तर्पण के दौरान पितरों का ध्यान करना चाहिए।

कहा जाता है कि अमावस्या तिथि पर कौवा, कुत्ते या गाय को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। इसके साथ ही आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल या बरगद के पेड़ पर जल अर्पित करें। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है।

दुर्लभ संयोग में 22 जुलाई से शुरू होगा सावन का महीना, दिन होंगे 29 और पड़ेंगे 5 सोमवार

पंचांगीय गणना के अनुसार इस बार 22 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। श्रावण की शुरुआत सोमवार के दिन होगी तथा समापन पर भी सोमवार का दिन रहेगा। एक माह में पांच सोमवार का विशेष अनुक्रम बन रहा है। हालांकि तिथि की घट बढ़ के कारण श्रावण 30 के बजाय 29 दिन का रहेगा। विशेष यह है कि श्रावण की शुरुआत श्रवण नक्षत्र में होगी, जो जनमानस के लिए शुभ व कल्याणकारी मानी जा रही है।

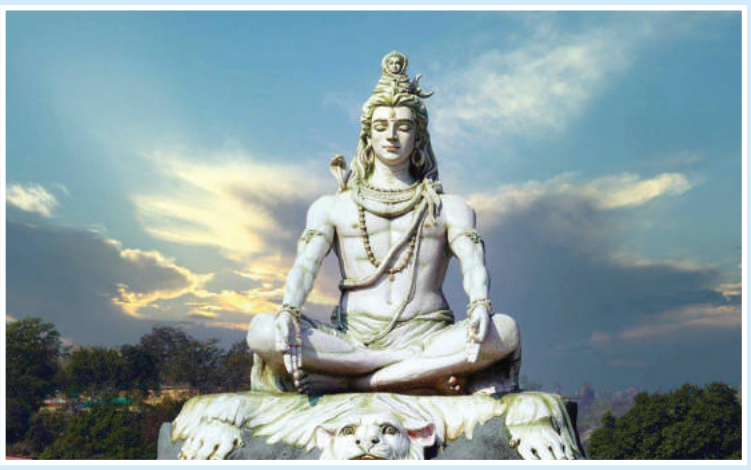

श्रावण मास में दो तिथियों का क्षय

ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डब्बावाला ने बताया 22 जुलाई को सोमवार के दिन, श्रवण नक्षत्र, प्रीति योग तथा मकर राशि के चंद्रमा की साक्षी में श्रावण मास की शुरुआत होगी। इस बार श्रावण मास में दो तिथियों का क्षय है, इस दृष्टि से यह माह 29 दिन का रहेगा। श्रावण की शुरुआत सोमवार के दिन होगी तथा समापन पर भी सोमवार रहेगा।

कुल पांच सोमवार आएंगे

इस माह में कुल पांच सोमवार आएंगे। धर्म आराधना की दृष्टि से पंचांग की यह स्थितियां शुभ हैं। शिव आराधना के लिए विशेष माह श्रावण मास में सोमवार का विशेष महत्व है, क्योंकि श्रावण का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है और भगवान शिव का दिन भी सोमवार बताया गया है। खासकर श्रवण नक्षत्र में सावन का आरंभ श्रवण नक्षत्र में सोमवार का दिन विशेष रूप से फल देने वाला बताया जाता है।

अमृत सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि रवि पुष्य जैसे खास योग

भारतीय ज्योतिष शास्त्र में योग संयोग का विशेष महत्व बताया जाता है। इस बार श्रावण मास में पांच सर्वार्थ सिद्धि योग एक अमृत सिद्धि योग और रवि पुष्य का विशेष संयोग रहेगा। ऐसी मान्यता है कि इन योगों में भगवान शिव की विशेष आराधना कार्य की सिद्धि के साथ-साथ मनोवांछित फल प्रदान करती है। यही नहीं इन योगों के दौरान विशेष कार्य भी साधे जा सकते हैं।

श्रावण में अच्छी बारिश होगी

काल की गणना तथा ऋतु चक्र की मान्यता से श्रावण माह में अच्छी बारिश के योग बनेंगे। संपूर्ण विश्व में इस माह के दौरान अलग-अलग प्रकार से वर्षा की दृष्टि का अनुपात संतुलित अवस्था में कहीं-कहीं दिखाई देगा। इस माह वर्षा की स्थिति श्रेष्ठ होगी।

तेजपत्ता करेगा आपकी हर इच्छा पूरी, बस कर लीजिए ये काम

आमतौर पर सभी घरों में तेजपत्ते का प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है. तेजपत्ता भोजन में स्वाद और सुगंध बढ़ाने का काम करता है । इसी के साथ तेजपत्ता में कई गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए आयुर्वेद में औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है।

वहीं ज्योतिष में तेजपत्ते से जुड़े ऐसे चमत्कारी उपायों के बारे में बताया गया है,जो बेहद लाभकारी है। गुणों से भरपूर तेजपत्ता आपकी कई समस्याओं को भी दूर करने की क्षमता रखता है। आइये जानते हैं तेजपत्ते के उपायों से कौन सी समस्या होती है दूर।

धनलाभ के लिए तेजपत्ता के उपाय

धन संबंधी समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी तेजपत्ते का यह उपाय कारगर माना जाता है। यदि खूब मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी बनी रहती है या पैसा टिकता नहीं है तो आप शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के चरणों में तेजपत्ते की पत्तियां अर्पित करें। फिर इनमें से कुछ पत्तियों को उठाकर अपने पर्स और तिजोरी आदि में रखें।

नकारात्मकता दूर करने के लिए तेजपत्ता के उपाय

कई घरों में धन का कोई अभाव नहीं रहता

फिर भी कलह-क्लेश जैसे माहौल बने रहते हैं। आपसी मतभेद और लड़ाई-झगड़े होते रहते हैं। इसका एक कारण घर पर मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। तेजपत्ता के उपाय से नकारात्मक ऊर्जा को दूर किया जा सकता है। इसके लिए शनिवार के दिन पांच तेजपत्ता को पांच काली मिर्च के साथ जला दें और पूरे घर पर इसके धुएं को फैला दें। ऐसा आप प्रत्येक शनिवार के दिन करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है।

बुरे सपने या अज्ञात भय के लिए तेजपत्ते का उपाय

अगर आपको अज्ञात भय सताता है या फिर अक्सर नींद में बुरे और डरावने सपने आते हैं तो आप सोते समय सिरहाने तेजपत्ता रखें। आप अपने तकिए के नीचे भी तेजपत्ते की कुछ पत्तियां रख सकते हैं। इस उपाय से बुरे सपने नहीं आएंगे।

क्या आपकी रसोई में भी रहती है छिपकली, जानें ये अच्छा है या बुरा

छिपकली को देवी लक्ष्मी का दूत माना जाता है, जो समृद्धि और धन की देवी हैं। घर में छिपकली का दिखना शुभ संकेत माना जाता है, जो आर्थिक लाभ और सफलता का प्रतीक है। इसे ज्ञान और आत्मज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि छिपकली अक्सर ऊंचे स्थानों पर रहती है, जो आध्यात्मिक ऊंचाई का प्रतीक है। लेकिन, कुछ मान्यताओं के अनुसार, छिपकली नकारात्मकता और बुरी आत्माओं का प्रतीक भी हो सकती है। खासकर अगर यह घर में मृत पाई जाए तो इसे अशुभ माना जाता है। सौभाग्य, बुद्धि, और सुरक्षा का प्रतीक मानी जाने वाली छिपकली का आपके घर में दिखना कब शुभ और कब अशुभ होता है आइए जानते हैं।

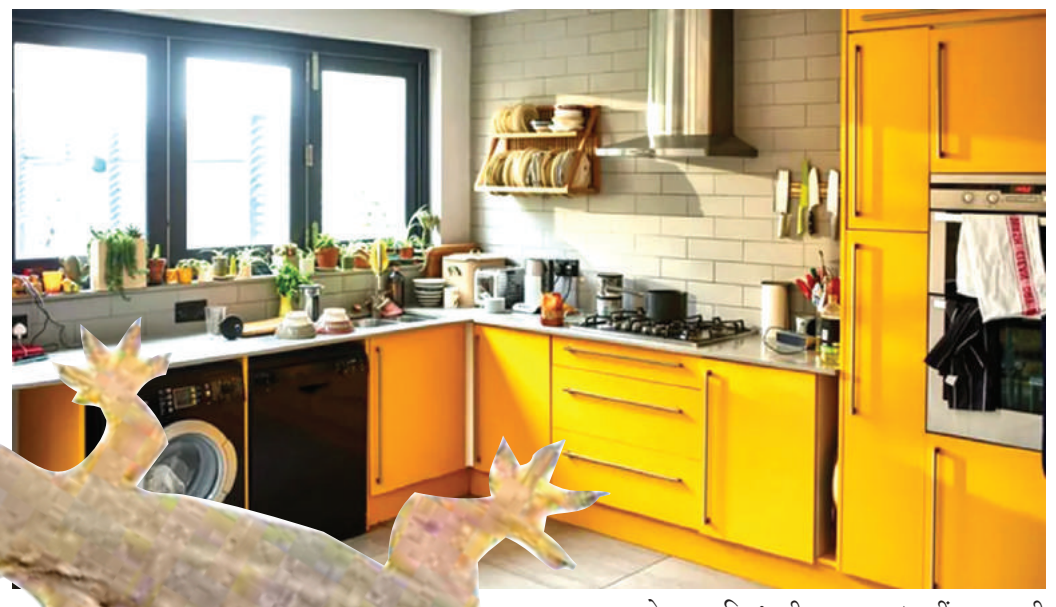

छिपकली के शुभ-अशुभ संकेत

छिपकली किचन या घर के मंदिर में नजर आए तो यह और भी शुभ माना जाता है। किचन में छिपकली का दिखना रसोई घर में छिपकली का दिखना अच्छा ही माना जाता है। ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, अच्छा ही होगा और आपको धन लाभ के योग भी बनेंगे।

अगर छिपकली रोज़ मंदिर में नजर आए तो इसका अर्थ होता है कि आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत दे रहा है।

अगर आपको काली चिपकली नजर आती है तो इसे अलक्ष्मी का संकेत माना जाता है। अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की बहन देवी लक्ष्मी की बड़ी बहन है और इनके आगमन से जीवन में आर्थिक हानि होती है।

अगर आपको शुक्रवार के दिन अचानक से घर के मंदिर में छिपकली दिख जाए तो इसे शुभ माना जाता है।

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, मंदिर में मरी हुई छिपकली दिखे तो यह अशुभ होता है। लेकिन, अगर आपको सुबह-सुबह ही छिपकली नजर आ जाए तो यह उन्नति और लाभ का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के फर्श पर चलती हुई छिपकली देखने का अर्थ होता है कि आपको जल्द ही आर्थिक लाभ हो सकता है।

वहीं अगर पूजा करने के दौरान छिपकली आपके ऊपर चढ़ जाएं या शरीर पर छिपकली गिर जाए तो माना जाता है कि बहुत जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है।

दीवाली या अन्य किसी बड़े पर्व पर अचानक से घर के मंदिर में छिपकली नजर आ जाए तो इसे शुभ मानते हैं। दीवाली का पर्व देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है और इस दिन अगर आपको उनके प्रतीक के रूप में छिपकली नजर आ जाए तो यह अतिशुभ ही कहलाएगा। वहीं अगर कटी हुई छिपकली या जख्मी छिपकली घर में नजर आए तो ये अशुभ संकेत हो सकता है। इससे घर में कलह और क्लेश बढ़ता है।

घर में छिपकली दिखना शुभ माना जाता है, खासकर मंदिर और किचन में। छिपकली को देवी लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर छिपकली किचन या मंदिर में दिखे, तो यह धन लाभ और शुभ समाचार का संकेत हो सकता है। वहीं, काली छिपकली को अलक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जिससे आर्थिक हानि हो सकती है। शुक्रवार के दिन छिपकली दिखना और भी शुभ होता है। दिवाली पर छिपकली दिखना अतिशुभ माना जाता है।

शुभ लाभ DAILY
खबरें जो सोच बदल दे
हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

कोसी निगल रही है जमीन, उजड़ने लगे सैकड़ों घर

सालाना 50 लाख खर्च के बाद भी विस्थापित हो रहे हैं लोग

पटना (एजेंसियां)।

सात नदियों से घिरे खगड़िया जिले के तीन ऐसे प्रखंड हैं, जहां के लोग नदियों के दंश झेल रहे। इन जगहों पर कटाव के कारण हर वर्ष सैकड़ो परिवार विस्थापित होते हैं, जो अपने घर को छोड़कर खेती-बाड़ी से भी दूर हो जा रहे हैं। दरअसल, खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के 4 पंचायत तेलीहार, डुमरी, बलैठा, इतमादि, पचाठ एवं गोगरी प्रखंड के 2 पंचायत सहरौन और बिरबास सहित चौथम प्रखंड के सिसवा आदि जगहों में हर वर्ष कोसी और बागमती नदी अपना रौद्र रूप धारणधारण करती है। इसके कारण इन इलाकों के उपजाऊ जमीन और लोगों के घर नदी में समा रहे हैं। जो हर वर्ष दर्जनों परिवार को बेघर कर रहा है।

कोसी और बागमती नदी में हो रहे कटाव के कारण प्रत्येक दिन दो से तीन फीट जमीन नदी के आगोश में समा रही है। इस वर्ष भी कोसी नदी किनारे हो रहे कटाव की रफ्तार तेज हो गई है। इसके कारण ग्रामीण डरे सहमे हैं और पलायन करने पर मजबूर हैं। हालांकि बाढ़ प्रमंडल-2 की मानें तो प्रत्येक वर्ष कटावनिरोधक कार्य किया जाता है। इस बार भी कटाव स्थल का चयन कर वहां पर बचाव कर किया जा रहा है।

कोसी और बागमती नदी पर बने बीपी मंडल सेतु (डुमरी पुल) भी इन इलाकों के लिए अभिशाप बना है। यह पुल एक तरफ जहां लोगों के लिए सुख सुविधा का साधन बना है। वहीं ये पुल बेलदौर प्रखंड के तेलीहार, डुमरी, बलैठा, इतमादि एवं गोगरी प्रखंड के सहरौन और बिरबास के लिए प्रत्येक वर्ष मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। बताया जा रहा कि सालों पहले सोनवर्षा घाट के समीप जिंदा बागमती नदी को सील कर उसकी बहाव धारा को बदल दिया गया था। इसके कारण कोसी में पानी का बहाव तीव्र होता गया। जानकारों का कहना है अगर बागमती की प्राकृतिक धारा से छेड़छाड़ नहीं किया जाता तो आज सैकड़ों लोगों के आशियाने नहीं उजड़ते।

विभाग की मानें तो खगड़िया में कोसी नदी और बागवती नदी के कटाव की रोकथाम के लिए प्रत्येक वर्ष करीब 50 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। बावजूद कटाव की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कोसी कटाव के रोकथाम को लेकर हर वर्ष कटाव निरोधात्मक कार्य या फिर फ्लड फाइटिंग के नाम पर सरकारी रकम खर्च करना ढाक के तीन पात साबित हो रहा है। बाढ़ प्रमंडल-2 के जूनियर इंजीनियर मनिकांत पटेल बताते हैं कि कटाव निरोधक कार्य तेजी से किया जा रहा है।

पचाठ, मुनिटोला, गाँधी नगर और इत्मादी में कटाव हो रहा है। जिसपर विभाग नजर बनाए हुए है। इधर जानकारों की माने तो जबतक इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तबतक इन इलाकों के लोग ऐसे ही बेघर होते रहेंगे।

बिहार में एक और पुल धंसा, निशाने पर इस बार लालू यादव की पार्टी

भाजपा ने कह दिया- बख्शेंगे नहीं

पटना (एजेंसियां)।

किशनगंज में एक और पुल धंसने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सीधे राष्ट्रीय जतना दल पर हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि यह पुल राजद के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के फंड से बना था। अब बिहार सरकार इस मामले की जांच करवाएगी कि राजद के तत्कालीन सांसद ने उस वक्त कितना पैसा खाया था। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि किशनगंज में जो पुल धंसा है, उसे राजद के तत्कालीन सांसद दिवंगत तसलीमुद्दीन के फंड से बना था। इस पुल का निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया इसलिए आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अन्य सभी पुल के साथ इस पुल की भी जांच करवाई जाएगी। आखिर तत्कालीन सांसद ने कितना पैसा खाया था। जांच के बाद सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। 2007-2008 में इस पुल का निर्माण हुआ था। जांच में जो दोषी पाए जाएंगे वह बख्शे नहीं जाएंगे।

मामला किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड का है। जहां तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बूंद नदी पर बना पुल का पिलर करीब एक फुट धंस गया है। यह पुल ठाकुरगंज के पथरिया पंचायत स्थित खोशी डांगी गांव में तत्कालीन सांसद मो. तस्लीम उद्दीन के सांसद कोष से 2007-8 में बनाया गया था। लेकिन सोमवार को पानी का दवाब नहीं झेल पाया और पिलर एक से डेढ़ फुट धंस चुका है। स्थानीय पूर्व मुखिया जवाहर सिंह ने बताया कि यह पुल तीन से चार पंचायतों को जोड़ता है। अगर यह पुल धराशायी हो जाता है तो 50 से 60 हजार आबादी प्रभावित होगी।

शेखपुरा में दिनदहाड़े 45 लाख की बैंक डकैती

ग्राहक बनकर घुसे बदमाश, स्टाफ को बंधक बनाकर की लूटपाट

पटना (एजेंसियां)।

शेखपुरा में सोमवार दिनदहाड़े बैंक डकैती हुई है। करीब 10 बदमाश बरबीघा के श्रीकृष्ण चौक स्थित एक्सिस बैंक में घुसे। बैंक के कर्मचारियों को जब तक शक हुआ तब तक बदमाशों ने हथियार निकाल लिया और सभी को बंधक बना लिया। इसके बाद कैश काउंटर और लॉकर में रखे करीब सारे कैश लूट लिया। इतना ही नही बदमाशों ने बैंक के अंदर मौजूद ग्राहकों से भी लूटपाट की। कुल 45 लाख रुपये लूट की बात सामने आ रही है। इधर, घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही

है। पुलिस के अनुसार, बैंक लूट की बात सामने आ रहे हैं। कितनी राशि की लूट हुई है? इसका अब तक पता लगाया जा रहा है। सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की तलाश की जा रही है। बैंक के स्टाफ और मैनेजर से भी जानकारी ली जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शी ने अनुसार, सुबह 10 बजे बैंक खुलने के कुछ देर बाद करीब 10 बदमाश अंदर आए। वह अलग-अलग जगह पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद बदमाशों ने हथियार निकाल लिया और पहले सबके फोन को जब्त कर लिया। इसके बाद लूटपाट करने लगे। बैंक के स्टाफ के साथ बदमाशों ने मारपीट भी की। ग्राहकों से भी बदमाशों ने लूटपाट की।

शादी के लिए कोर्ट नहीं पहुंचने पर सजा

महिला चिकित्सक ने वार्ड पार्षद का गुप्तांग काटा

सारण (एजेंसियां)।

देश-दुनिया में आज डॉक्टर्स डे पर अच्छे संदेशों की भरमार के बीच एक चौंकाने वाली खबर बिहार से सामने आ रही है। बिहार के सारण में एक महिला चिकित्सक ने एक वार्ड पार्षद का गुप्तांग काट लिया। डॉक्टर्स डे पर महिला ने यह इंतकाम लिया है। महिला चिकित्सक का आरोप है कि वार्ड पार्षद उसका प्रेमी है। करीब एक साल से वह शादी का झांसा देकर उसका यौन शोषण कर रहा था। जब उसे लगा कि वह शादी नहीं करेगा, सिर्फ शोषण ही करता रहेगा तो इंतकाम लेने के लिए उसका गुप्तांग काट लिया।

घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि वार्ड पार्षद प्रेमी निजी अस्पताल की महिला चिकित्सक को विगत एक वर्ष से शादी का झांसा देकर कर उसका यौन शौषण कर रहा था। आज इसी बात पर दोनों में विवाद हुआ और इसी गुस्से में महिला चिकित्सक ने अपने प्रेमी वार्ड पार्षद का गुप्तांग काट दिया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल प्रेमी

को आननफानन में रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

घटना के संबंध में पुलिस का कहना है कि मढ़ौरा थाना क्षेत्र मुख्यालय के एक निजी अस्पताल में एक महिला चिकित्सक ने स्थानीय नगर पंचायत के वार्ड पार्षद सह कथित प्रेमी का गुप्तांग सोमवार की दोपहर काट दिया है। जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वार्ड पार्षद को रेफरल अस्पताल पहुंचाया है। जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। हालांकि महिला चिकित्सक ने खुद पुलिस व मीडिया के सामने स्वीकारा है कि उसका प्रेम प्रसंग विगत एक वर्ष से चल रहा था। लेकिन कथित प्रेमी शादी का झांसा देकर हमेशा उसका यौन शोषण करता था। विवाह करने नाम पर हर समय बहाना बनाता था।

सोमवार को अपनी आदत के अनुसार नगर पंचायत का वार्ड पार्षद सह कथित प्रेमी अपनी कथित प्रेमिका के घर पर आया। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और दोनों रोमांटिक मूड में आने लगे। लेकिन महिला लगातार उसपर शादी करने का दवाब बनाते हुए शारीरिक संबंध बनाने से मना कर रही थी। उधर प्रेमी वार्ड पार्षद शादी की बात को टालते हुए उससे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान दोनों के बीच बात बढ़ने लगी और इसी दौरान महिला ने उसके गुप्तांग को चाकू से काटकर कटे हुए भाग को बाथरुम में फ्लैस कर दिया। गुप्तांग कटते ही प्रेमी चीखने चिल्लाने लगा, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी वहां जुट गये और तुरंत स्थानीय थाना को कॉल कर के बुला लिया। आननफानन में पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और दर्द से तड़पते प्रेमी को जल्दी से सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक इलाज कर उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया।

घटना के संबंध में सारण के पुलिस अधीक्षक डॉ कुमार आशीष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रेमी को पटना रेफर कर दिया गया है, जबकि आरोपी प्रेमिका को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।

पुलिस का कहना है कि प्रेमी मढ़ौरा नगर पंचायत के वार्ड संख्या 12 के निर्वाचित पार्षद है, जबकि आरोपी महिला चिकित्सक वैशाली जिले के लालगंज की रहने वाली है। इस संबंध में सिविल सर्जन का कहना है कि आरोपी महिला खुद को चिकित्सक और बीएचएमएस बताती है। वह मढ़ौरा के चीनी मिल के सामने एलबी स्वास्थ्य अरोग्य संस्थान नाम से फर्जी नर्सिंग होम संचालित करती है। पुलिस का कहना है कि फर्जी तरीके से निजी नर्सिंग होम संचालिका के खिलाफ मढ़ौरा रेफरल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने सिविल सर्जन सारण को पत्र लिखकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद फर्जी तरीके से निजी नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा था। अब पुलिस फर्जी नर्सिंग होम की भी जांच करेगी।

दुकान पर बैठे बालू-सीमेंट व्यवसायी पर बाइक सवार बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग

हायर सेंटर रेफर

मधेपुरा (एजेंसियां)।

मधेपुरा के मुरलीगंज नगर पंचायत के रहिका टोला में सोमवार को बाइक सवार बदमाशों ने एक बालू-गिट्टी व्यवसायी को दो गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में इलाज के लिए सहरसा ले जाया गया है। घायल की पहचान भतनी निवासी सिकेंद्र यादव के बेटे अंकेश कुमार उर्फ निकु (30) के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, पिछले छह वर्ष से अंकेश कुमार अपने परिवार के साथ मुरलीगंज नगर पंचायत के रहिका टोला में घर बनाकर रहते हैं। साथ ही वह घर पर ही गिट्टी-बालू की दुकान भी चलाते हैं। सोमवार की सुबह पूजा-पाठ कर अंकेश अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। सुबह करीब नौ बजे अपाचे बाइक पर सवार तीन अज्ञात अपराधी अंकेश के दुकान पर पहुंचे और उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घटना के बाद बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए भाग निकले।

वहीं, गोली की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायल युवक को मुरलीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया।

जहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने गंभीर स्थिति देखते हुए उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज से भी उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक को दो गोली लगी है। एक गोली छाती और दूसरी गोली गर्दन में लगी है।

इधर, घटना की सूचना मिलते ही मुरलीगंज थानाध्यक्ष सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। हालांकि अभी तक घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। मधेपुरा अडझ प्रवेंद्र भारती ने बताया कि मुरलीगंज में एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने की जानकारी मिली है। घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है।

कोचिंग से वापस घर लौट रही छात्रा से छेड़खानी

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर किया पुलिस के हवाले

बेतिया (एजेंसियां)।

बेतिया में कोचिंग से पढ़ाई कर अपने घर लौट रही एक 17 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। घटना जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। जहां से पढ़ाई कर वापस अपने घर जा रही एक छात्रा से छेड़खानी कर रहे एक मनचले को ग्रामीणों ने पकड़ पुलिस को सौंप दिया।

पुलिस ने पीड़ित छात्रा की शिकायत पर मनचले युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पकड़े गए मनचले की पहचान गोपालपुर थाना के गणेशपुर निवासी पीडीएस दुकानदार इरशाद आलम (18) के रूप में हुई है।

पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह कोचिंग से पढ़ाई कर साइकिल से अपने घर जा रही थी। इस बीच रास्ते में युवक ने उससे बदतमीजी की। तरह-तरह की फब्तियां कसीं, जिससे परेशान होकर उसने उसका विरोध किया। विरोध करने पर आरोपी युवक उससे अश्लील हरकत करने लगा। छात्रा लगातार विरोध करती रही, लेकिन वह बाज नहीं आया। छात्रा ने बताया कि मेरे विरोध करने और आरोपी की हरकत देखकर अगल-बगल के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया।

थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि आरोपी को पकड़कर ग्रामीणों द्वारा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वहीं, पीड़िता के आवेदन पर कांड दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने में जुटी हुई है।

तीन साल से गायब रहकर वेतन उठाने वाली शिक्षिका का नियोजन रद्द

4.32 लाख रुपये भी वापस देना पड़ेगा

दरभंगा (एजेंसियां)।

दरभंगा के गौडबोराम प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय तेनुआ की एक शिक्षिका सुप्रीति कुमारी ने बगैर स्कूल गए ही विभाग से वेतन उठाती रही और शिक्षा विभाग इससे अनजान बना रहा। इस बात का खुलासा तब हुआ जब प्रखंड लोजपा अध्यक्ष राजकुमार झा ने आरटीआई के माध्यम से जानकारी लेकर विभाग से इस बात की शिकायत कर डाली। इस के बाद शिक्षा विभाग ने त्वरित कार्यवाई करते हुए तत्काल सम्बंधित नियोजन इकाई से शिक्षिका सुप्रीति कुमारी का नियुक्ति रद्द कर दिय था साथ ही नीलाम वाद पत्र दायर करते हुए वेतन के रूप में प्राप्त की गई 4 लाख 32 हजार 638 रुपये वापस करने का आदेश दिया।

बता दें कि विभागीय जांच में पाया गया की शिक्षिका सुप्रीति कुमारी ने 12 अप्रैल 2021 से स्कूल में अनुपस्थित रहते हुए भी

सरकारी वेतन के लाभ के रूप में 4 लाख 32 हजार 638 रुपये उठाव कर लिए है। उक्त शिक्षिका 12 अप्रैल 2021 से लगातार स्कूल में अनुपस्थित चल रही थी ग्रामीणों इसकी शिकायत कई बार प्रिंसिपल से की थी लेकिन फिर भी शिक्षिका लगातार गायब होकर सरकारी वेतन का लाभ लेती रही। थक हारकर ग्रामीणों के कहने पर लोजपा प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार झा से आईटीआई से शिक्षिका के विषय मे जानकारी जुटाते हुए विभाग से इसकी शिकायत की तब जाकर विभाग ने कार्रवाई की।

इस सम्बंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि यह मामला उनके आने से पहले का है। इस मामले की जांच की गई है और सम्बंधित पंचायत नियोजन इकाई को दो दिनों के भीतर आरोपी शिक्षिका के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक गोपाल अग्रवाल द्वारा श्री शेषसाई इंटरप्राइजेज प्लॉट नंबर. 98/1, को-ऑपरेटिव इंडस्टीयल एस्टेट, गांधी नगर, बालानगर के पास मेडचेल-मल्काजगिरि जिला. हैदराबाद 500037, तेलंगाना स्टेट से मुद्रित तथा प्लॉट नं. ए-23/5 तथा 6, दूसरा माला, ओपीआईई, बालानगर, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना राज्य-500037 से प्रकाशित। आर. एन. आई रजिस्टर्ड नं. TELHIN/2019/78163, फोन नं. 040-29551811. E-mail : dailyshubhlabh@gmail.com